वर्ष: 5 अंक:5 मई, 2025 मूल्य: 60 रु. पृष्ठ : 44

राजस्थान टुडे

RNI No. RAJHIN/2020/11458

"जो कहा वो कर दिखाया"

OPERATION SINDOOR

पहलगाम हमले का जवाब-

अब और नहीं, अब और नहीं....

5

जोधपुर स्थापना दिवस विशेष (12 मई)

अपणायत के लिए ख्यात जोधपुर ने बॉलीवुड को दिए कई स्टार 29

थाली में तहजीब: मारवाड़ का स्वाद, सदियों की साधना

जायकों की जमीन जोधपुर 35

BONE AND JOINT HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE

पश्चिमी राजस्थान में पूरी तरह हड्डी एवं जोड़ रोग उपचार को समर्पित एक मात्र अस्पताल

सूर्यनगरी के 567वें स्थापना दिवस

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

3 shyam Nagar**,** Near Radha Krishna Mandir**,** Pal Link Road**,** Jodhpur **(**Rajasthan**), 342003 ,** India

Phone No**. +91-291-2979315 / +91-9694022500**

Facebook**/**boneandjointhospital | YouTube@boneandjointhospital**2009**

राजस्थान टुडे

आपकी पत्रिका, आपकी बात
www.rajasthantoday.online

RNI No. RAJHIN/2020/11458
वर्ष 5, अंक 5, मई, 2025
(प्रत्येक माह 15 तारीख को प्रकाशित)

प्रधान सम्पादक
दिनेश रामावत

राजनीतिक सम्पादक
सुरेश व्यास

सम्पादक
अजय अस्थाना

प्रबंध सम्पादक
राकेश गांधी

ब्यूरो प्रभारी
जयपुर- बलवंत राज मेहता

रेखाचित्र- राजेंद्र यादव

संपादकीय कार्यालय
बी-4, फोर्थ फ्लोर, एम.आर. हाईट्स
महावीर कॉलोनी, भास्कर सर्किल,
रातानाड़ा, जोधपुर - 342011
व्हाट्सएप नंबर - 9828032424
ई-मेल - rajasthantoday@gmail.com

सभी विवादों का निपटारा जोधपुर की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

• मारवाड़ मीडिया प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक पूनम अस्थाना द्वारा बी-4, फोर्थ फ्लोर, महावीर कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर-342011 से प्रकाशित और डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 01 पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीयल एरिया, रिलायंस वेयर हाउस के पास, मोगरा कलां, जोधपुर-342802 में मुद्रित, संपादक : अजय अस्थाना।

अंदर के पेजों पर

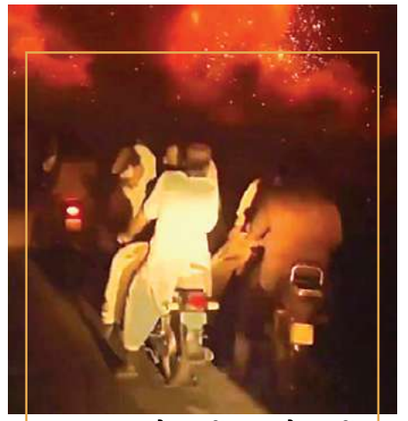

05... अब और नहीं, अब और नहीं

8... पहलगाम त्रासदी में झांकता आइना
14... हंगामा है क्यूं बरपा..!
16... जब दिमाग व अनुभव ट्रांसफर होने लगेंगे
18... मुफ्त योजनाएं – लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा
21... सरहदों की निगहबानी में AI का दमखम
37... शिक्षा नीति- सुनहरा कल, डगर आसान नहीं
40... परिणिता - भारतीय महिलाओं की प्रेरणादायक उड़ान

9... कांग्रेस के कर्णधारों पर संकट

नियमित कालम

12... बात बेलगाम
13... बोल हरि बोल
41... कविता कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ करें
42... ग्रहों की चाल

जोधपुर स्थापना दिवस विशेष

24... आओ, जोधपुर को और समृद्ध व गौरवशाली बनाएं
25... 'जयपुर फुट' से मिला जीने का हौसला
27... राष्ट्रीय संस्थानों से बनी वैश्विक पहचान
29... अपणायत के लिए ख्यात जोधपुर ने बॉलीवुड को दिए कई स्टार

राजस्थान टुडे में प्रकाशित आलेख लेखकों की राय है। इसे राजस्थान टुडे की राय नहीं समझा जाए। राजस्थान टुडे के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी भावना किसी वर्ग या व्यक्ति को आहत करना नहीं है। विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व राजस्थान टुडे का नहीं होगा।

मोदी ने जो कहा, वो कर दिखाया

दिनेश रामावत
प्रधान सम्पादक

आखिर मंगलवार की देर रात भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चला कर दिखा भी दिया। रात एक बजे बाद शुरू हुए इस अभियान के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर-ए-मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर समेत आतंकियों के नौ ठिकाने ध्वस्त करते हुए भारत ने जता दिया कि बहुत जल्द आतंकियों का नामो निशां मिटा दिया जाएगा।

पहलगाम में पिछले माह अंत में हुए आतंकी हमले और पाक आतंकियों के नापाक मंसूबों को देखते हुए आखिर भारत कब तक चुप बैठता? देश में हर तरफ से आतंकियों के खात्मे की आवाज उठ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों एक सभा में कह दिया था कि पहलगाम हमले के दोषियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा, जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। इसके तुरंत बाद उन्होंने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड देते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई का समय, किस्म और आकार सेनाएं ही तय करेगी, देश को हमारी सेनाओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो कहा, वो आखिर मंगलवार की देर रात भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चला कर दिखा भी दिया। रात एक बजे बाद शुरू हुए इस अभियान के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर-ए-मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर समेत आतंकियों के नौ ठिकाने ध्वस्त करते हुए भारत ने जता दिया कि बहुत जल्द आतंकियों का नामो निशां मिटा दिया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्य के चयन और क्रियान्वयन के तरीके में काफी संयम दिखाया है। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की बारीकी से निगरानी की।

हैरानी की बात तो ये थी कि गृह मंत्रालय ने बुधवार रात को 'मॉक ड्रिल' का ऐलान कर रखा है, और उधर पाकिस्तानी नेता इस 'मॉक ड्रिल' का मजाक उड़ाने में व्यस्त थे। किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि भारतीय सेना इस 'मॉक ड्रिल' के पहले वाली रात क्या करने वाली है।

उल्लेखनीय है धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर लौटता अप्रैल एक ऐसा नारकीय दाग लगा गया था कि जिसके बारे में कल्पना करते ही हर कोई सहम जाता है। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन सीजन के पीक पर पहुंचने से पहले ही देश के दुश्मन आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 लोगों को चुन-चुन कर मौत की नींद सुला दिया। इस हमले में सिर्फ पुरुषों की हत्या की गई। महिलाओं और बच्चों के दिलो-दिमाग में जिंदगी भर न भूल सकने वाला मंजर रह गया। मानवता की आवाज उनकी चीखों में कहीं खो गई, लेकिन कथित तौर पर नाम, जाति और धर्म पूछकर की गई सैलानियों की टार्गेट किलिंग सर्वधर्म-समभाव, समरसता और अनेकता में एकता जैसी खासियतों के कारण दुनिया भर में अलग ही पहचान रखने वाले हिन्दुस्तान की आत्मा और आपसी सद्भावना पर एक ऐसा असहनीय हमला था, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। हमले के लिए शुरुआती तौर से ही दोषी माना जा रहा हमारा पड़ोसी बेशर्मी से भले ही हमले में उसका हाथ होने से इनकार करे, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह पाकिस्तान हर बार आतंकियों का पनाहगार-मददगार बनकर दुनिया के सामने आता रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने खुद माना है कि वे अमेरिका व यूरोपीय देशों से मदद के लालच में आतंकी संगठनों की मदद का गंदा काम करते रहे हैं। पहलगाम पर वीभत्स आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के मंत्री की स्वीकारोक्ति भले ही आज हुई, लेकिन भारत कई बरसों से पाकिस्तान की नापाक हरकतों को संयुक्त राष्ट्र व दुनिया के अन्य मुल्कों के सामने प्रामाणिकता के साथ रखता रहा है। यही कारण है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान अलग-थलग पड़ा हुआ है।

इस बार हमारी कवर स्टोरी में 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम हमले के हर पहलू को बारीकी से समझाने की कोशिश की है। सद्भावना पर असहनीय हमले की बात के साथ हम इस बार सद्भावना, अपनी अपणायत और मीठी बोली के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध जोधपुर के स्थापना दिवस पर भी विशेष सामग्री दे रहे हैं। जोधपुर का खानपान ही नहीं, जोधपुर की सूरत-सीरत और यहां के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती स्टोरीज, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। हर की तरह मई के अंक को भी संग्रहणीय बनाने का प्रयास किया गया है। आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहेगा।

-शुभकामनाओं के साथ

पहलगाम हमले का जवाब- OPERATION SINDOOR

अब और नहीं, अब और नहीं....

सुरेश व्यास वरिष्ठ पत्रकार एवं रक्षा विशेषज्ञ

धारा 370 हटने के बाद 'आजाद सांस' ले रहे धरती के स्वर्ग जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की दोपहर हुए वीभत्स आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में चरम पर पहुंचे तनाव और हिंदुस्तान भर के लोगों में गुस्से के उबाल के बीच भारत ने आखिर बदले की ओर एक कदम बढ़ा ही लिया। बर्बर ढंग से 26 महिलाओं का उनके व बच्चों के सामने सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों पर भारत का गुस्सा कहर बनकर टूटा और हमले के 15 दिन बाद ही सीमा पार स्थित नौ ठिकानों पर एक साथ मिसाइल अटैक कर आतंकियों के ठिकाने नैस्तनाबूद कर दिए गए। भारतीय वायुसेना के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार किए बिना प्रक्षेपास्त्रों के जरिए ऐसा धावा बोला कि पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भनक तक नहीं लग सकी। भारत ने भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वाले हमले का जवाब भी 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए ही दिया।

6 और 7 मई की दरम्यानी रात एक बजकर 5 मिनट से एक बजकर 30 मिनट तक की गई एयर स्ट्राइक की गूंज न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके), बल्कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत के बहावलपुर तक सुनाई दी। स्ट्राइक के लगभग नौ घंटे बाद भारत ने सम्भवतः 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पहली बार हुई भारतीय सशस्त्र बलों की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो जांबाज महिला अधिकारियों को सामने कर दुनिया को एक खास संदेश भी दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ भारतीय थल सेना की कर्नल सफिया कुरेशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान स्थित आतंकियों के नौ ठिकाने बर्बाद किए गए, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया जाता था और अलग- अलग जगहों के लॉन्च पैड से आतंकियों को भारत में दाखिल करवाया जाता था।

विदेश सचिव मिस्त्र कहते हैं कि भारत ने पहलगाम की आतंकी घटना के बाद ऐसा करके अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। घटना के बाद पाकिस्तान ने अनर्गल बयानबाजी और आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि उसे आतंकियों को नियंत्रित करने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। भारत को लगातार ऐसे और आतंकी हमलों की खुफिया जानकारी मिल रही थी। पाकिस्तान की अकर्मण्यता और निष्क्रियता को देखते हुए भारत को सम्भावित आतंकी हमलों को टालने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ा।

संसद और मुम्बई पर आतंकी हमलों से लेकर ऊरी, पुलवामा और पहलगाम के आतंकी हमलों का उल्लेख करते हुए भारत की ओर से कहा गया कि अब तक पाकिस्तान पोषित आतंक 300 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान ले चुका है और इन हमलों में 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान आतंकियों की शरणस्थली है, यह दुनिया के सामने कई बार साबित हो चुका है। पहलगाम में जिस बर्बर तरीके से निर्दोष लोगों को उनके परिजनों के सामने सिर में गोलियां मारी गई, यह दर्शाता है कि पाकिस्तान कैसे कश्मीर में सामान्य हो रहे हालात को पचा नहीं पा रहा। लश्कर-ए-तैयब्बा और हिज्बुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) जैसे संगठनों का नकाब पहन कर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसका जवाब दिया जाना जरूरी है।

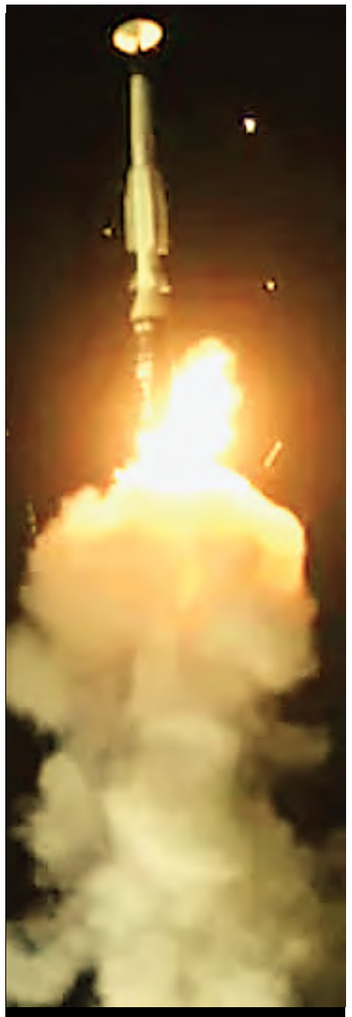

ये तो केवल झांकी है...

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक तो केवल झांकी है। इसमें पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया और न ही किसी नागरिक को मारा गया है। भारत की एयर स्ट्राइक पूर्णतः पेशेवराना ढंग से अंजाम दी गई। पाकिस्तान हालांकि इससे बौखलाया हुआ है और पुराने वीडियो शेयर करके भारत को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन नहीं लगता कि वह बदले में किसी भारतीय सैन्य ठिकाने की तरफ आंख उठाएगा, कारण कि वह जानता है कि इसका नतीजा युद्धक बर्बादी हो सकता है और वह फिलहाल उसे झेलने की स्थिति में है नहीं।

पूरी घेराबंदी के बाद एक्शन

रक्षा विशेषज्ञ कर्नल मनीष ओझा (सेवानिवृत्त) का मानना है कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान की पूरी कूटनीतिक घेराबंदी के बाद ही लिया है। हमले के तुरंत बाद जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आया और भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अमेरिकी सेक्रेट्री ऑफ स्टेट रूबियो से बात हुई, उसे देखकर लगता है कि भारत ने न सिर्फ अमेरिका, बल्कि अन्य देशों को भी इस कार्रवाई से पहले विश्वास में लेने की कोशिश की होगी। हाल ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के महानिदेशक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाना भी इंगित करता है कि अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान को ज्यादा आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में है। इसके अलावा भारत ने देश के सामने एयर स्ट्राइक का ब्यौरा रखने से पहले कई इस्लामिक देशों को भी जानकारी दे दी।

एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत के लोगों में गुस्सा था, उसे देखते हुए सरकार हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी और मौका भांपकर ही पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है और यहां तक कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी पाकिस्तान की हरकतों को पहचान चुके हैं। इस अधिकारी का कहना था कि भारत के पास दो या तीन विकल्प ही थे। पहला विकल्प एयर स्ट्राइक जैसा कदम था और दूसरा विकल्प दो-तीन महीनों का इंतजार, जब घाटियों में बर्फ जमने लगती। सर्दियों के मौसम में पाकिस्तान के लिए चीन जैसे देश की मदद लेना भी मुफीद नहीं होता। ऐसे में भारत ने इंतजार की बजाए पहले विकल्प को चुना जरूर है, लेकिन वह हर किसी स्थिति का सामना करने के लिए अब भी तैयार है।

सियासी पहल पर ध्रुवीकरण का मुल्लमा

फिर क्या कारण रहा कि इतना बड़ा आतंकी हमला पहलगाम में हो गया? इस पर कश्मीर मामलों पर नजदीक से नजर रखने वाले पत्रकार आनंद मणि त्रिपाठी कहते हैं कि सरकार ने धारा 370 हटाने का राजनीतिक फैसला तो कर लिया और इसके आधार पर कई बड़े दावे भी लगातार किए जाते रहे, लेकिन सरकार की राजनीतिक पहल में ध्रुवीकरण ज्यादा रहा। भाजपा के नेता लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं, जिससे मुस्लिम आबादी में अलगाव पैदा होता है और हिन्दू आबादी उत्तेजित। उनका कहना है कि असल में आतंकी भी यही चाहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम एकता को निशाने पर लिया जाए। इसी को आतंकियों ने जिहाद का सहारा बना रखा है। पहलगाम हमले में भी यही दृष्टिगोचर होता है। हालांकि इस बार स्थानीय कश्मीरियों से आतंकियों को वह समर्थन नहीं मिल रहा और साम्प्रदायिक तरीके से की गई हत्याओं से इनमें भी रोष है।

हर पहलू पर नजर जरूरी... बहरहाल, पहलगाम हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। आम लोग भी मान चुके हैं कि हमले का रिमोट पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों में था, लेकिन निशाना सैलानियों को ही क्यों बनाया गया, यह पहेली सुलझना आसान नहीं है। भले ही हम मान लें कि कश्मीर और सीमा पार सक्रिय आतंकियों के बीच अब टैरर का हमास मॉडल पहुंच गया है। आपको याद दिला दें कि इस्रायल और हमास की जंग के बीच साल 2023 में पहली बार हमास ने ही इस्रायल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में आम लोगों और पर्यटकों को निशाना बनाया था, ताकि आम लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके।

क्यों हुआ पहलगाम हमला

कश्मीर से धारा 370 हटने और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा स्थगित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से सरकार लगातार दावे कर रही थी कश्मीर से दहशतगर्दी को खत्म कर दिया गया है। पिछले ही साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में कहा था कि अब तो कश्मीर के लोग आजादी से सांस ले रहे हैं। पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों का काम धंधा भी फलने-फूलने लगा है। सरकार ने कितनी ही बार संसद में दिए गए जवाबों में भी दावा किया कि आंतकी घटनाएं लगभग खत्म प्रायः हो गई है और लोग बेखौफ होकर पर्यटन के लिए कश्मीर आ-जा रहे हैं। पर्यटकों की संख्या पिछले दो साल में ही डेढ़ करोड़ से बढ़कर इस साल अब तक ढाई करोड़ के करीब पहुंच जाने के आंकड़ों के पुट के साथ ये दावे बैसरन की घटना के दो दिन पहले तक होते रहे, तो सवाल उठता है कि ये हमला कैसे हो गया? क्या सरकार ने मान लिया था कि अब कोई आतंकी बंदूक चलाने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगा? यदि ऐसा नहीं था तो कश्मीर का स्विटजरलैंड कहे जाने वाले बैसरन में सुरक्षा व्यवस्था को क्यों भुला दिया गया? घटना के बाद सर्वदलीय बैठक में भी यह सवाल उठा और सरकार ने भी माना कि कहीं न कहीं चूक तो रही है, लेकिन टार्गेट किलिंग जैसी इस घटना ने इसे और भी अहम बना दिया। कुछ पर्यटकों के दावे के आधार पर कहा गया कि आंतकियों ने धर्म और जाति पूछकर लोगों को निशाना बनाया। सिर्फ पुरुषों को कत्ल किया गया। वह भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका के उप राष्ट्रपति जे.डी. वैंस भारत की यात्रा पर थे, ताकि वैश्विक स्तर पर दब सा गया कश्मीर मुद्दा फिर दुनिया में प्रमुखता से गिना जा सके।

अतिआत्मविश्वास का नतीजा

बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे आका निर्देशित कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज और आतंकी संगठनों के प्लान के हिसाब से पहलगाम हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन कई विशेषज्ञ मोदी सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जरूर आधारभूत विकास में तेजी आई है। अनिश्चितता के बादल छंटने लगे। पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन आतंकी घटनाएं खत्म होने के मामले में सरकार अतिआत्मविश्वास में ही रही और छिटपुट घटनाएं होती रही और सरकार कहती रही कि अब हालात सामान्य है। इससे देश के अन्य हिस्सों से लोग सैर सपाटे के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भी, लेकिन सुरक्षा बलों के बेहतरीन इस्तेमाल पर जैसे अतिआत्मविश्वास की गर्द चढ़ती रही और आतंकियों ने मौके का फायदा उठा लिया।

अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमला क्यों हुआ और क्या इसे सुरक्षा में चूक माना जाए। कश्मीर मामलों की जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन अचम्भा जताती है कि पहली बार उन्होंने देखा-सुना कि पहलगाम के प्रमुख पर्यटन स्थल के आस-पास सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं थे। वे इस बात पर भी संदेह खड़ा करती हैं कि देरी से पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने कुछ घंटे बाद ही हमलावर आतंकियों के नाम और स्केच जारी कर दिए। वे कहती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने कभी इस इलाके से आतंक खत्म होने की बात नहीं की। वे हालात को नियंत्रण में ही बताते रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से यह ज्यादा प्रचारित हुआ कि अब कश्मीर से आतंक पूरी तरह खत्म हो चुका है। जबकि हकीकत है कि कश्मीर में नजर आ रही शांति सुरक्षा बलों के नियंत्रण के कारण ही नजर आ रही थी।

ये आतंकी ठिकाने हुए ध्वस्त

1. **बहावलपुरः** अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर, जहां है जैश-ए-महुम्मद का मुख्यालय
2. **मुरीदकेः** साम्बा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तैयबा का शिविर, जहां से मुम्बई हमले के आतंकी पहुंचे थे
3. **गुलपुरः** नियंत्रण रेखा पर पुंछ-राजौरी से 35 किमी दूर ठिकाना, जहां से पिछले साल तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाया गया
4. **सवाई नालाः** पाक अधिकृत कश्मीर के पास तंगधार सेक्टर से करीब 30 किमी दूर लश्कर का ठिकाना, जहां से पहगाम हमले के आतंकी आए थे
5. **बिलालः** लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी लॉन्च पैड
6. **कोटलीः** राजौरी के पास नियंत्रण रेखा से करीब 15 किमी दूर लश्कर के कैम्प में करीब 50 आतंकी जमा थे
7. **बरनालाः** राजौरी के पास नियंत्रण रेखा से दस किमी दूर आतंकी कैम्प
8. **सरजालः** सांबा-कठुआ के पास अन्तरराष्ट्रीय सीमा से करीब 8 किमी दूर जैश-ए-मुहम्मद का आतंकी शिविर
9. **महमूनाः** सियालकोट के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी दूर हिज्बुल का प्रशिक्षण शिविर

जारी है कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक

वैसे तो पहलगाम के नामी पर्यटक स्थल बैसरन घाटी में कत्ले आम के तुरंत बाद मोदी सरकार हरकत में आ गई थी और खुद मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ कर दिल्ली लौट आए। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान पर 'कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक' कर दी और पाकिस्तान से राजनयिक व व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ने के साथ पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने के साथ 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने जैसे कदम उठा लिए गए। पहलगाम हमले के बाद बिहार में अपनी पहली ही आमसभा में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस घटना का ऐसा प्रतिशोध लिया जाएगा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं होगी। इसके बाद से लोगों के मन में सवाल पर सवाल उमड़ रहे थे कि आगे होगा क्या? कहां होगा, कैसे होगा?

भारत का तगड़ा सन्देश

भारत ने पहले तो 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वालों के घर में घुसकर उन्हें मारा। फिर इसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया और अब भारतीय सेना की दो जांबाज महिला अधिकारियों को प्रेस ब्रीफिंग के लिए भेजा गया। आज के समय में प्रतीक अधिक मायने रखते हैं। आप क्या कहते हैं और क्या दिखाते हैं, इससे आपने जो करते हैं उसका उद्देश्य और मजबूत होता है।

सोफिया कुरैशी - 2016 में पुणे में डेढ़ दर्जन देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास 'एक्सरसाइज फोर्स 18' में 40 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करके सुर्ख़ियों में आई थीं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के दौरान जब 1999 कारगिल युद्ध में वो सेना में शामिल हुई थीं, तब उनकी उम्र महज 17 वर्ष थी। उनके दादा भी भारतीय सेना में रहे हैं। पति मेकेनाइज्ड इन्फेंट्री में सैन्य अधिकारी हैं।

व्योमिका - नाम से ही समझ जाइए। बचपन से सपना था उड़ने का। माता-पिता ने नाम भी 'व्योम' से रखा। एनसीसी में शामिल होने के बाद इंजीनियरिंग की और भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट बनीं। सोफिया कुरैशी के उलट व्योमिका सिंह सेना में शामिल होने वाली पहली सदस्य हैं अपने परिवार की। 2500+ फ़्लाइंग अवर्स का अनुभव रखने वाली व्योमिका 2020 में अरुणाचल प्रदेश के कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में राहत-बचाव अभियान चला चुकी हैं। 21,650 फ़ीट ऊपर स्थित मणिरंग शिखर पर पर्वतारोहण कर चुकी हैं।

पहलगाम त्रासदी में झांकता आइना

धर्म की सियासत : आस्था या आग?

धर्म आज सियासत का हथियार बन गया है। पहलगाम की घटना इसका सबसे दुःखद उदाहरण है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हमारी राजनीति इससे अलग है? चुनावों में मुस्लिम-महिलाओं का 'हिजाब', दलितों के 'मंदिर प्रवेश' या किसी संप्रदाय का 'राष्ट्रभक्ति प्रमाणपत्र' क्या यह सब धर्म का उपयोग नहीं है? राजनीति ने धर्म को अब 'जनसंख्या संतुलन', 'मजहबी कट्टरता' और 'वोट बैंक' की श्रेणी में बांट दिया है। नतीजा यह है कि समाज में विश्वास की जगह संदेह, और भाईचारे की जगह भय ने ले ली है।

विभाजन के साये में राष्ट्रीय एकता

पहलगाम की घटना से एक ओर जहां राष्ट्रीय एकता की नई मिसाल पेश हुई, वहीं यह भी उजागर हुआ कि भारत में आंतरिक विभाजन कितना गहरा है। यह विडंबना है कि आतंकवाद से लड़ने का सपना लिए हम एकजुट होते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में धर्म के आधार पर एक-दूसरे से कटते जाते हैं।

विवेक श्रीवास्तव ✍ लेखक

कश्मीर, जिसे मुग़ल बादशाह जहाँगीर ने 'जन्नत' कहा था, एक बार फिर दहशतगर्दी की साज़िश का शिकार बना। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में केवल गोलियाँ नहीं चलीं, एक समाज के रूप में हमारी सोच भी तार-तार हुई। आतंकियों ने कथित तौर पर धर्म पूछकर निर्ममता से लोगों की जान ले ली। वहीं, एक कश्मीरी नौजवान आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों को बचाने की कोशिश की और वह शहीद हो गया।

"तेरा मज़हब है क्या, तेरा नाम क्या है,
किसी ने पूछा और तू क़त्ल हो गया।
इंसानियत बस देखती रह गई,
किसी गली के मोड़ पर, कहीं मर गई।"

भारत, जिसकी रूह उसकी विविधता में बसती है, आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ धर्म, जाति और क्षेत्र की पहचान, इंसानियत की जगह लेने लगी है। पहलगाम की वादियों में बर्फ़ की सर्द हवाओं के बीच, एक ख़ून की गर्म बूंद ने गवाही दी कि दुश्मन अब सिर्फ़ सरहद पार से नहीं आता, वह हमारे पूर्वग्रहों, हमारी चुप्पियों और हमारे भेदभाव में भी है।

कश्मीर, जिसे मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 'जन्नत' कहा था, एक बार फिर दहशतगर्दी की साजिश का शिकार बना। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में केवल गोलियाँ नहीं चलीं, एक समाज के रूप में हमारी सोच भी तार-तार हुई। आतंकियों ने कथित तौर पर धर्म पूछकर निर्ममता से लोगों की जान ले ली। वहीं, एक कश्मीरी नौजवान आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों को बचाने की कोशिश की और वह शहीद हो गया।

आदिल की कुर्बानी ने न केवल एक बहादुर कश्मीरी की तस्वीर पेश की, बल्कि यह भी साबित किया कि घाटी का दिल अब भी भारत के साथ धड़कता है। पहली बार स्थानीय जनता खुलकर आतंक के ख़िलाफ़ खड़ी नज़र आई। यह बदलाव की आहट है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आहट गूंज में बदलेगी या सत्ता की राजनीति इसे दबा देगी?

लोकतंत्र की रगों में जातिवाद का ज़हर... भारत में जाति एक ऐसी परछाईं है जो हर सामाजिक और राजनीतिक निर्णय पर गिरती है। संविधान के मूल्यों की कसौटी पर जब हम समाज को परखते हैं तो दिखता है कि योग्यता अब केवल एक छलावा है। असली मुद्दा है जातीय पहचान। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बहस हो या विश्वविद्यालयों में दाख़िले की प्रक्रिया, हर जगह पहचान पहले, पात्रता बाद में देखी जाती है। यह सोच केवल नीति-निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि आज सत्ता के गलियारों में नियुक्तियों से लेकर अफ़सरशाही के निर्णयों तक में 'जातिगत समीकरण' प्राथमिकता बन चुके हैं।

सत्ता का जातिगत गठबंधन... आज जब आप किसी भी प्रभावशाली मंत्री या सांसद के दफ़्तर में झांकते हैं, तो उनके निजी स्टाफ़ (पीए, पीएस, पीआरओ) से लेकर सचिवालय तक, एक खास जाति का वर्चस्व नज़र आता है। यहां 'योग्यता' की जगह 'अपनापन' ही कुंजी बन गया है। यह प्रवृत्ति अब केवल अपवाद नहीं रही। यह सत्ता का ढांचा बन चुकी है। चुनावी घोषणापत्रों से लेकर जमीनी विकास योजनाओं तक, 'जातीय लाभ' सबसे बड़ा निर्णायक बन गया है। गांवों में सड़कों से लेकर शौचालयों तक पहले जाति देखी जाती है, फिर ज़रूरत। यही वजह है कि तमाम योजनाओं के बावजूद, असली ज़रूरतमंद हाशिये पर रह जाते हैं।

मौन की साझेदारी... जिस मीडिया को समाज का आईना कहा जाता है, वह अब एक भ्रमित दर्पण बन चुका है। सत्ता के नज़दीक बैठने की चाह में, मुद्दे को 'सुनामी' या 'ब्रेकिंग' बनाने के चक्कर में, पत्रकारिता अब पीआर बन चुकी है। आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता पर गहराई से सवाल उठाने की जगह, मीडिया अब किसी और रूप में ही सामने है। आदिल जैसे नायक का बलिदान कुछ चैनलों पर "ब्रेकिंग" बना, लेकिन अगले दिन ही वह गायब हो गया, क्योंकि वह न तो 'टीआरपी' का हीरो था, और न किसी दल का।

रास्ता क्या है?... भारत अगर वाक़ई विश्वगुरु बनना चाहता है, तो उसे पहले अपने अंदर के इन ज़हरों से मुक्त होना होगा। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ डिग्री नहीं, बल्कि दृष्टि बनना चाहिए। धर्म को हथियार नहीं, सेतु बनाना होगा। और सबसे ज़रूरी, जाति को पहचान नहीं, एक इतिहास मानकर आगे बढ़ना होगा। सरकारों को चाहिए कि वे जातिगत गणित से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नीति पर काम करें। नौकरियों और शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, अफ़सरशाही में प्रतिनिधित्व समान हो, और हर उस संगठन पर नज़र रखी जाए जो जाति या धर्म के नाम पर समाज में जहर घोलता है। **(उक्त आलेख लेखक के निजी विचार हैं।)**

नेशनल हेराल्ड केस : क्या होगा सोनिया और राहुल गांधी का भविष्य?

कांग्रेस के कर्णधारों पर संकट!

राजेश कसेरा ✍ वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीति विश्लेषक

कांग्रेस प्रमुख व राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी इस केस में ऐसे उलझे की बीते 13 सालों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इस केस में यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो न केवल कांग्रेस की समस्याएं बढ़ेंगी, बल्कि गांधी परिवार की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। इन हालात में पार्टी का क्या होगा? इसकी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी धुरी सोनिया और राहुल के आस-पास घूमती हैं।

व्यक्तिवादी सियासी सोच

मौजूदा दौर में देखें तो राजनीतिक दलों की सोच, विचारधारा और काम करने की शैली व्यक्तिवादी ज्यादा हो गई है। देश के अधिकांश दल कार्यकर्ताओं पर कम और पार्टी के नेताओं पर ज्यादा टिके हैं। कांग्रेस पूरी तरह से सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर टिकी हैं तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यादव परिवारों पर। बसपा भी मायावती तक सीमित रह गई तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी तक। हाल ही दिल्ली में सत्ता से दूर हुई आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की हार के बाद बिखर गई। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां भी केवल उसके शीर्ष नेताओं के भरोसे चलती हैं। हर पार्टी केवल अपने नेताओं को बचाने में लगी है, पार्टी को नहीं।

देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस के दुर्दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। बीते 11 सालों में कांग्रेस ने राजनीतिक रूप से लगभग हर चुनाव में मात खाई तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी लगातार जनाधार खोया। हाल ये हो गए कि कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गए तो कई नेताओं के जेल जाने की नौबत आ गई। अनगिनत जांचों और कई कोर्ट केसों में फंसे कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें साल-दर-साल बढ़ती ही गईं। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस पर देश की जनता का भरोसा घटता गया और चुनौतियां बढ़ती गईं।

इसमें भी नेशनल हेराल्ड केस ने तो पार्टी के कर्ता-धर्ताओं को ही बुरी तरह से फंसा दिया। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस केस में बीते 13 सालों से बुरी तरह फंसे हुए हैं। इस केस में यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो न केवल कांग्रेस की समस्याएं बढ़ेंगी, बल्कि गांधी परिवार की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। इन हालात में पार्टी का क्या होगा? इसकी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी धुरी सोनिया और राहुल के आस-पास घूमती हैं। कांग्रेस संकट में घिर जाएगी और पार्टी की बची-कुची ताकत भी कमजोर पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को बैठे-बिठाए संजीवनी मिल जाएगी।

बाहर आया बोतल में बंद जिन्न

नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई फिर से अदालत में शुरू हो गई है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा-तीन (मनी लॉन्ड्रिंग) और धारा-चार (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी के साथ यंग इंडियन कंपनी के निदेशकों सैम पित्रोदा और सुमन दुबे समेत अन्य के नाम हैं। साल 2012 में भाजपा नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया तो कांग्रेस ने रत्तीभर भी नहीं सोचा होगा कि बोतल में बंद ये जिन्न उनका पीछा नहीं छोड़ेगा।

मजबूरी या खीज : शीर्ष नेताओं के खिलाफ एक्शन पर कांग्रेस एकजुट... ईडी की ओर से चार्जशीट दायर होने के बाद से कांग्रेस ने केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी इसे भाजपा की चाल बता रही है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नीचे तक के नेता बोल रहे हैं कि जान-बूझकर उनके नेताओं की छवि खराब की जा रही है। विरोध के दौरान कांग्रेस ने धरना-प्रदर्शन भी किए, जबकि यह स्पष्ट है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए है।

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1915

The National Herald

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

A WEEKLY GREEK AMERICAN PUBLICATION

Bringing the news to generations of Greek Americans

www.thenationalherald.com

ऐसे फंसे सोनिया-राहुल

साल 2010 में बनी यंग इंडियन कंपनी का कुल 76 फीसदी शेयर सोनिया और राहुल गांधी (38-38 फीसदी) के पास और बाकी 24 फीसदी शेयर मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नांडीस के पास था। वोरा और फर्नांडीस दोनों का निधन हो चुका है। कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ का ऋण नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। ऋण चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जर्नल (एजेएल) ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। इस सौदेबाजी की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है।

समन के बाद ईडी का संज्ञान... वर्ष 2012 के नवंबर माह में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। याचिका में उन्होंने बताया कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने महज 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का जो उपाय निकाला, वह नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के दो साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किए। इसके बाद अगस्त-2014 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने संज्ञान लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया।

नियमित जमानत पर हैं बाहर... केस दर्ज होने के बाद एक साल बाद 19 दिसंबर 2015 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत मिल गई। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था तो राहत की बात ये रही कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। इस फैसले के दो साल बाद 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया।

जानें मामला आखिर है क्या... वर्ष 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के पास था। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। यह दो और अखबार भी छापती थी। हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा-25 से कर मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे-धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई।

जंगे आजादी की बने थे आवाज... एजेएल के तीनों अखबार देश की आजादी में महत्वपूर्ण कड़ी बनने वाले माध्यम बने थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ जुड़े होने के कारण इसकी पहचान राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में होने लगी। उस समय इसमें प्रकाशित होने वाले लेख इतने प्रभावशाली साबित हुए कि अंग्रेज तक भयभीत हो गए। वर्ष 1942 में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। तीन साल बाद फिर इसका प्रकाशन शुरू हुआ और आजादी के बाद भी प्रमुख समाचार पत्रों के तौर पर छपता रहा। बाद में यह कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बनकर रह गया। वर्ष 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया।

कांग्रेस ने नियम विरुद्ध दिया कर्जा... आर्थिक तंगी के कारण एजेएल को कांग्रेस पार्टी ने समय-समय पर 90 करोड़ रुपए उधार दे दिए, जबकि यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट- 1950 का उल्लंघन है। इसके मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती। 23 नंवबर 2010 को गांधी परिवार की नॉन-प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन सामने आई, जिसके निदेशक सुमन दुबे और सैम पित्रोदा बने। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को भी निदेशक बोर्ड में शामिल किया गया। इसके बाद एजेएल के शेयर बकायदा सौदा करके यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए। 90 करोड़ का कर्ज केवल 50 लाख रुपए लेकर माफ कर दिया गया। इसके बाद 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी कंपनी की निदेशक बन गईं। जेएल की बात करें तो भारत में इसकी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है।

अस्सी फीसदी शेयर होल्डर्स भी गायब... एजेएल कंपनी को शुरू करने वाले शेयर धारकों की संख्या लगभग पांच हजार थी। वर्ष 2010 तक 1057 शेयरधारक ही रह गए। इनमें पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री शांति भूषण के पिता और इलाहाबाद-मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू शामिल थे। उन्होंने दावा भी किया था कि उनके पिता ने एजेएल की स्थापना पर 300 शेयर खरीदे थे। भूषण ने भी एजेएल का स्वामित्व यंग इंडियन को दिए जाने को गैरकानूनी बताया था।

बेशकीमती संपत्तियों पर थी नजर : स्वामी

साल 2012 में मामले की कलई खुली तो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोर्ट में केस करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये डील गैर कानूनी तरीके से की गई। देश के सात सात शहरों की प्राइम लोकेशन पर मौजूद एजेएल की जमीनों की कीमत ही 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। स्वामी ने आरोप लगाए कि यंग इंडिया ने एजेएल खरीदने के दौरान इसकी जानकारी शेयर धारकों को नहीं दी। न ही समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। इससे जाहिर था कि कंपनी की नजर एजेएल की बेशकीमती संपत्तियों पर थीं। उनके इसी मुकदमे के बाद नेशनल हेराल्ड केस देश के सामने आया।

राजस्थान में भी कसा शिकंजा!

राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को गत 24 अप्रैल को ईडी ने जलजीवन मिशन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में जोशी से पूछताछ करेंगे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बने सवा साल हो गया, लेकिन यह पहला अवसर है जब भ्रष्टाचार के मामले में किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बार-बार कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार करने वाले बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा इन्हें पकड़ने के लिए सरकार को ललकारते रहे। डोटासरा ने तो यहां तक कहा था कि मगरमच्छों को पकड़ने के वादा करने वाली भाजपा से चूहे तक नहीं पकड़े जा रहे।

क्या जोशी ने घोटाले को अकेले अंजाम दिया?

जोशी की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें बड़ा सवाल यह है कि क्या जल जीवन मिशन घोटाले को जलदाय मंत्री महेश जोशी ने अकेले अंजाम दिया? माना कि करोड़ों रुपए के टेंडरों को स्वीकृत करवाने में जोशी की भूमिका थी? पर, इतने बड़े भ्रष्टाचार की भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्यों नहीं लगी? सब जानते हैं कि गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में जोशी का जबरदस्त दबदबा था। अशोक गहलोत तीन बार कोरोना से संक्रमित हुए और एक बार एंजियोप्लास्टी करवाई, तब उनका काम जोशी ने किया था। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार को बचाने के लिए पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई, वह भी महेश जोशी के नाम से हुई। महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी जब बलात्कार के केस में फंसे तो उसे बचाने के लिए सीएम गहलोत और उनकी सरकार पूरी ताकत लगा दी।

गहलोत और जोशी की घनिष्ठता जगजाहिर

प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी की घनिष्ठता जगजाहिर है। कांग्रेस सरकार में भी दोनों के गठजोड़ से सब वाकिफ थे। इसी तरह से प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े विशेषज्ञों की मानें तो सभी विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ऐसे में किसी विभाग में भ्रष्टाचार होने पर वे भी जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में जोशी के गिरफ्त में आने के बाद क्या भ्रष्टाचार की आंच गहलोत तक पहुंचेगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।

जोशी के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत

ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जेजेएम के भ्रष्टाचार का पैसा महेश जोशी के मित्रों और रिश्तेदारों के खातों में आया। इससे जोशी के लिए बेनामी संपत्तियां तक खरीदी गईं। यह भी देखना होगा कि जोशी तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत से जुड़े सवालों का क्या जवाब देते हैं? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ईडी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास सहित कई नेताओं के यहां भी छापामार कार्यवाही की थी। ऐसे में क्या इन पर भी आने वाले दिनों में फिर से कोई कार्रवाई होगी, ये सवाल भी बने रहेंगे।

मौन में राजनीति

भीनमाल से विधायक डॉ. समरजीत सिंह की राजनीति इन दिनों 'मौन और मौजूदगी की अनुपस्थिति' से जानी जाने लगी है। कांग्रेस का बड़ा आयोजन हो, कार्यकर्ताओं का सैलाब हो, और स्थानीय विधायक मंच से गायब हों— यह न केवल सवाल खड़े करता है, बल्कि पार्टी नेतृत्व के प्रति उदासीनता और असंतोष को भी उजागर करता है। जालोर में कांग्रेस भवन के लोकार्पण और कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे महत्त्वपूर्ण मौके पर उनकी गैरमौजूदगी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को निराश किया, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी यह कहने पर मजबूर कर दिया कि पार्टी के भीतर 'स्लीपर सेल' नहीं चाहिए। डॉ. समरजीत सिंह की यह चुप्पी और दूरी दर्शाती है कि या तो वे पार्टी के हालिया दिशा-निर्देशों से असहमत हैं, या फिर राजनीतिक मंच पर उनकी रुचि अब महज़ नाममात्र की रह गई है। जिन जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज़ बनना था, वे खुद ही मंच की रोशनी से दूर भाग रहे हैं। राजनीति में मौन भी कभी-कभी मुखर विरोध बन जाता है, और शायद समरजीत सिंह का यह मौन भी आने वाले समय में बड़ा संदेश दे जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी इस 'मौन' को सुनने को तैयार है या अब उसकी साफ-साफ जवाबदेही लेगी?

शिक्षा से ज्यादा ठहराव की चिंता

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा व्यवस्था को एक नया "मूलमंत्र" दिया है– बिना ठहरे सुधार नहीं! अब हर अधिकारी को माह में चार बार ग्राम पंचायतों में ठहरना होगा, जैसे शिक्षा की देवी वहीं डेरा डाले बैठी हों। दिलावर के तेवर देखकर लगता है कि वे शिक्षा मंत्रालय नहीं, कोई युद्ध मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा – "बिना फील्ड विजिट नहीं चलेगा काम!" मतलब अब अधिकारी कागजों में योजना नहीं बनाएंगे, बल्कि कीचड़ में उतरकर स्कूली हकीकत से साक्षात्कार करेंगे। कहना पड़ेगा, मंत्री जी ने 'ठहरने' को इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया कि अब शिक्षा से ज्यादा चर्चा ठहराव की होने लगी है। कुछ अधिकारियों ने तो गांवों में चार दिन ठहरने के लिए होटल बुकिंग की सोची, लेकिन वहां "शौचालय निर्माण योजना" अधूरी निकली! घटिया निर्माण पर कार्रवाई की चेतावनी भी मिली— यानी जो स्कूल की दीवार गिरने से बच गए हैं, अब वे रिपोर्ट की स्याही से ढह सकते हैं। मंत्रीजी का शिक्षा सुधार फार्मूला सीधा है– जहां ठहरोगे, वहीं समझोगे! अब देखना यह है कि शिक्षा सुधरती है या अधिकारी "ठहरने की विवशता" में छुट्टियों का गणित बनाते हैं!

ग्रामीणों का 'प्रशासनिक उपवास'

मुख्य सचिव सुधांश पंत जब कोटपूतली पहुंचे तो शायद उन्होंने सोचा था कि गार्ड ऑफ ऑनर, बैठकें और कैमरे ही उनके स्वागत को काफी होंगे। मगर जनता ने उन्हें एक अलग ही 'ऑनर' दिया– कलक्ट्रेट के गेट पर ताला जड़कर! कहते हैं, अधिकारी का कद बहुत बड़ा होता है, लेकिन गांव वालों ने साबित कर दिया कि ताले की चाबी उस कद से भी बड़ी हो सकती है। पंत जहां निर्देश दे रहे थे, वहीं बाहर जनता गेट बंद कर 'प्रशासनिक उपवास' पर बैठ गई। अब पंत साहब को पिछले गेट से निकाला गया– वो भी गुपचुप तरीके से, जैसे कोई फिल्म का सस्पेंस सीन हो। शायद पहली बार हुआ होगा कि एक मुख्य सचिव को 'सहमे कदमों से' पीछे के दरवाजे से बाहर जाना पड़ा हो। अधिकारियों की बैठकें, योजनाओं की समीक्षा, नीतियों का अमल– सब ठीक, लेकिन जब जनता अपनी बात न सुने जाने पर ताले से संवाद करे, तो समझिए कि 'फील्ड विजिट' से ज्यादा ज़रूरी है 'फील्ड रियलिटी'। पंत साहब, अगली बार जब फील्ड पर आएं तो ताले नहीं, दिल खोलने वाले अधिकारी लेकर आइए। वरना जनता गेट बंद करने में देर नहीं करती– और अफसर पीछे से निकल जाते हैं!

कुंडली में ईडी योग

राजस्थान की राजनीति में जब भी कोई नेता खुद को राहुल गांधी का सच्चा अनुयायी घोषित करता है, तो लगता है जैसे ईडी के रडार पर अपने आप एक बत्ती जल उठती है। इस बार बारी आई प्रतापसिंह खाचरियावास की। वही तेज-तर्रार नेता जो जुबान से जलेबी घुमा देते हैं और बयानों में मिर्च झोंकना उन्हें बचपन से आता है। सुबह-सुबह 7 बजे जब जयपुर की गलियों में दूधवाले भी ऊंघ रहे थे, ईडी ने दरवाज़ा खटखटाया– और राजनीतिक हलचल की चाय चढ़ गई। खाचरियावास जी ने तुरंत बयान ठोका, 'राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो बीजेपी का क्या होगा?' अब भाई, जनता को तो यह जानना है कि आपके घर में क्या मिला, आप बार-बार राहुल गांधी का सपना 2047 क्यों दिखा रहे हैं? वैसे कांग्रेस की चुप्पी देख लगता है कि पार्टी कह रही है– "खुद बोया है, खुद ही भोगो।" खाचरियावास जी के तेवर देख लगता है जैसे उन्होंने ईडी को चाय पानी भी ऑफर किया होगा– 'घबराओ मत, यहां डरने का सामान नहीं मिलता!' पर अब देखना ये है कि जांच क्या बताती है– वाणी वीर थे या वाकई जमीन-जायदाद में भी पराक्रमी निकले?

▪ बलवंत

फर्जी निकला 'दिलजला' दिल का डाक्टर..!

हरीश मलिक
वरिष्ठ व्यंग्यकार

डाक्टर को भगवान कहा जाता है। लेकिन अब 'है' कुछ की करतूतों से 'था' में बदल गया है। पड़ोसी छोटू मुल्क में एक ऐसा डॉक्टर सुर्खियों में है, जो कान पर थप्पड़ मार-मारकर मरीजों का इलाज करता है। यह बात दूसरी है कि अपना भारत महान भी ठीक इसी तकनीक से बरसों के पाकिस्तान का इलाज कर रहा है। दो-चार बार तो थप्पड़ के जगह हथगोले और सर्जिकल स्ट्राइक भी दागने पड़े। फिर भी ससुरा सुधरने का नाम ना ले रहा। खैर, अब चलते-चलते दमोह के डॉक्टर की बात भी कर लेते हैं। उसका असली नाम- नरेंद्र विक्रमादित्य यादव।

फर्जी नाम- डॉ. एन जॉन कैम। काम- नकली कॉर्डियोलॉजिस्ट बनकर हार्ट सर्जरी यानी दिल का ऑपरेशन। नतीजा- सात लोगों की मौत। मतलब ये डॉक्टर को दिल को सही करने बजाए यमराज बनकर लोगों के दिलों को डराने में लगा रहा। दिल का डॉक्टर पूरी तरह दिलजला फर्जी निकला। इसकी डिग्री, रजिस्ट्रेशन सब कुछ फर्जी। मजे की बात ये है कि भइये, 2006 में विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष शुक्ल जी का ऑपरेशन भी इसी फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने किया था! मतलब, जब सरकार की ही आंख-कान बंद हैं तो मासूम जनता तो गरीब की जोरू कहलाती है!

दुनिया का चौधरी बोले तो 'पलटू चाचा'

मनुष्यों में एक प्रजाति ऐसी भी है जो देश-काल की सीमाओं से सर्वथा परे है। देश हो या विदेश, इनके कई गुण-अवगुण चोर-चोर मौसेरे भाई की तरह मिलते हैं। समझदार को इशारा काफी होता है और आप तो सर्वज्ञानी है, सो समझ ही गए होंगे कि हम राजनेताओं की परम प्रजाति की चकल्लस कर रहे हैं। वैसे इनका तकियाकलाम फिल्मी गाने कस्मे-वादे और वफा सब बातें हैं बातों का क्या...से हूबहू मेल खाता है। अब अपने ट्रम्प भइया को ही ले लीजिए। उनके ट्रम्प टैरिफ ने दुनियाभर में खूब धमाल मचाया। लेकिन यो क्या भाया...ये तो पलटी मारने में अपने 'पलटू चाचा' को भी मात दे बैठे। पलटू चाचा तो सिर्फ सत्तासुख की खातिर पार्टियों में पलटी मारते हैं, लेकिन डोनल्ड डक की चाल से स्टॉक मार्केट से लेकर बड़े-बड़े बिजनेसमैन तक दिन में तारे गिनने लगे। ट्रम्प ने अपनी ही पार्टी से लेकर विदेशी नेताओं तक को खूब छकाया। ट्रम्प ने अपने पैरों पर टैरिफ की कुल्हाड़ी मार कर अब 90 दिन की मोहलत दी है। यह भी हो सकता है कि मोहलत उनका खुद का दिमाग ठंडा करने के लिए हो। क्योंकि शी नाम वाले हीमैन जिनपिंग की चाल ने दुनिया के चौधरी बनने निकले ट्रम्प की नींद उड़ा दी है।

बदजुबानी यानी, कामरा की कहानी

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक बड़ा फाड़ू मीम्स नजर आया... जब 'समय' खराब चल रहा तो तो चुप 'रैना' चाहिए। सही समझे, वही स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना जिन्होंने पहले कॉमेडी का कबाड़ा किया और फिर उनका खुद का भी हो गया। लेकिन सेम प्रोफेशन वाले से यदि कोई सबक ले तो लोग क्या कहेंगे। भाई की नाक ना कट जाएगी। सो कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कोई क्लियर-कट मैसेज नहीं लिया। भाई लिया होता तो आजकल मद्रास हाईकोर्ट के हाथ-पैर ना जोड़ रहे होते। फिल्मों में कॉमेडी के फन्ने खां कह गए हैं कि किसी को हंसाना सबसे बड़ी कला है। पर आजकल के कुछ युवा कॉमेडियनों ने कला में अपनी अश्लील कलाकारी घुसेड़ दी है। कला गई चूल्हे में तेल लेने। अपन तो अपना एजेंडा चलाएंगे। किसी को भी 'गद्दार' बताएंगे। हद तो वह युवा पीढ़ी भी कर रही है, जो कामरा की फैन है। उसको लगता है कि यदि ऐसी कॉमेडी पर नहीं हंसे तो पिछड़े मान लिए जाएंगे। चार लोग कहेंगे कि इन्हें नए जमाने की कॉमेडी की चाल-चलन नहीं मालूम है। यह चार लोग वो हैं, जिन्हें खुद कॉमेडी की समझ नहीं है!

'सिकंदर' का मुकद्दर नहीं चला

विलियम शेक्सपियर ने सच ही लिखा था कि नाम में क्या रखा है। यदि नाम की ही महत्ता होती को खुशहाल सिंह कभी दुखी और धनीराम गरीबी-गुरबत में ना मिलते। लेकिन ये बात बॉलीवुड वालों के गले कम ही उतरती है। तभी वे पुरानी हिट फिल्मों के नाम चुराकर पुरानी बोतल में नई शराब बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं। 1978 में अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी मुकद्दर का सिकंदर आई थी। तब फिल्म ने खूब धूम मचाई। अब सलमान खान इसका सिकंदर लेकर अपना मुकद्दर बनाने निकले। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला.., मुकद्दर की बात है। कभी-कभी मुकद्दर को ब्लैक बक की भी हाय लग जाती है। और काठ की हांडी भी बार-बार नहीं चढ़ पाती है। ईद पर रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर अब सलमान के फैंस ने ईदी मांगी है कि 'सिकंदर' को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए!

यह 'विदा' कहने का वक्त है माही

अपने भारतीय संस्कारों में विदाई का परम महत्त्व है। बिटिया की विदाई। कंवर-सा की विदाई। अधिकारी की विदाई। यहां तक कि कभी मेहमानों को विदा करने स्टेशन तक जाने का चलन था। लेकिन कुछ विशेष किस्म के जिद्दी मेहमानों की कभी-कभी जबरन विदाई की नौबत भी आ जाती है। खबर आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान रितुराज के घायल होने से माही को तैंतालीस की 'तरुणाई' में एक बार फिर से टीम की कप्तानी सौंप दी गई है। वह भी तब, जबकि कैप्टन कूल की 'किलर इंस्टिंक्ट' फेल हो चुकी है। हेलिकॉप्टर शॉट अब जमीन पर भरभरा रहा है। माही परफेक्ट फिनिशर की अपनी भूमिका से भी पूरा न्याय नहीं कर पा रहे। बातें तो माही की सम्मानजनक विदाई की चल रही थीं, लेकिन हार पर हार झेल रही सीएसके को धोनी की कप्तानी के साथ एक और हार मिल गई। समझ में नहीं आ रहा कि सीएसके के लिए रितुराज का घायल होना बड़ा झटका है या फिर माही का फिर से कप्तान बनना!

गर्मी में खोपड़िया का बचाव जरूरी

गर्मी के दिन काफी बड़े और दिलवाले होते हैं, लेकिन दिमाग गर्मी से सन्न होकर कुछ कम हो जाता है। इसलिए इन दिनों सरल वाक्यों का प्रयोग ही श्रेष्ठतम बचाव है। संयुक्त, मिश्रित और द्विअर्थी वाक्यों से शरीर का कम्प्यूटर यानी दिमाग जल्दी पक जाता है। वैसे गर्मी के मौसम में सब कुछ जल्दी पकता है, लेकिन खोपड़िया का नंबर सबसे अव्वल है। इसलिए इसे ठंडा रखने के श्रेष्ठ उपाय परम आवश्यक हैं। गर्मी में सबसे सरल उपाय है तीन पंखुड़ियों वाला पंखा। लेकिन इसे देखकर सहज ख्याल आता है कि कुछ कहावतें कैसे समय के साथ बदल जाती हैं। जैसे, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। भला पंखे की तीन पंखुड़ी से काम कैसे बिगड़ेगा। बल्कि वो ना हों तो गर्मी के दिनों में अच्छे-भले आदमी का बिगाड़ा हो जाए। गर्मी में बिन पंखा सब सून है। क्योंकि तब सुनने, समझने और बोलने की क्षमता का पतन हो जाता है। डैड डेड की तरह, मम्मी मिस्र की ममी की तरह दिखाई देने लगते हैं।

अब अदालत तय करेगी वक्फ कानून की वैधता

हंगामा है क्यूं बरपा...!

राधा रमण ✍ वरिष्ठ पत्रकार

देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड गठित किया गया है। समय-समय पर इन वक्फ बोर्डों पर आर्थिक घपले के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन चूंकि वक्फ मामलों की सुनवाई सरिया कानून के तहत होने, वक्फ के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकने और सार्वजनिक अदालतों में नहीं होने के कारण कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। उधर वक्फ बोर्डों के पदाधिकारी मालामाल होते रहे हैं।

भले ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल को देशभर में वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू हो गया है, लेकिन इसकी वैधता पर अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव हो सकेगा। इस कानून को कई मुस्लिम संगठनों और राजनेताओं ने अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके लिए 73 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। देश के अलग-अलग भागों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का बवाल शर्मिंदा करने वाला है। वहां तीन लोगों की जान चली गई। कई वाहनों को आग के हवाले किया गया। लूटपाट हुई और पांच सौ से ज्यादा लोग पलायन कर गए। करीब 250 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर समूचा शहर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है।

भाजपा के नेता इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्लिम परस्त नीति को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं तो ख़ुफिया एजेंसियां मुर्शिदाबाद हिंसा को सीमापार के घुसपैठ से जोड़ रही हैं। उधर, ममता बनर्जी सवाल कर रही हैं कि अगर, पश्चिम बंगाल में विदेशी घुसपैठ हो रही है तो फिर केंद्र सरकार और गृहमंत्री आखिर क्या कर रहे हैं..? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए सियासत का पहिया कुछ ज्यादा घूम रहा है।

इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में 'वक्फ बचाव अभियान' शुरू कर दिया है। इसके तहत एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराकर ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस कानून में क्या है, जिससे मुस्लिम संगठनों और बिल का विरोध करने वाले दलों का 'इस्लाम' खतरे में आ गया है।

विपक्षी दल दे रहे हवा

कांग्रेस समेत देश के विपक्षी दल वक्फ संशोधन कानून के विरोध को हवा दे रहे हैं। इस कानून के विरोध में याचिका दाखिल करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रतिनिधि समेत कई लोग शामिल हैं। लगातार दो दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय देने के साथ याचिकाकर्ताओं को भी विरोध के पांच बिन्दुओं पर सहमति बनाकर आने को कहा, ताकि अदालत जल्दी कोई फैसला ले सके। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने वक्फ संशोधन क़ानून पर अमल तत्काल प्रभाव से रोक दिया और अगली तारीख तक वक्फ बोर्ड और परिषदों में किसी नियुक्ति और वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव पर रोक लगा दी।

दरअसल, विपक्ष और नये वक्फ कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि सारा विवाद वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर कब्जे को लेकर है। देशभर में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है। इससे ज्यादा भूमि का स्वामित्व रेलवे और सशस्त्र बलों के पास है। वक्फ बोर्डों को यह सम्पत्तियां मुसलमानों ने दान की है, जिन पर दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, दुकान आदि स्थापित हैं। इसके अलावा बहुतेरी कृषि भूमि भी है। इसकी देखरेख के लिए देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड गठित किया गया है। समय-समय पर इन वक्फ बोर्डों पर आर्थिक घपले के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन चूंकि वक्फ मामलों की सुनवाई सरिया कानून के तहत होने, वक्फ के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकने और सार्वजनिक अदालतों में नहीं होने के कारण कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। उधर वक्फ बोर्डों के पदाधिकारी मालामाल होते रहे हैं।

नये वक्फ कानून से आम मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन वक्फ (दान) में मिली सम्पत्तियों के बन्दर बांट होने का शक जरूर गहराने लगा है। वैसे भी वक्फ ने अपनी आमदनी का उपयोग किसी गरीब मुसलमान की पढ़ाई-लिखाई अथवा उसका जीवन स्तर सुधारने के लिए किया हो, इसका उदाहरण नहीं मिलता। काश, अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों की दशा-दिशा सुधारने की कोई पहल करता होता तो आज हालात कुछ और होते। हां, वक्फ बोर्डों पर काबिज लोग जीवनभर ऐशोआराम का जीवन जरूर जीते रहे।

संसद में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजजू ने कहा कि वक्फ बोर्डों के पास लाखों करोड़ की सम्पत्ति होने के बावजूद इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के पक्ष में नहीं होने के कारण अराजकता की स्थिति थी। हम बिल नहीं लाते तो वह संसद भवन पर भी दावा कर सकते थे।

विधेयक के समर्थक नेता कहते हैं कि विपक्ष के नेता वक्फ कानून का विरोध कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हमदर्द बनने का दिखावा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लगाए टैरिफ पर चुप रहते हैं। ये वही लोग हैं जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या आदि पर सड़क पर निकल कर विरोध करना भूल गए हैं। ये वही लोग हैं जो समाज में जातीयता का जहर घोलने पर आमादा हैं। ये वही लोग हैं जो जाने-अनजाने भाजपा की बिछाई बिसात पर चौसर खेलने को अभिशप्त हैं।

दरअसल, भाजपा तो शुरू से चाहती है कि देश का जनमत हिन्दू-मुस्लिम में विभाजित हो जाए, ताकि उसे आसानी से बहुमत मिलता रहे। सवाल नए वक्फ कानून पर नहीं, बल्कि कानून बनाने के समय पर होना चाहिए। 2014 और 2019 में जब भाजपा को संसद में पूर्ण बहुमत था। उस समय भाजपा चाहती तो यह कानून आसानी से बनाया जा सकता था। लेकिन तब भाजपा ने ऐसा नहीं किया। अब जबकि लोकसभा में भाजपा के महज 240 सांसद हैं, तब यह कानून बनाकर भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार सरीखे अपने सहयोगी दलों के नेताओं की मुस्लिम परस्ती को खुलेआम चुनौती दे दी है। साथ ही यह संदेश भी कि 'वृंदावन में रहना है तो राधे-राधे कहना होगा'।

बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसका सर्वाधिक नुकसान नीतीश की पार्टी जनता दल (यू), चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) और जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा को होगा। भाजपा ने अपने चक्रव्यूह में इन्हें घेर लिया है और निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वक्फ बिल पर संसद में जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह की दलील सुनकर जदयू में भगदड़ की स्थिति बन गई और उसके दर्जनभर से अधिक नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कई अभी पार्टी छोड़ने की कगार पर बैठे हैं और उचित समय का इंतजार कर रहे हैं।

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ठीक ही तो कहते हैं कि 'जिस तरह से जदयू और तेलुगुदेशम पार्टी ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया, वो बताता है कि पिछले दस महीनों में सियासत का चक्का कितनी तेजी से घूमा है। नीतीश और नायडू दोनों ने अब भाजपा की प्रमुख स्थिति को स्वीकार कर लिया है। इसमें भी नीतीश का बार- बार पाला बदल राजनीति में विचारधारा हीनता का स्पष्ट उदाहरण है। चंद्रबाबू नायडू का मामला थोड़ा पेचीदा है। वे एक ऐसे राज्य की कमान संभाल रहे हैं, जहां भाजपा बड़ी ताकत नहीं है। उनके पास प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक अनुभव है, जिसकी मदद से वे भाजपा पर निर्भर हुए बिना भी आंध्र प्रदेश की सत्ता में बने रह सकते हैं।'

विपक्ष का एक तर्क यह भी है कि केंद्र सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पने के बाद ईसाइयों और फिर मन्दिरों की जमीन पर कब्जा करेगी। लेकिन यह दूर की कौड़ी है। बहरहाल, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं और देखना दिलचस्प होगा कि शीर्ष अदालत इस समस्या का कैसे समाधान करती है।

गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि नये बिल से अब वक्फ के आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। पहले वक्फ का फैसला ही अंतिम होता था। यह गलत धारणा है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के धार्मिक आचरण, उनके द्वारा दान की गई सम्पत्ति में हस्तक्षेप करेगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी कहते हैं कि देशभर में वक्फ का दुरुपयोग करना एक बीमारी बन गई है। इसे रोकने में नया कानून कारगर होगा। आरिफ कहते हैं कि गरीबों, कमजोरों और जरूरतमंदों पर अपनी आमदनी में से खर्च करने की बात कुरआन में भी लिखी गई है, लेकिन वक्फ यह सब कहां करता था। वक्फ के जरिये न तो कोई अस्पताल चलता है, न ही बढ़िया स्कूल-कालेज। इसके जिम्मेदारों ने वक्फ को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए वक्फ की जमीन पर धर्मार्थ काम करने की जरूरत है।

VS

उधर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि यह कानून मुसलमानों की सम्पत्ति हड़पने के लिए बनाया गया है। यह भारत के मूल विचारों पर हमला है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भाजपा मस्जिद- मन्दिर में टकराव बढ़ाकर देश को अस्थिरता में धकेलना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वह पश्चिम बंगाल में कानून को लागू नहीं होने देंगी। मुंगेरीलाल की तरह हसीन सपने देखते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वह इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। सपा-बसपा के नेता भी कुछ इसी तरह की बात कहते हैं।

'ब्रेन-टू-ब्रेन इंटरफेस की बदलती दुनिया'

जब दिमाग व अनुभव ट्रांसफर होने लगेंगे

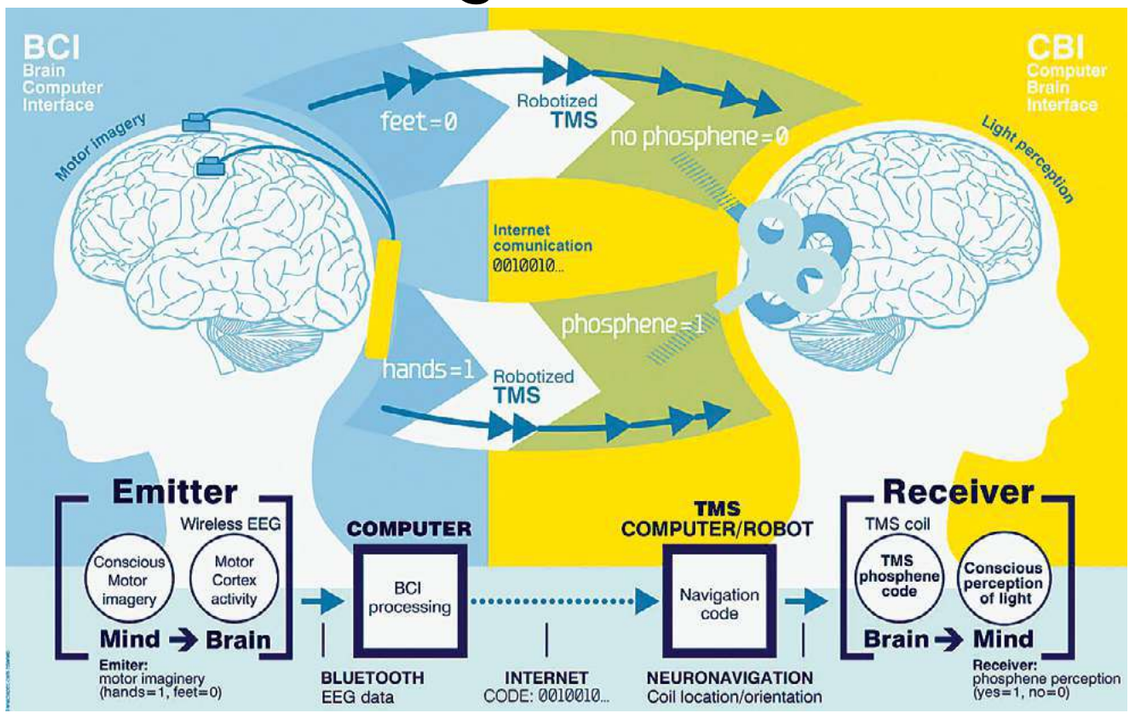

राकेश गांधी ✍ वरिष्ठ पत्रकार

एक समय था जब 'टेलीपैथी', यानी मन की बात बिना कहे समझना, केवल विज्ञान की कहानी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज की वैज्ञानिक प्रगति इस धारणा को वास्तविकता की दिशा में ले जा रही है।

कई बार नए- नए शोधकार्यों को देखते हुए व सुनते हुए मन में ख्याल आता है कि क्या इंसान अपने अनुभव को किसी दूसरे इंसान के दिमाग या शरीर में मात्र एक इंजेक्शन या किसी तकनीक के जरिए ट्रांसफर करा सकेगा? ऐसा ख्याल इसलिए भी आता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी आकाश में उड़न खटोले के माध्यम से उड़ने की कल्पना की थी और आज हम विमानों में आसानी से उड़ रहे हैं। कभी चांद-सितारों तक पहुंचने का मन बनाया था, आज पहुंच भी रहे हैं। कभी किसी जानलेवा बीमारी का नामो-निशां मिटाने की ठानी थी, इसमें भी सफलता हासिल कर ली। इतना सबकुछ देखकर दिमाग या अनुभव ट्रांसफर की कल्पना बेमानी नहीं लगती। निकट भविष्य में लगता है इंसान इसमें सफलता जरूर हासिल कर लेगा।

एक समय था जब 'टेलीपैथी', यानी मन की बात बिना कहे समझना, केवल विज्ञान की कहानी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज की वैज्ञानिक प्रगति इस धारणा को वास्तविकता की दिशा में ले जा रही है। दुनिया भर के शोधकर्ता उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद अनुभव, ज्ञान और विचारों को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में ट्रांसफर कर सके। अगर ऐसा संभव हो जाता है, तो यह मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी उपलब्धियों में से एक होगी।

विद्युत संकेतकों व रसायनों के जरिए काम करता है दिमाग

वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा दिमाग बिजली व रसायनों के जरिए अपना काम करता है। जब हम कुछ सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, या कुछ महसूस करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच विद्युत संकेत चलते हैं। वैज्ञानिकों को अब इन्हीं संकेतों को पढ़ने और संप्रेषित करने में सफलता मिल रही है। ब्रेन-टू-ब्रेन इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो दो लोगों (या प्राणियों) के दिमागों को कम्प्यूटर या अन्य डिवाइस के माध्यम से जोड़ती है। इसका उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति का मस्तिष्क, दूसरे के मस्तिष्क को सीधे सूचना भेज सके, वो भी बिना किसी भाषा, हावभाव या स्क्रीन के। वर्ष 2013 में ड्यूक यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के प्रोफेसर मिगुएल निकोलेलिस और उनकी टीम ने दो चूहों के बीच दिमागी संचार का सफल परीक्षण किया। एक चूहा 'प्रेषक' था, जो एक बटन दबाकर इनाम प्राप्त करता था। उसके मस्तिष्क से निकाले गए सिग्नल को वायरलेस तरीके से दूसरे चूहे को भेजा गया, जिसे 'रिसीवर' चूहा कहा गया। रिसीवर चूहा बिना देखे और सिखाए, वही बटन दबाने लगा।

इंसानों के बीच 'हां' और 'ना' का ट्रांसफर

वर्ष 2014 में अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी (Electroencephalography) और ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (Transcranial Magnetic Stimulation) तकनीक की मदद से दो व्यक्तियों के बीच एक सरल विचार का आदान-प्रदान किया। एक व्यक्ति ने "हां" या "ना" सोचा। यह सूचना दूसरे व्यक्ति के दिमाग में पहुंचाई गई, जो फिर अपने अनुभव के अनुसार प्रतिक्रिया करता। हालांकि यह एक छोटे स्तर का प्रयोग था, लेकिन यह सिद्ध करता है कि इंसानी दिमाग को तकनीकी माध्यमों से जोड़ना संभव है। इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी मस्तिष्क की तरंगों को मापने और समझने की वैज्ञानिक विधि है, जबकि ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन (टीएमएस) एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए मस्तिष्क की बाहरी सतह पर चुंबकीय तरंगें भेजकर मस्तिष्क की गतिविधियों को उत्तेजित किया जाता है।

मस्तिष्क व कम्प्यूटर के बीच सीधा संवाद

एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इस क्षेत्र में बड़ी रुचि दिखाई है। यह कंपनी एक ऐसी माइक्रोचिप बना रही है जो इंसान के मस्तिष्क में लगाई जा सकती है। इसके जरिए मस्तिष्क और कम्प्यूटर के बीच सीधा संवाद हो सकेगा। इस तकनीक को ब्रेन-कम्प्यूटर इंटरफेस (बीसीआई) कहा जाता है। मस्क ने दावा किया है कि शीघ्र ही यह तकनीक न केवल लकवाग्रस्त मरीजों की मदद कर सकेगी, बल्कि सामान्य लोगों को भी "सुपरह्यूमन" बना सकती है। वे कहते हैं, "एक उच्च गति के ब्रेन-मशीन इंटरफेस के जरिए हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ सहजीविता स्थापित कर सकते हैं।"

क्या अनुभव भी ट्रांसफर हो सकेंगे..?

इस दिशा में काम कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ 'जानकारी' ही नहीं, बल्कि अनुभव और भावनाएं भी ट्रांसफर की जा सकती हैं। मेमोरी इम्प्लांट क्षेत्र में कुछ प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग में ऐसी यादें "इम्प्लांट" कीं, जो उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं की थीं। उदाहरण के लिए, चूहे को यह अहसास दिलाया गया कि एक विशेष गंध से उसे झटका लगेगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यह तकनीक भविष्य में पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानि आघातोत्तर तनाव विकार जैसे मानसिक रोगों के इलाज में उपयोगी हो सकती है, जहां नकारात्मक यादों को हटाया या बदला जा सके।

यदि ऐसा संभव हुआ तो

यदि ब्रेन-टू-ब्रेन ट्रांसफर पूरी तरह से संभव हो जाए, तो यह हमारी शिक्षा, चिकित्सा, मनोविज्ञान, रक्षा और संचार प्रणाली को पूरी तरह बदल सकता है। शिक्षक का अनुभव छात्रों में सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है। डॉक्टर सर्जरी की ट्रेनिंग को सीधे दिमाग में अपलोड कर सकते हैं। सैनिक बिना बोले रणनीतियां साझा कर सकते हैं। अपंग व्यक्ति रोबोट को अपने दिमाग से नियंत्रित कर सकेगा। हालांकि वैज्ञानिक इस समस्या पर भी जूझ रहे हैं कि क्या ये तकनीक सुरक्षित है? इस तकनीक के साथ कई नैतिक और सामाजिक चिंताएं भी जुड़ी हैं। निजता के हनन की आशंका रहेगी, क्योंकि कोई भी किसी की अनुमति के बिना उसकी सोच को पढ़ पाएगा। मस्तिष्क में डाली गई जानकारी को बदलने की कोशिश की जा सकती है। और यदि किसी की सोच किसी अन्य इंसान के प्रभाव में आ जाए, तो क्या वह इंसान अभी भी 'वही' रह पाएगा जो वो पहले था? ब्रेन हैकिंग, मेमोरी मैनिपुलेशन, और सोच की चोरी जैसे मुद्दे विज्ञान के साथ-साथ नीति-निर्माताओं और समाज के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

> हमने दो मस्तिष्कों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया है। यह ऐसा है जैसे दो दिमाग मिलकर एक की तरह काम कर रहे हों।"
> **- डॉ. मिगुएल निकोलेलिस** (न्यूरोसाइंटिस्ट, ड्यूक यूनिवर्सिटी)

> जैसे ही आप सोच को डिकोड कर सकते हैं, आपको उसे सुरक्षित रखने के बारे में भी सोचना चाहिए। मस्तिष्क से जुड़ा डाटा सबसे निजी जानकारी होती है।"
> **- डॉ. राफाएल युस्टे** (कोलंबिया यूनिवर्सिटी)

> वह दिन दूर नहीं जब सोच से नियंत्रित कृत्रिम अंग और मस्तिष्क-आधारित सीखना, रोजमर्रा की हकीकत होंगे।"
> **- डॉ. नितिन शर्मा** (पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी)

> हम सिर्फ दिमागी संकेत पढ़ नहीं रहे हैं; हम एक नई संवाद पद्धति बना रहे हैं — दिमाग से दिमाग तक, सीधे।"
> **- डॉ. ऐंड्रू श्वार्ट्ज** (प्रोफेसर- न्यूरोबायोलोजी)

पौराणिक दृष्टिकोण — क्या यह विचार नया है?

भारतीय पौराणिक साहित्य और दर्शन में ऐसी कई अवधारणाएं मिलती हैं जो ब्रेन-टू-ब्रेन इंटरफेस या अनुभव ट्रांसफर की कल्पना से मिलती-जुलती हैं: जैसे,

मन की बात समझना- महाभारत में श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद कई बार मौन, दृष्टि और भावना के माध्यम से होता है। हनुमान जी सीता माता का दुःख मन से जान लेते हैं — यह मानसिक तरंगों के माध्यम से संप्रेषण का सांस्कृतिक संकेत हो सकता है।

गुरु-शिष्य परम्परा और संस्कारों का स्थानांतरण - गुरु अपने अनुभव और ज्ञान को शिष्य में स्थानांतरित करता है — न केवल शब्दों से, बल्कि ध्यान और अभ्यास के माध्यम से। कुछ ग्रंथों में संकल्प द्वारा ज्ञान देने की बात आती है।

संजय की दिव्य दृष्टि, रीयल-टाइम न्यूरल लिंक? - संजय कुरुक्षेत्र युद्ध का विवरण धृतराष्ट्र को रीयल टाइम में देते हैं, जैसे आज वीडियो फीड या ब्रेन सिग्नल ट्रांसमिशन होता है।

वरदान और श्राप के माध्यम से स्मृति या गुणों का ट्रांसफर- कई कथाओं में ऋषि-मुनि स्मृति, शक्ति या चेतना का स्थानांतरण करते हैं, जो अनुभव ट्रांसफर की अवधारणा से मिलता-जुलता है।

इन उदाहरणों से ये तो स्पष्ट है कि आधुनिक विज्ञान जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसकी कल्पना भारतीय दर्शन और पुराणों में अमूर्त रूप में पहले ही की जा चुकी थी। हमारे पूर्वज सदियों आगे की सोचने में सक्षम रहे हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में यह तकनीक अपने शुरुआती दौर में है। यह सही है कि अभी हम किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण अनुभव, भावना या जीवन-ज्ञान दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन दिशा स्पष्ट है। आज जो असंभव लगता है, वह कल सामान्य हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक समय मोबाइल फ़ोन असंभव लगते थे, और आज हमारी जेब में कम्प्यूटर है। वैसे ही आने वाले दशक में, हमारी सोच और ज्ञान भी "शेयर" और "डाउनलोड" किया जा सकेगा। यह तकनीक न केवल विज्ञान, बल्कि मानवता की सोच को भी नया आयाम देगी।

मुफ्त योजनाएं : लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा

राजीव हर्ष ✍ वरिष्ठ पत्रकार

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया है कि मुफ्त योजनाओं को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश या नीति बनाई जानी चाहिए। कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों ने राज्य सरकारों की ओर से दी जा रही मुफ्त सुविधाओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी दी है कि ये योजनाएं देश को श्रीलंका जैसी आर्थिक आपदा की ओर धकेल सकती हैं।

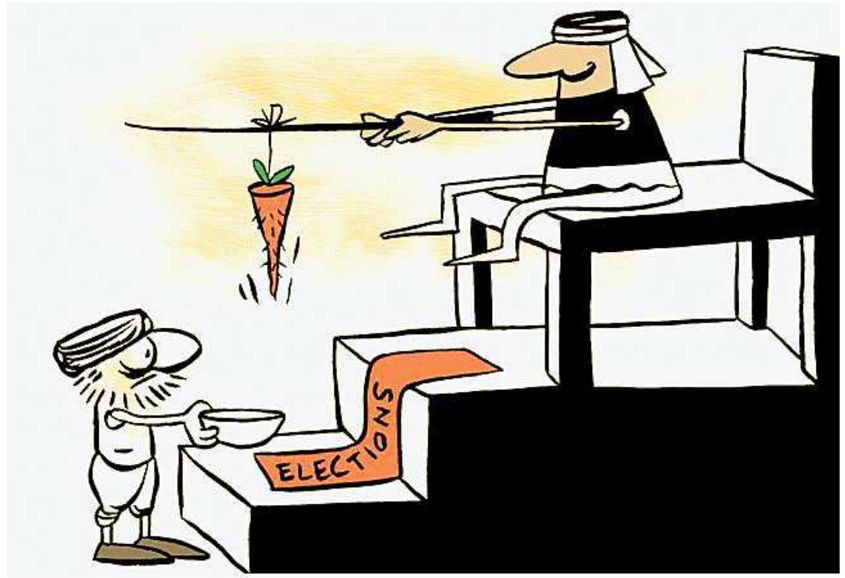

हमारे देश की जनता मुफ्तखोर नहीं है। जनता ने कभी भी पानी, बिजली, लैपटॉप, टैब, साइकिल, स्कूटी, टीवी, गैस सिलेंडर जैसी चीजें और सेवाएं मुफ्त में नहीं मांगी। किसी भी सेवा या वस्तु के मुफ्त वितरण की मांग को लेकर देश में कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन हमारे राजनेता हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए जनता को मुफ्तखोर बनाने पर तुले हैं।

राजनीतिक दल और नेता राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्रों में वस्तुएं और सेवाएं निशुल्क देने, ऋण माफ करने और बिना काम किए ही नकद धन राशि देने जैसे लोक लुभावन वादे करते हैं और जीतने के बाद के बाद सत्ता में बने रहने के लिए इन मुफ्त योजनाओं को लागू करते हैं। आमतौर पर इन योजनाओं के पीछे कोई दीर्घकालिक आर्थिक योजना नहीं होती। ऐसी योजनाएं कुछ समय तो जनता को राहत देती हैं, लेकिन एक अंतराल के बाद ये योजनाएं अर्थव्यवस्था पर बोझ और अंततः जनता के लिए घातक बन जाती हैं। इन योजनाओं ने देश के कई राज्यों के बजट घाटे को चिंताजनक स्थिति में डाल दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऐसी योजनाओं ने श्रीलंका और वेनेजुएला को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया है कि मुफ्त योजनाओं को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश या नीति बनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 'चुनाव आयोग ने इस मामले में समय रहते कदम उठाए होते तो शायद कोई भी राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं के वादे करने की हिम्मत नहीं करता। इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दल इस पर बहस नहीं करना चाहेगा। कुछ वरिष्ठ नौकरशाहों ने राज्य सरकारों की ओर से दी जा रही मुफ्त सुविधाओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी दी है कि ये योजनाएं देश को श्रीलंका जैसी आर्थिक आपदा की ओर धकेल सकती हैं।

भारत में मुफ्त योजनाओं की शुरुआत

वर्ष 1967 में देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, तब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के समय द्रमुक ने एक रुपए में डेढ़ किलो चावल देने का वादा किया। इस वादे के दम पर द्रमुक ने तमिलनाडु से कांग्रेस का सफाया कर दिया। बाद में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने मतदाताओं को मुफ्त साड़ी, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन सेट आदि देने का वादा कर इस संस्कृति को व्यापक विस्तार दिया। साल 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। नारे के साथ ही उन्होंने मुफ्त सुविधाएं और सब्सिडी देने की शुरूआत की। इसके बाद 1980 और 1990 के दशक के आते आते कई राज्य सरकारों ने मुफ्त बिजली, पानी और अनाज देने जैसी योजनाएं शुरु कर दी। अभिनेता एनटीआर ने 1982 में तेलुगुदेशम पार्टी (टीडीपी) की स्थापना कर आंध्र प्रदेश में मुफ्त मिड डे मील, दो रुपए किलो चावल और बिजली पर अनुदान जैसी योजनएं शुरू करने के वादे किए। इन योजनाओं की बदौलत वे चुनाव जीत गए। धीरे-धीरे मुफ्त योजनाओं का दायरा विस्तृत होता गया। राज्यों ने अनुदान, अनाज, स्वास्थ्य और शिक्षा से आगे बढ़ते हुए लैपटॉप, साइकिल, टीवी मुफ्त में देने की योजनाएं शुरू कर दी।

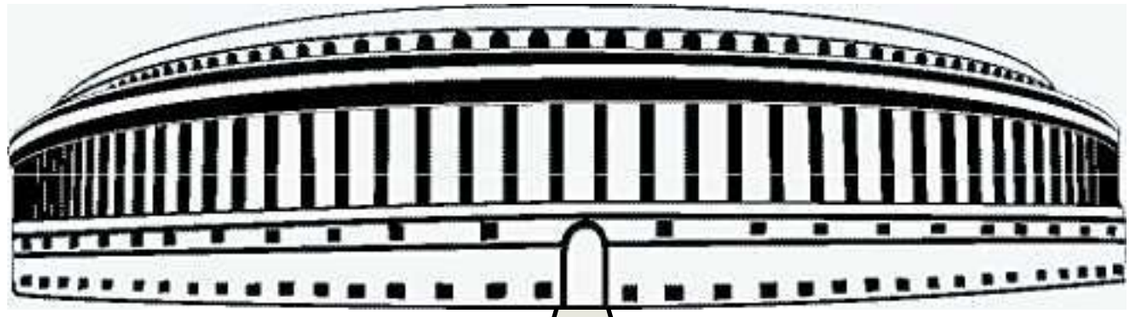

मुफ्त योजनाओं के प्रभाव... विशेषज्ञ कहते हैं कि मुफ्त योजनाएं लक्षित और टिकाऊ हों, किसी समूह की उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक विषमता दूर करने, औद्योगिक विकास को गति देने, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, स्वास्थ्य सेवाओं को सब के लिए सुलभ बनाने जैसे लोक कल्याण कारी उद्देश्यों को लेकर बने तो ये आर्थिक विषमता को दूर करने, विकास को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

सकारात्मक प्रभाव... मुफ्त योजनाओं से समाज के कमजोर वर्गों को तत्काल राहत मिलती है, मुफ्त अनाज या बिजली जैसी सुविधाएं उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। मुफ्त सिलेंडर, शौचालय, राशन आदि से महिलाओं और ग्रामीण वर्ग को विशेष राहत मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में देकर समाज के पिछड़े वर्गों को भी विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। मुफ्त योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की क्रय शक्ति बढाती है, जिससे उपभोग में वृद्धि होती है, बाजार में मांग बढ़ती है। इससे अर्थ व्यवस्था को गति मिलती है।

नकारात्मक प्रभाव... बिना किसी लक्ष्य के, हर आर्थिक वर्ग के लोगों को बिना किसी ठोस कारण के प्रदान की जाने वाली मुफ्त योजनाएं राष्ट्र पर आर्थिक बोझ बनकर राजस्व घाटे को बढ़ाती हैं। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है और देश को आर्थिक बदहाली का शिकार बनाती है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मुफ्त योजनाओं का चलन ज्यादा है। ये राज्य बढ़ते राजकोषीय घाटे से जूझ रहे हैं। नीति आयोग का मानना है कि जिन राज्यों में मुफ्त योजनाओं का चलन ज्यादा है वे राज्य ऋण के जाल में फंसे रहते हैं। राज्य का आर्थिक ढांचा कमजोर हो जाता है।

मुफ्त योजनाओं पर होने वाले खर्च से निपटने के लिए करों में बढ़ोतरी करनी पड़ती हैं, यह कर भार निजी क्षेत्र और उद्योगों को वहन करना पड़ता है। इससे निवेश में कमी आ सकती है और रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं।

यदि मुफ्त योजनाएं उत्पादन बढ़ाने की बजाय केवल उपभोग को बढ़ावा देने लगे तो मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। यह असंतुलन महंगाई बढ़ने का कारण बनता है।

मुफ्त योजनाएं मानसिकता पर गहरा असर डालती है। लगातार मुफ्त सुविधाएं मिलने से "आश्रित मानसिकता" पनपती है जो आत्मनिर्भरता में कमी, श्रम और उत्पादकता में गिरावट का कारण बनती है।

दूषित करती है लोकतंत्र को

चुनाव जीतने के लिए बनने वाली लोक लुभावन मुफ्त योजनाएं लोकतंत्र को दूषित करती है। बिना योजना के मुफ्त योजनाओं के वादे करना मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है। इसलिए ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा हैं और लोकतंत्र को दूषित करती है।

अर्थव्यवस्था के लिए संकट

इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलप मेंट (आईएसआईडी) के निदेशक नागेश कुमार का मानना है कि ''मुफ्त योजनाएं राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति के लिए नुकसानदायक हैं। जैसा कि श्रीलंका के मामले में देखा गया, राजकोषीय लापरवाही हमेशा संकट की ओर ले जाती है।'' बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुलपति एन.आर. भानुमूर्ति कहते हैं कि मुफ्त योजनाएं राज्यों में पहले से ही बिगड़ती सार्वजनिक ऋण की स्थिति को और बिगाड़ सकती हैं

कानून की जरूरत

वरिष्ठ अधिवक्त एस. सुब्रमण्यम बालाजी ने मुफ्त उपहार के बांटे जाने के खिलाफ 2013 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस पी. सतशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान उपहार की बढ़ती राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए कानून की आवश्यकता जताई। कोर्ट ने माना कि उपहार बांटने से मतदाता और चुनावी प्रक्रिया पर असर होता है। इससे दोनों प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह राजनीतिक पार्टियों से चर्चा कर चुनावी घोषणा पत्रों के लिए प्रभावी दिशानिर्देश तय करे।

मुफ्त योजनाओं से बदहाल हो गया श्रीलंका

पड़ोसी देश श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के साथ-साथ मुफ्त योजनाएं इस देश की आर्थिक बदहाली का एक प्रमुख कारण है। देश में पर्याप्त आर्थिक संसाधन न होने के बावजूद जारी की गई मुफ्त योजनाओं से देश कर्ज के दलदल में फंस गया। देश का वो हाल किया कि लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। श्रीलंका कभी दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। वर्ष 2009 से 2015 तक का समय श्रीलंका का स्वर्णिम काल माना जाता है। सन् 2019 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान गोटबाया राजपक्षे ने जनता को लुभाने के लिए टैक्स कम करने का वादा किया। सत्ता में आने के बाद गोटबाया सरकार ने करों में भारी छूट प्रदान कर दी। सरकार ने किसानों को खाद का निशुल्क वितरण किया। बिजली और ईंधन पर भारी अनुदान दिया गया। आयकर में छूट दी गई, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की गई। सालों तक किसानों को मुफ्त खाद, आम जन को बिजली और ईंधन पर सब्सिडी, करों में भारी छूट जैसी योजनाओं से फौरी तौर पर जनता को राहत मिली, मगर सरकारी खजाना खाली हो गया। सरकार कर्ज में डूब गई। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया, जिससे अनाज, तेल और दवाओं का आयात प्रभावित हुआ व महंगाई बढ़ने लगी। अनाज, गैस, पेट्रोल जैसी जरूरी पदार्थ दुर्लभ हो गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा जैसी जरूरी सेवाओं पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे।

ब्याज चुकाना हुआ मुश्किल... राजकोषीय घाटा पूरा करने और जरूरत की चीजों के आयात के लिए श्रीलंका ने अन्य देशों से कर्ज लेना शुरू किया। जो इतना बढ़ गया कि ब्याज चुकाना मुश्किल हो गया। इसे न चुकाने पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने श्रीलंका को अस्थिर घोषित करना शुरू कर दिया, जिससे देश का विकास अवरुद्ध हो गया। ऐसे हालात से कर्ज में डूबी सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी कम करनी पड़ी। मुफ्त सेवाएं बंद से जनता में असंतोष फैलने लगा। गोटबाया राजपक्षे ने 2019 में जो योजनाएं जनता को लुभाने के लिए शुरू की थी, वे 2022 के आते आते जनता के त्रास का कारण बन गई। अप्रेल 2022 में देश भर में लाखों लोग विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले वे मालदीव, फिर सिंगापुर गए और 13 जुलाई 2022 को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया।

वेनेजुएला भी हुआ बर्बाद

दक्षिण अमरीकी देश वेनेजुएला में तेल के विशाल भंडार है। इसकी गिनती अमीर देशों में हुआ करती थी। जनता खुशहाल थी। तेल से होने वाली आय पर निर्भर इस देश की सरकार ने बहुत सी लोकलुभावन मुफ्त योजनाएं शुरू की। इनके चलते देश की अर्थ व्यवस्था का वो हाल हुआ कि रोज़गार, भोजन और जीवन की मूल सुविधाओं की कमी के चलते 70 लाख लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग गए। इसे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पलायनों में गिना जाता है।

1999 से 2013 तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे ह्यूगो शावेज़ क्रांतिकारी नेता थे। उनकी नीतियों को 21वीं सदी के समाजवाद के रूप में जाना जाता है। ह्यूगो शावेज़ और उनके बाद आए निकोलस मादुरो ने तेल से होने वाली आय को ठोस योजना और दीर्घकालीन वित्तीय प्रबंधन के बिना ही समाज कल्याण की मुफ्त योजनाओं पर खर्च करना शुरू किया। इससे आम लोगों को कुछ समय के लिए तो राहत मिली मगर कालांतर में देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई।

दरअसल सन 2000 से 2012 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें काफी ऊंची थी। सरकार को तेल से भरपूर राजस्व मिल रहा था। इस दौर में जनता को बिजली और पेट्रोल लगभग मुफ्त मिल रहे थे। मकान और राशन रियायती दरों पर दिया जा रहा था। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क कर दी गई। इन योजनाओं से तात्कालिक तौर पर तो जनता को राहत मिली। गरीबी कम हुई और साक्षरता का प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन तेल की कीमतों में गिरावट आते ही ये योजनाएं सरकार पर बोझ बन गई। सरकारी खर्च और राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा। सरकार के पास डॉलर खत्म हो गए। ज़रूरी दवाइयां, खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का आयात बंद हो गया। महंगाई बढ़ने लगी। दैनिक जरूरत की चीजों के दाम हर हफ्ते कई गुना बढ़ने लगे और 2018 तक आते आते महंगाई दर दस लाख फीसदी से भी अधिक हो गई। सरकार ने नोट छापने शुरू कर दिए। इससे मुद्रास्फीति बढने लगी। नोट इतने हो गए कि अब उनका लेनदेन गिनने के बजाय तौल कर किया जाने लगा। एक ब्रेड खरीदने में करोड़ों बोलिवर लगते थे। भोजन और जीवन की मूल सुविधाओं के अभाव के चलते जनता देश छोड़कर भागने लगी और वेनेजुएला की लोकलुभावन मुफ्त योजनाएं दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक पलायन का कारण बन गई।

प्राचीन भारत और रोम में भी चलती थी मुफ्त योजनाएं

प्राचीन भारत में और रोम में भी राजा महाराजा मुफ्त योजनाएं चलाते थे। ये योजनाएं कल्याणकारी एवं सार्वजनिक हित के लिए चलाई जाती थी। इन योजनाओं को राजधर्म माना जाता था। ये धर्म और सामाजिक दायित्व से प्रेरित हुआ करती थी। वहीं प्राचीन रोम में मुफ्त योजनाएं राजनीतिक नियंत्रण का साधन थी। प्राचीन भारत में राजा और सम्पन्न व्यक्ति अन्नक्षेत्र खोलते थे। जहां गरीबों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था होती थी। मंदिरों और मठों में भी अन्नक्षेत्र खोले जाते थे। धर्म पर आधारित राज व्यवस्था में रोगियों, वृद्धों, विधवाओं, अतिथियों एवं ब्राह्मणों की सेवा करना राजा का कर्तव्य माना जाता था। राजा इन वर्गो को भोजन, वस्त्र औषध आदि प्रदान करता था। चिकित्सा व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी हुआ करती थी।

अशोक कालीन शिलालेखों से पता चलता है कि उस काल में मनुष्यों और पशुओं के लिए औषधालयों की स्थापना राज्य की ओर से की जाती थी। जन कल्याण के लिए कुएं, सराय, सड़कें और वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाते थे। गुप्त काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा छात्रों को भोजन व आवास की सुविधा निशुल्क दी जाती थी। यह व्यवस्थाएं राज्य, दानी व्यक्तियों, या राजा के संरक्षण में संचालित होती थी।

महाजनपद काल और उसके बाद तक प्राकृति आपदाओं एवं सूखा, अकाल जैसी परिस्थितियों में राजा की ओर से राहत कार्य चलाए जाते थे। इन राहत कार्यों के तहत अन्न वितरण तथा प्रजा के कर माफ करने जैसे कार्य किए जाते थे। अकाल के दौरान सड़क एवं तालाब आदि के निर्माण में श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था।

वहीं, रोमन साम्राज्य में आम जनता, विशेषतः गरीब वर्ग को राहत और सहारा देने, जनता को रिझाने और विद्रोह को दबाने के लिए मुफ्त भोजन और मुफ्त मनोरंजन योजनाएं चलाई जाती थी। लगभग 123 ईसा पूर्व गरीबों को भूख से बचाने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रोम में अनाज वितरण योजना चालू की गई। इस योजना के तहत गरीब नागरिकों को सस्ती दरों पर या मुफ्त में गेहूं दिया जाता था। सम्राट अगस्तस और क्लॉडियस के काल में इस योजना के तहत लगभग दो लाख रोमवासियों को नियमित रूप से मुफ्त अनाज मिलने लगा।

पूरे रोम में हज़ारों सार्वजनिक स्नानघर बनाए गए, जिनमें गरीब और अमीर सभी निःशुल्क स्नान करते थे। सार्वजनिक स्नानघर सामाजिक मेलजोल और आराम का जरिया होते थे। अकाल के दौरान गरीब जनता को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य की ओर से सड़कों, पुलों, इमारतों आदि का निर्माण करवाया जाता था।

मुफ्त योजनाओं के प्रकार

देश में इस समय अनेक प्रकार की मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। कुछ गरीबों और किसानों जैसे वर्गों को राहत देने के लिए हैं तो कुछ केवल राजनीतिक लाभ के लिए चलाई जा रही है।

सीधी नकद सहायता: सरकार की ओर से गरीबों, किसानों नकद राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे उनके खातों में जमा होती है।

निशुल्क सेवाएं: ऐसी योजनाओं के तहत जनता को बिजली, पानी, गैस, परिवहन जैसी सेवाएं निशुल्क प्रदान की जा रही है।

मुफ्त सामग्री वितरण: आम जनता को, विद्यार्थियों को लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, टेलीविजन, टैब जैसी वस्तुएं निशुल्क प्रदान की जाती है।

निशुल्क सेवा: केंद्र व राज्य सरकारें जनता शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं निशुल्क प्रदान करती है।

कर्जमाफी: सरकारें समय समय पर गरीब किसानों, छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज माफी की घोषणा करती है।

अनुदान: अनाज या किसी खास वस्तु का उत्पादन बढ़ाने या औद्योगिक विकास के लिए दिया जाता है।

इसलिए हुई शुरूआत... ▪ अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा के समय जनता को राहत प्रदान करने के लिए। ▪ अनाज का उत्पादन बढाने के लिए ▪ औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ▪ गरीब और वंचित जनता को भुखमरी से बचाने के लिए ▪ आर्थिक विषमता दूर करने के लिए ▪ जनता को साक्षर करने के लिए ▪ स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए।

सरहदों की निगहबानी में AI का दमखम

प्रो. (डॉ). सचिन बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार

स्काईबॉर्ग प्रोजेक्ट के तहत स्वायत्त ड्रोन विकसित किए गए हैं। चीन ने भी जहां AI से लैस सीएच—7 ड्रोन विकसित कर लिए हैं। साथ ही स्वचालित AI रोबॉट्स ही नहीं, युद्ध में रणनीतियों का पूर्वानुमान लगाने वाले सिमुलेशन AI सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने 2023 के रक्षा बजट में 261 बिलियन डॉलर में सर्वाधिक खर्च AI पर किया।

किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात सैनिक अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं। जैसे जलवायु, तापमान, विषम परिस्थितियां, दुश्मन पर लगातार निगरानी, जमीन में छिपी लैंड माइंस, घात लगाए घुसपैठिए, औचक हमले और हवाई कार्रवाई आदि। ऐसे में चाहे जितनी भी सतर्कता क्यों न बरती जाए, किसी भी एक तरफा हमले या घात लगाकर की गई कार्रवाई में जान—माल की क्षति हो ही जाती है। लेकिन अब सरहदों की निगहबानी के लिए पूरी दुनिया ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नित नए समाधान व उपाय खोज रही है। इसमें AI आधारित स्वायत्त हथियार प्रणाली, निगरानी यंत्र, बारूदी सुरंग डिटेक्टर सहित AI संचालित बख्तरबंद वाहन ही नहीं टैंक, मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान और खोजी रोबो—डॉग्स विकसित किए जा रहे हैं।

दुनिया के दूसरे देशों पर नजर डालें तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI पर अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना स्टारगेट पर 500 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा करके, AI पर एकाधिकार की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। हालांकि अमेरिका का रक्षा विभाग प्रोजेक्ट मेवन के तहत ड्रोन से प्राप्त वीडियो का AI विश्लेषण करते हुए खुफिया डाटा निर्मित करता है। वहीं 2018 में जेएआइसी यानि जॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित कर AI एकीकरण की प्रक्रिया को अभियान का रूप दिया गया और स्काईबॉर्ग प्रोजेक्ट के तहत स्वायत्त ड्रोन विकसित किए गए हैं। चीन ने भी जहां AI से लैस सीएच—7 ड्रोन विकसित कर लिए हैं। साथ ही स्वचालित AI रोबॉट्स ही नहीं, युद्ध में रणनीतियों का पूर्वानुमान लगाने वाले सिमुलेशन AI सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने 2023 के रक्षा बजट में 261 बिलियन डॉलर में सर्वाधिक खर्च AI पर किया। रूस की बात करें तो उसने भी 2025 तक 400 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। साथ ही AI आधारित उपग्रह निगरानी प्रणालियों को ईजाद कर लिया है। इसके अलावा यूरान—9 नामक स्व-निर्देशित सैन्य वाहन व टैंक का विकास किया है। इजराइल का रुख करें तो इस बार युद्ध में उसके 'आयरन डोम'' के चमत्कार समाचारों में छाए रहे। उसके मिसाइल डिफेंस AI सिस्टम, हमलावर रॉकेट और सरहदों में दाखिल होने वाली मिसाइलों को नेस्तनाबूद करने में बेहद सफल रहे।

गौरतलब है कि पिछले साल ही हमारी सेना ने अखनूर में AI संचालित मानव रहित वाहन की मदद से आतंकियों का खात्मा किया था। इस मॉडल

खास बात यह है कि हमारे देश में भी सेना ने बहुत पहले ही AI को 'आर्मड विद इंटेलिजेंस' की सोच के साथ अपनाते हुए एक रणनीति के तहत युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया था। 2018 में रक्षा क्षेत्र में AI के इस्तेमाल पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। वहीं 2019 में 'सप्त शक्ति' नामक AI सेमिनार के जरिए हिसार में मंथन किया गया। इसी प्रकार 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस के तहत एक प्रदर्शनी आयोजित करते हुए AI आधारित 75 तकनीक और सैन्य उपकरणों को लॉन्च किया गया। जिन्हें डीआरडीओ और डिफेंस पीएसयू द्वारा पहले ही जांचा परखा जा चुका था। इसी प्रकार दिसंबर में बेंगलुरु में भारतीय सेना AI इनक्यूबेशन सेंटर यानी आइएएआइआइसी की शुरुआत की जो सेना को अत्याधुनिक AI तकनीक से लैस करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानि देश की रक्षा व युद्ध को लेकर आधुनिकीकरण की कवायद सतत रूप से जारी है।

ऑपरेशन ने जहां सैनिकों को छिपे हुए खतरे से आगाह किया, वहीं आतंकियों की गोलीबारी से होने वाली क्षति से भी बचाया। यह तो एक उदाहरण भर है, लेकिन यह भी जानना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारी एक बंदूक ही सैनिक को दुश्मन की गतिविधि पर अलर्ट करते हुए टारगेट की दूरी, सही निशाना और सही समय बताते हुए स्वतः दुश्मन को ढेर कर दे। जी हां, यह संभव हो गया है। हमारी सेना ने AI का उपयोग करते हुए स्मार्ट स्कोप AI फॉर टारगेट एक्विजिशन एंड एंगेजमेंट नामक डिवाइस विकसित किया है, जो किसी भी हथियार को सटीक मारक क्षमता देने में सक्षम है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह भी है कि कम से कम गोली खर्च और जान की सलामती को आश्वस्त करता है। वहीं एडीबी यानि आर्मी डिजाइन बोर्ड के एक्सपर्ट द्वारा सरहदों पर तैनात किए जा रहे साइलेंट संतरी ऐसे रोबोटिक रेल माउंटेड डिवाइस हैं जो दुश्मन, आतंकी या घुसपैठियों की तुरंत सूचना देकर सेना को सचेत करने में सक्षम हैं। खास बात यह भी है कि यह AI अलर्ट सिस्टम फेस डिटेक्शन के जरिए अपने देश के सैनिक और बाहरी तत्व की परख कर सकता है। इसी प्रकार संहारक लैंड माइंस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने AI पावर्ड अनमैन्ड व्हीकल भी तैयार कर लिए हैं जो बारूदी सुरंगों की शिनाख्त ही नहीं, उसे निष्क्रिय करने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं प्रिज्म यानी प्रोएक्टिव रियल टाइम इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस मॉनिटरिंग सिस्टम तो बॉर्डर पर मीलों दूर की बनाई वीडियो की गुणवत्ता को AI तकनीक से बढ़कर, असफ्ट से अधिक स्पष्ट करने में कामयाब रही है।

कुल मिलाकर आधुनिक वारफेयर बहुत तेजी से बदल रहा है, जिसमें सैन्य कार्यप्रणाली और उपकरणों को नवीनतम तकनीक से बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण, निगरानी, लॉजिस्टिक्स, यूएवी, लीथल आटोनोमस वेपन सिस्टम सहित घातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली व विविध प्रकार की रोबॉटिक्स शामिल है। वहीं युद्ध का दायरा भी बदल गया है। जैसे कि अब हमें सेटेलाइट की सुरक्षा, देश में हर तरह के डिजिटल यंत्रों को संरक्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूर्वनियोजित विध्वंस से बचाने के लिए भी गहन पड़ताल और सुरक्षा यंत्र विकसित करने होंगे। इस मामले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान उल्लेखनीय है कि 'जो AI सेक्टर को काबू में रखेगा, वही दुनिया पर राज करेगा।' इसके मद्देनजर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल ही नहीं, भारत भी अपना AI दमखम आजमाने को तैयार है।

HISTORY OF SIR PRATAP SCHOOL VIS-A-VIS ITS JOURNEY TO

SIR PRATAP VIDHI MAHAVIDYALAY

Munshi Shubhlal ji
Pioneer & Philanthropist

Hon'ble Justice
N. N. MATHUR (Chief Patron)
Former Vice Chancellor
NLU Jodhpur

Girish Mathur
Founder of Sir Pratap Vidhi
Mahavidyalay

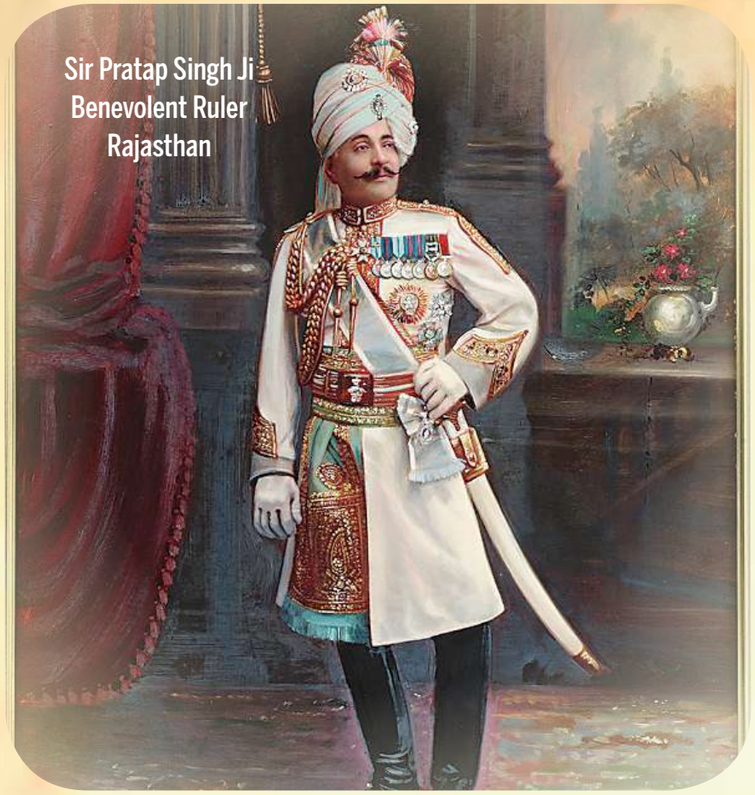

Sir Pratap Singh Ji
Benevolent Ruler
Rajasthan

Established as an Anglo Vernacular School in year 1887 by Kayastha Community of Jodhpur. Land was donated by late Munshi Shubh Lal ji, a philanthropist who envisioned the need of education for overall development of Kayastha Community as also for the society at large.

In year 1890, gained the status of Middle School adding two new Hindi Pathshalas six years later.

The School was run on grants by State and some private donations.

Ever since its inception the school has retained a secular character imparting education to all sections of society irrespective of caste/sub caste etc. Many of Students belonging to different castes like Brahmins, Muslims, Kayastha, Rajputs and other backward castes/sections/classes passing out from the school significantly contributed to National struggle for freedom and also made illustrious careers in public life. Mames like Late Nathuram Mirdha, Late Ramniwas Mirdha, Late Barkatullah Khan (also Ex. CM of Rajasthan) and many others are held in high esteem for their active role in freedom struggle.

Lots of more alumni have brought laurels to Pratap School.

Shri Ashok Mathur an alumnus of "Sir Pratap School" is an eminent jurist of national & international repute a matter of great pride for school. He was Chief Justice of Madhya Pradesh, West Bengal and subsequently made it to Hon'able Justice of Supreme Court, Post retirement, Government of India harnessed his services in refurbishing judicial system for defence forces. He shot into public prominence as chairman of 7th pay commission, a highly prestigious and trusted assignment demanding high degree of financial & economic prudence. He headed many enquiry commission appointed by Govt. of India.

Further to the list of Alumni are:-

Late PPS Mathur - 1st Director Rajasthan Ayurvedic college.

Mr. Kuldeep Ranka - Senior IAS Officer.

Mr. Rajendra Gehlot – Former State Minister and JDA Head & many more in the list others with illustrious carriers.

Pratap School has a chequered journey facing financial constraints at different periods of time due to stoppage of Government grant and private financial support. Each time members of Kayastha Community generously contributed individually and collectively to save the situation.

In year 1919, Dalpat memorial 'Science Block' was inaugurated in the royal presence of 'Sir Pratap Singh Ji' who was pleased with performance of school and granted Rupees 5000 towards welfare of students and extension of school building in view of increasing students' strength. The School was named after Regent 'Sir Pratap Singh Ji' in his honour recognizing his patronizing support.

In year 1920, it was recognized as 'High School' by Allahabad University thus holding the pride and honour of being only and first private High School in Marwar.

A few affluent and generous people of Kayastha Community had added more glory to the history by organizing two magnificent events in the honour of Yuvraj Sumer Singh Ji, first on his birth and second on his succession to royal throne in March 1916. Both events were organized on large scale in the premises of school building lending a golden pages to the history of School. The Royal family was much pleased with hospitality and exuberance of Kayasthas, Sir Pratap Singh Ji praised efficient functioning of school and its quality standard and gave an inspiring speech which was published in Marwar Gazette on 18 March 1916.

Names of organizers were Shri Mukund Ji and Shri Chatturbhuj Ji. Shri Mukund Ji also donated land for garden.

New School building was constructed and gifted by Mr. Vijay Karan in memory of his father late Munshi Indramal Ji in year 1938. Likewise many names appear in the history belonging to Kayastha as also from other well as other community who also contributed for survival of the school.

With efflux of time 'Kayastha Samaj Management' was established to ensure proper functioning of school.

Subsequently a separate body 'Nav Shiksha Samaj' was created in year 1956-57 to look after academic activities of 'Sir Pratap School'. 'Sir Pratap Mahavidyalaya' is its latest achievement-a brilliant intellectual assets indeed.

"Sir Pratap Vidhi Mahavidyalaya is a momentous event marking the dawn of a new era in academic history of Nav Shiksha Samaj. It has emerged from fusion of efforts and enterprise put in by Shri Girish Mathur President of Na Shiksha Samaj and his entire team our heartiest compliments to them. Sir Pratap Vidhi Mahavidyalaya is going beyond legacy of bookish learning and adopt latest teaching methodologies without rigidly confining to boundary of the core subject but also provide for interdisciplinary interface. Students are encouraged to develop logical and analytical skills imperative to making successful lawyers and judges of tomorrow oriented towards social welfare. Sir Pratap Vidhi Mahavidyalaya is moving ahead with missionary zeal and earns Stellar Brand Value in the academic world in short time."

Our best wishes for progress and prosperity.

Justice N. N. Mathur, (Chief Patron), Former Vice Chancellor, National Law University, Jodhpur

आओ, जोधपुर को और समृद्ध व गौरवशाली बनाएं

जब मैं जोधपुर के विशाल किले मेहरानगढ़ की प्राचीरों को निहारता हूं, जब नीली गलियों की ठंडी हवा मुझे छूती है, तब मैं गर्व से भर उठता हूं— गर्व अपने महान पूर्वजों पर, जिन्होंने मरुस्थल में इस स्वप्न-नगरी को बसाया और उसे दुनिया के मानचित्र पर विशिष्ट स्थान दिलाया।

आज जब हम जोधपुर की स्थापना का पर्व मना रहे हैं, तो मैं श्रद्धा से अपने पूर्वज राव जोधा जी को नमन करता हूं, जिन्होंने सन् 1459 में अपने अद्भुत दृष्टिकोण और अडिग संकल्प से इस नगर की नींव रखी। उनके बाद राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह और मेरे पूज्य पिताश्री महाराजा हनवंत सिंहजी जैसे वीर, दूरदर्शी और कलाप्रेमी शासकों ने इस भूमि की गरिमा को निरंतर बढ़ाया। उनके प्रयास से जोधपुर न केवल राजस्थान का, बल्कि पूरे विश्व का गौरव बना।

जोधपुर का स्थापत्य इसकी आत्मा है। मेहरानगढ़ की प्राचीरों से लेकर पुराने शहर की कलात्मक हवेलियां व उम्मेद भवन पैलेस की भव्यता तक, हर पत्थर गाथाएं कहती है। यहां की जीवनशैली— सहज, गरिमापूर्ण और रंगों से भरी हुई— सच्चे राजस्थानी संस्कारों की परिचायक है। मिर्ची बड़ा और घेवर जैसे व्यंजनों से लेकर माखनिया लस्सी तक, यहां के खानपान ने स्वाद की दुनिया में अलग पहचान बनाई है। जोधपुरी साफा, बंदगला कोट और जोधपुरी बिरजिस आज विश्वभर में फैशन का हिस्सा बन चुके हैं।

जोधपुर की कला, संस्कृति और साहित्य की परम्परा सदियों से समृद्ध रही है। मारवाड़ी भाषा की मिठास, अगणित रचनाकारों की साधना और लोकसंगीत की ऊंची तानों ने हमारी आत्मा को संवारा है। हमारी संगीत परम्परा ने अनेक स्वर-रत्नों को जन्म दिया, जिन्होंने जोधपुर की लोकधुनों को विश्वपटल पर पहुंचाया।

सैन्य दृष्टि से मारवाड़ ने हमेशा वीरता के मानदंड स्थापित किए। हमारे रणबांकुरों ने विदेशी आक्रांताओं से लेकर आधुनिक युद्धों तक में अपना लोहा मनवाया। आज भी जोधपुर सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा योगदान के लिए जाना जाता है।

अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यापार, हस्तशिल्प और पर्यटन ने जोधपुर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। विधि और ज्योतिष के क्षेत्र में भी जोधपुर ने विद्वानों की एक समृद्ध परम्परा को संजोया है। राजनीतिक रूप से हमारे पूर्वजों ने न्यायप्रिय शासन की मिसाल पेश की, और आज भी जोधपुर लोकतांत्रिक चेतना का सशक्त केंद्र बना हुआ है।

खेलों में जोधपुर के सपूतों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। पोलो जोधपुर की ही देन रही है। वहीं, सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में जोधपुर की धरती ने ऐसी पृष्ठभूमियां दी हैं, जिन्होंने सैकड़ों कहानियों को अमर बना दिया।

आज स्थापना के शुभ अवसर पर मैं सिर नवाकर अपने सभी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने स्वप्न, श्रम और तप से इस धरा को अमूल्य बनाया। मैं समस्त मारवाड़वासियों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके परिश्रम, धैर्य और प्रेम व भाईचारे ने जोधपुर को जीवंत और गौरवशाली बनाए रखा।

आइए, हम सब मिलकर अपने पूर्वजों के सपनों के अनुरूप जोधपुर को और भी उज्ज्वल, समृद्ध और गौरवशाली बनाएं। मैं व मेरे परिवार की ओर से समस्त जोधपुरवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ चामुण्डा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे।

–महाराजा गज सिंह
मारवाड़-जोधपुर

आज स्थापना के शुभ अवसर पर मैं सिर नवाकर अपने सभी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने स्वप्न, श्रम और तप से इस धरा को अमूल्य बनाया। मैं समस्त मारवाड़वासियों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके परिश्रम, धैर्य और प्रेम व भाईचारे ने जोधपुर को जीवंत और गौरवशाली बनाए रखा।

एक टूटी पगडंडी से शुरू हुई थी यह यात्रा...

‘जयपुर फुट’ से मिला जीने का हौसला

बलवंत राज मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

‘जयपुर फुट’ केवल रबर और लकड़ी का बना एक कृत्रिम अंग नहीं है। यह मानवता के उन टूटे पांवों के नीचे बिछी वह मिट्टी है, जो उन्हें फिर से खड़ा होने का हौसला देती है। यह वो चप्पल है, जो आत्मसम्मान की खामोश आहट में भी रास्ता ढूंढ लेती है। यह वो लाठी है, जो गिरने नहीं देती, और वो सपना है, जो अंधेरे में भी रोशनी खोज लेता है।

कभी एक टूटी हुई पगडंडी थी, जिस पर न तो कोई साफ़ रास्ता था, न ही उम्मीदों के कोई निशान। यह पगडंडी एक ऐसे घायल इंसान के आंसुओं से भीगी थी — जिसने चलने की चाह तो रखी, पर पांव नहीं थे। और तब कहीं दूर एक दिल धड़क रहा था, जो उस पगडंडी को राह बनाना चाहता था। उस दिल का नाम है— डी.आर. मेहता।

उन्होंने न कोई हथियार उठाया, न कोई आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बस एक सवाल उठाया— “अगर कोई चल नहीं सकता, तो क्या वह जी भी नहीं सकता?”

इस सवाल का उत्तर बना — ‘जयपुर फुट’।

‘जयपुर फुट’ केवल रबर और लकड़ी का बना एक कृत्रिम अंग नहीं है। यह मानवता के उन टूटे पांवों के नीचे बिछी वह मिट्टी है, जो उन्हें फिर से खड़ा होने का हौसला देती है। यह वो चप्पल है, जो आत्मसम्मान की खामोश आहट में भी रास्ता ढूंढ लेती है। यह वो लाठी है, जो गिरने नहीं देती, और वो सपना है, जो अंधेरे में भी रोशनी खोज लेता है।

भारत में जब विकलांगता को कलंक की नजर से देखा जाता था, तब ‘जयपुर फुट’ ने यह सिखाया कि शरीर की कमी आत्मा की शक्ति को नहीं रोक सकती। विकलांग व्यक्ति को सहारा नहीं, सम्मान चाहिए— और आत्मनिर्भरता का अवसर।

भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) की स्थापना जब हुई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाएगी, जो विकलांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करेगी। आज तक 24 लाख से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं— ये नई चाल की रचना, उम्मीद की मरम्मत, और आत्मा की पुनः प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं।

इस यात्रा की एक घटना इतिहास में मानवीयता की मिसाल बन गई है— एक पाकिस्तानी सैनिक ने कहा, “मेरा पैर भारत की गोली से गया, लेकिन भारत ने ही मुझे खड़ा किया।” यह उस सेवा की पराकाष्ठा है, जो सीमाओं से परे, केवल मानवता के नाम पर की जाती है। ‘जयपुर फुट’ को महज़ एक तकनीकी उपकरण कहना न्याय नहीं होगा। यह एक दर्शन है— “Mobility for Dignity” का मंत्र। यह सोच है कि किसी को सहारा देकर नहीं, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाया जाए।

'जयपुर फुट' की सफलता इस बात की मिसाल है कि कैसे स्थानीय संसाधनों और देसी तकनीक से एक ग्लोबल मॉडल बनाया जा सकता है। जहां पश्चिमी देशों में कृत्रिम पैर लाखों रुपए में बिकते हैं, वहीं जयपुर फुट निःशुल्क या बेहद कम लागत में उपलब्ध है— और तकनीकी रूप से कहीं भी कमतर नहीं। इस तकनीक को पहचान दिलाने में बॉलीवुड के अभिनेता कमल हासन से लेकर अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का योगदान रहा है। आज यह तकनीक अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों तक पहुंच चुकी है।

बी.एम.वी.एस.एस. की कार्यशालाएं और विशेष शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं। इन शिविरों में मिलने वाले कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और अन्य उपकरणों ने लाखों लोगों को न केवल नई जिंदगी दी है, बल्कि आत्मविश्वास भी लौटाया है।

जब करुणा और तकनीक का मिलन होता है, तो चमत्कार जन्म लेते हैं — 'जयपुर फुट' इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। यह एक ऐसी तकनीक है, जो गले लगाती है, सहलाती है, और फिर से दौड़ने का सपना देती है। आज जब 'जयपुर फुट' की यात्रा 50 वर्ष पूरे कर रही है, तो यह केवल एक संस्था की वर्षगांठ नहीं, बल्कि करुणा, तकनीक और आत्मबल के त्रिवेणी संगम की वर्षगांठ है। डी.आर. मेहता की दूरदृष्टि, सेवा भावना और संगठन निर्माण की अद्भुत क्षमता ने जो बीज बोया था, वह आज एक वटवृक्ष बन चुका है— जिसकी छांव में लाखों जीवन न सिर्फ संवर रहे हैं, बल्कि नए सपने भी देख रहे हैं।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अध्ययनः 'दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी'

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध सामाजिक शोधकर्ता डॉ. जेम्स हिल्टन द्वारा 1995 में किए गए एक गहन अध्ययन में डी.आर. मेहता को एक विशेष उपमा दी गई— "दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी"। यह उपमा साधारण नहीं थी, बल्कि एक गहरा और प्रेरक अर्थ अपने भीतर समेटे हुए थी— जो उनके समर्पण, सेवा भावना, और समाज के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

यहां "भिखारी" शब्द किसी निर्धनता या गरीबी का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करता है, जो अपनी पूरी जिंदगी समाज की भलाई के लिए अर्पित कर देता है— अपना समय, ऊर्जा और ज्ञान सबकुछ समर्पित कर देता है। मेहता ने कभी भी किसी से व्यक्तिगत लाभ की याचना नहीं की। वे तो सदा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सेवा, समर्पण, और संवेदना की 'भिक्षा' मांगते रहे— ताकि कोई अपाहिज खड़ा हो सके, कोई टूटा हुआ सपना फिर से उड़ान भर सके।

यह उपमा उनके द्वारा किए गए निःस्वार्थ कार्यों और समाज में लाए गए परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रतीक है— जो यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व मांगने में नहीं, देने में होता है।

दीपक की लौ-सा जीवनः डी.आर. मेहता का शब्दचित्र

नब्बे वर्ष की आयु में, जब अधिकांश लोग स्मृतियों की छांव में विश्राम खोजते हैं, डी.आर. मेहता आज भी सेवा के सूर्य की पहली किरण बनने को तत्पर हैं। उनका जीवन एक चिरसंचारी जलधारा की भांति है— न थमता है, न ठहरता। वे उस वटवृक्ष की तरह हैं, जिसकी जड़ें गहराई तक समर्पण में धंसी हुई हैं, और जिसकी छाया ने अनगिनत जीवन को राहत और संबल प्रदान किया है।

प्रशासनिक सेवा में वे एक मूक बांसुरी जैसे रहे— शांत, लेकिन जब भी फूंकी गई, तो समाजहित की स्वर-लहरियां गूंज उठीं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन विरले अधिकारियों में से हैं, जिनकी नीयत, नजरिया, और निष्ठा— तीनों में अद्भुत संतुलन रहा। उन्होंने अपने पद को सिंहासन नहीं, साधना माना। और जब सेवा से निवृत्त हुए, तो वे उस घड़ीदार की भांति निकले जो आज भी समाज के लिए समय गिनता है, राह दिखाता है।

'जयपुर फुट' की कल्पना उनके भीतर उसी क्षण अंकुरित हुई थी, जब उन्होंने एक अपंग युवक को सड़क किनारे गिरते हुए देखा। उस क्षण वे पिघलते मोम की तरह हो गए— भीतर की संवेदना ने उन्हें तपाया, और सेवा का दीपक बनकर उन्होंने रोशनी दी उन तमाम जिंदगियों को, जो जीवन की दौड़ से सिर्फ इसलिए बाहर हो गई थीं, क्योंकि उनके पास पैर नहीं थे। उनकी सोच किसी प्राचीन लिपि की तरह है— सरल, फिर भी गूढ़। वे बोलते कम हैं, लेकिन उनके कर्म स्वयं मुखर हैं— जैसे कोई सन्त बिना उपदेश के, केवल जीवन जीकर शिक्षा दे। उनकी दृष्टि में सेवा कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि करुणा की साधना है।

डी.आर. मेहता एक ऐसा दीपक हैं जो स्वयं जलता है, और दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। वे उम्र की किताब में भले ही नब्बेवें पृष्ठ पर हों, लेकिन उनका उत्साह आज भी पहले अध्याय-सा ताजा है। वे हमें सिखाते हैं कि सेवा का कोई रिटायरमेंट नहीं होता— यदि हृदय में संवेदना की ज्वाला जल रही हो, तो जीवन का हर क्षण उपयोगी बन सकता है। वे समय के उस संतुलित पलड़े की तरह हैं— जिसकी एक ओर अनुभव का भार है, तो दूसरी ओर सेवा की परिपक्वता।

'पदक- पुरस्कार की चाह नहीं, सेवा ही मेरा जीवन'

कुछ लोग इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं, और कुछ इंसानियत की रगों में बहते हैं। डी.आर. मेहता ऐसा ही एक नाम हैं— जिनके हाथ में कलम है, पर दिल में करुणा का क़लमघर भी धड़कता है। भारत के प्रशासनिक गलियारों में जहां वे नीतियों के शिल्पकार रहे हैं, वहीं 'जयपुर फुट' के ज़रिए वे लाखों ज़िंदगियों में आज भी आशा की रीढ़ रोपते आ रहे हैं।

उनके द्वारा प्राप्त पद्म भूषण महज़ एक सम्मान नहीं, उस हर कृतज्ञ पांव की गूंज है, जो आज ज़मीन पर आत्मविश्वास से चल रहा है। 'राजस्थान रत्न' उनके लिए राज्य की मिट्टी की ओर से झुकी हुई कृतज्ञता है— जैसे मरुधरा अपने बेटे को आशीर्वाद में मोतियों की माला पहना रही हो। 'भारत निर्माण पुरस्कार' उनके उन कदमों की चमक है, जो गांवों की धूल भरी पगडंडियों पर भी उजाले की चादर बिछा रहे हैं। लेकिन यह रोशनी केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। जब CNN-IBN और CNBC-TV18 जैसे मंच उन्हें सम्मानित करते हैं, तो लगता है जैसे दुनिया भारत के उस कोने को देख रही है, जहां सेवा और सरलता साथ-साथ चलते हैं।

- डॉ. पॉल ब्रांड अवॉर्ड, टेक म्यूज़ियम अवॉर्ड, रोटरी इंटरनेशनल का 'Service Above Self' सम्मान– ये सब उनके उस अंतर्निहित मंत्र के साक्षी हैं: "दूसरों के लिए जियो, यही असली जीवन है।"
- Forbes Asia उन्हें "Heroes of Philanthropy" कहता है, लेकिन जिन ज़रूरतमंदों को वे कृत्रिम अंग पहनाते हैं, उनके लिए वे हीरो नहीं— फरिश्ते हैं।
- डी.आर. मेहता की उपलब्धियां किसी दीवार पर टंगे तमगों की कतार नहीं हैं, बल्कि वे उन गली-कूचों में दौड़ते बच्चों की हंसी हैं, जो कल तक एक पैर पर ज़िंदगी को घसीट रहे थे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि पद, पुरस्कार और प्रसिद्धि से परे भी एक सेवा-संसार है, जहां दिल की धड़कन ही सबसे बड़ी भाषा बन जाती है।

राष्ट्रीय संस्थानों से बनी वैश्विक पहचान

डॉ. मनीष शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर, निफ्ट, जोधपुर

जोधपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नगरी के रूप में हो गई है। इन संस्थानों में प्रमुख रूप से आईआईटी, एम्स, एफडीडीआई, इग्नु, आईआईएचटी, एनएलयू, निफ्ट प्रमुख है। भारत सरकार के ये संस्थान आज टेक्नोलॉजी, मेडिकल, डिजाइन, मैनेजमेंट, फैशन एजुकेशन, फुटवियर, लॉ, रिसर्च एंड डवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंसलटेंसी और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्रों में बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस और प्रोसेस में अहम रोल अदा कर रहे हैं।

पश्चिमी राजस्थान अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन यहां विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आ जाने से जोधपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नगरी के रूप में हो गई है। इन संस्थानों में प्रमुख रूप से आईआईटी, एम्स, एफडीडीआई, इग्नु, आईआईएचटी, एनएलयू, निफ्ट प्रमुख है। भारत सरकार के ये संस्थान आज टेक्नोलॉजी, मेडिकल, डिजाइन, मैनेजमेंट, फैशन एजुकेशन, फुटवियर, लॉ, रिसर्च एंड डवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंसलटेंसी और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्रों में बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस और प्रोसेस में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जोधपुर में इन संस्थानों में करीब 20 राज्यों के स्टूडेन्ट्स अपना करियर संवार रहे हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर

आईआईटी के जोधपुर में स्थापित होने के साथ दुनियाभर में इस शहर की चर्चा होने लगी। किसी शहर में बहु-विषयक दृष्टिकोण के साथ परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाला एक भविष्य-संचालित संस्थान होना सौभाग्य की बात होती है। यहां संयुक्त अनुसंधान/परियोजनाओं, आईपीआर विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता/स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम किया जा रहा है। यहां दुनिया भर से शिक्षाविदों, शोध संस्थानों, व्यावसायिक संगठनों, नागरिक समाज, सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावशाली साझेदारी बनाने के लिए एक कुशल मंच तैयार किया गया है, जिससे युवाओं को तकनीक के क्षेत्र में नवाचारों में अधिक विकल्प मिल सकें। यहां के इनोवेशन की आज दुनियाभर में चर्चा है। यह संस्थान लंबे समय से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) जोधपुर

इस संस्थान को भारत के शीर्ष लॉ स्कूलों में से एक है। 1999 में अपनी स्थापना के बाद से एनएलयू ने ज्ञान की मौजूदा सीमाओं को आगे बढ़ाने और चुनौती देने के उद्देश्य से एडवोकेट और कानूनी विद्वान तैयार करने का प्रयास किया है। यह संस्थान भारत के सभी कोनों से विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से आने वाले शीर्ष गुणवत्ता वाले छात्रों को आकर्षित करता है। इस संस्थान से पास होने वाले छात्र भारत और विदेशों में शीर्ष लॉ फर्मों में काम करते हैं, न्यायाधीय बनते है, कुछ अदालतों में अभ्यास करते हैं और कुछ कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाते हैं। यहां स्नातक कोर्स में बीएएलएलबी और बीबीए एलएलबी संचालित है और कॉर्पोरेट लॉ, आईपीआर लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड पब्लिक लॉ में एलएलएम संचालित है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर

यह एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है, जो चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। संस्थान की शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाएं इसे एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनाती हैं। एम्स जोधपुर का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है और यह संस्थान इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। यहां एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालित है। इसके अलावा पीजी पाठ्यक्रम, डीएम/एम सीएच कार्यक्रम, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम, संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान पाठयक्रम, आईआईटी— एम्स संयुक्त कार्यक्रम और पीएचडी कोर्स संचालित है। यहां बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स और पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री भी कराई जाती है। इस प्रकार जोधपुर की मेडिकल शिक्षा में इस संस्थान से ऐतिहासिक क्रांति आई है।

फुटवियर डिजाइन एंड डवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एफडीडीआई)

एफडीडीआई एक प्रमुख शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थान है, जो फुटवियर और उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, खुदरा और फैशन मर्चेंडाइज़ और फैशन डिजाइन क्षेत्रों के विकास और वृद्धि के लिए समर्पित है। एफडीडीआई की पूरे भारत में उपस्थिति है और देश भर में इसके 12 अत्याधुनिक परिसर हैं। इसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सुविधाएं हैं। एफडीडीआई अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च स्तरीय प्रशिक्षित विशेषज्ञ पेशेवरों को तैयार करने के लिए जाना जाता है। एफडीडीआई में बैचलर डिग्री के रूप में बीडेस फुटवियर डिजाइन एवं प्रोडक्शन, रिटेल एवं फैशन मर्चेंडाइज, फैशन डिजाइन, लैदर लाइफस्टाइल एंड प्रोडक्ट डिजाइन कोर्स संचालित है। मास्टर डिग्री के रूप में एमडेस रिटेल एवं फैशन मर्चेंडाइज, फैशन डिजाइन, फुटवियर डिजाइन एवं प्रोडक्शन कोर्स संचालित है। इसके अलावा यह लघु अवधि के उद्योग विशिष्ट कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)

यह भारत में फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, प्रबंधन और वस्त्र निर्माण तकनीकी के शिक्षण एवं अनुसंधान की सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख संस्थान है। वर्ष 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने निफ्ट की एक शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापना की गई है। भारत की संसद द्वारा पारित निफ्ट अधिनियम (2006) के माध्यम से निफ्ट को अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी, आईआईएम की भांति फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा तथा शिक्षा के विकास और अनुसंधान के लिए सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे यह संस्थान अपने विद्यार्थियों को डिग्री, सर्टिफिकेट तथा पीएचडी प्रदान करती है। इस संस्थान ने उत्कृष्ट शिक्षण के माध्यम से फैशन उद्योग जगत को उत्कृष्ट डिजाइनर, प्रबंधक, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ प्रदान किए हैं। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने में भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, जो भारतीय फैशन उद्योग और वैश्विक फैशन उद्योग को क्वालिफाइड तकनीकी प्रोफेशनल्स प्रदान करने की भूमिका भी अदा करता है। निफ्ट के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की जाती है। देशभर में निफ्ट के 19 केन्द्र संचालित है। इनमें प्रमुख रूप से फैशन डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिजाइन, फैशन टैक्नोलॉजी, फैशन मैनेजमेंट, टैक्सटाइल डिजाइन, लैदर डिजाइन पाठ्यक्रमों में शिक्षा दी जाती है। निफ्ट की ओर से राजस्थान की कला, वेशभूषा और संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए विभिन्न प्रदर्शनी, फैशन शो कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आयोजित कर चुके हैं।

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी)

जोधपुर के चोखा रोड़ स्थित यह एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है, जो हथकरघा प्रौद्योगिकी और हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। यह संस्थान भारत में हथकरघा उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए काम करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान का उद्देश्य हथकरघा कारीगरों के कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना है। संस्थान के पाठ्यक्रम, अनुसंधान और विकास गतिविधियां इसे एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान बनाती हैं। आईआईएचटी जोधपुर में हैण्डलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा संचालित है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नु) जोधपुर

विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा और निरंतर व्यावसायिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय अपने द्वारा पेश किए जा रहे शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानों और निजी उद्यमों के साथ नेटवर्किंग कर रहा है। 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नु) ने समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी ज्ञान समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किया है। इसने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से उच्च-गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करके सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने का प्रयास किया है। इस तरह जोधपुर करवड़ स्थित इस संस्थान से पश्चिमी राजस्थान में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने मे अपनी अलग पहचान बनाई है।

इस प्रकार जोधपुर में राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना ने शहर की पहचान को बढ़ाया है और इसे एक प्रमुख शैक्षिक, तकनीक और चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित किया है। एम्स, एनएलयू, आईआईटी और एनआईएफटी जैसे संस्थान जोधपुर को एक नई पहचान दे रहे हैं, जो न केवल शहर के विकास में योगदान दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान भी बना रहे हैं।

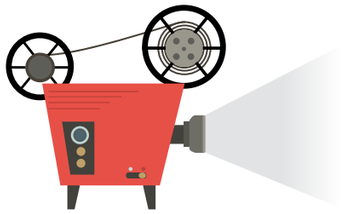

अपणायत के लिए ख्यात जोधपुर ने बॉलीवुड को दिए कई स्टार

अपने जमाने के स्टार अभिनेता रहे महिपाल

सुधांशु टाक
लेखक, समीक्षक

जोधपुर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। नाटक या साहित्य हो या फिर प्रदर्शकारी कलाएं, हर विधा के कलाकार यहां मिल जाएंगे। यही वजह है कि शहर का फिल्मों से भी पुराना नाता रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो ऐसे कई युवा और वरिष्ठ कलाकार हैं, जो अपने अभिनय से बालीवुड में धाक जमाए हुए हैं।

राजस्थान की धरती अपने क़िलों-महलों और वीरगाथाओं के लिए तो मशहूर है ही, यहां की समृद्ध संस्कृति, कला और गीत-संगीत भी हमेशा से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जिसकी स्थापना 12 मई 1459 में मारवाड़ रियासत के राव जोधा ने की थी, प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहलाता है। जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत, सुंदरता और यहां की अपणायत के लिए जोधपुर विश्व प्रसिद्ध है।

जोधपुर मारवाड़ की कला क्षेत्र में अपनी समृद्ध विरासत रही है। यहां की कला और गीत-संगीत से हिंदी सिनेमा भी अछूता नहीं रहा और बोलते सिनेमा के शुरूआती दिनों से ही जोधपुर के कलाकार हिंदी सिनेमा का अटूट हिस्सा बन बैठे। खेमचन्द प्रकाश, महिपाल, सज्जन जैसे जोधपुर के कलाकारों ने सिनेमा के क्षेत्र में भरपूर योगदान दिया।

वैसे जोधपुर देखने के साथ-साथ महसूस करने का शहर है। कला और संस्कृति के शहर जोधपुर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। नाटक या साहित्य हो या फिर प्रदर्शकारी कलाएं, हर विधा के कलाकार यहां मिल जाएंगे। यही वजह है कि शहर का फिल्मों से भी पुराना नाता रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो ऐसे कई युवा और वरिष्ठ कलाकार हैं, जो अपने अभिनय से बालीवुड में धाक जमाए हुए हैं। आइए जोधपुर के स्थापना दिवस पर जानते हैं यहां के उन कलाकारों को जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना विशिष्ट योगदान दिया।

चौथी क्लास में ही मंच पर उतर गए थे महिपाल

महिपाल भंडारी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महिपाल के नाम से जाने जाते थे। अपने जमाने में स्टार अभिनेता रहे। 24 दिसम्बर 1919 को जोधपुर के एक रईस ओसवाल जैन परिवार में पैदा हुए महिपाल भंडारी महज़ 6 साल के थे कि उनकी मां गुज़र गईं। पिता का कारोबार कोलकाता में था, इसलिए महिपाल का पालन-पोषण पुश्तैनी शहर जोधपुर में अपने दादा की देखरेख में हुआ। चित्रकला और कविता में उनके दादा की गहरी दिलचस्पी थी, जिसका असर महिपाल पर भी पड़ा। महिपाल के मुताबिक़ जब वो चौथी क्लास थे तो 'अभिमन्यु' नाम की नाटिका में पहली बार मंच पर उतरे थे, जिसमें उन्हें मोनोएक्टिंग का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। महिपाल ने क़रीब 4 दशकों के अपने करियर में कुल 130 फ़िल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 108 फ़िल्मों में वो नायक थे। ज्यादातर पौराणिक फ़िल्मों में उनकी नायिका मीना कुमारी, अनीता गुहा या निरूपा राय हुआ करती थीं तो फ़ैंटेसी फ़िल्मों में शकिला, चित्रा या श्यामा। 1960 के दशक के मध्य तक उनका करियर बुलंदियों पर रहा। लेकिन 1970 का दशक आते- आते पौराणिक और फ़ैंटेसी फ़िल्मों में दर्शकों की दिलचस्पी कम होने लगी। ऐसे में महिपाल ने अभिनय से रिटायरमेंट लेना बेहतर समझा। 'गंगासागर' (1978) और 'बद्रीनाथ धाम' (1980) उनकी आख़िरी फ़िल्मों में से थीं। रिटायरमेंट के बाद महिपाल अपना वक़्त लिखने- पढ़ने में गुज़ारते थे। पैदल चलने के शौक के कारण वे रोज़ क़रीब 8-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। यही वजह है कि वो आख़िरी समय तक स्वस्थ और सजग बने रहे। 15 मई 2005 की सुबह 9 बजे जब 86 साल की उम्र में अचानक ही महिपाल का निधन हुआ, तब वे सुबह की सैर से घर लौटे ही थे। महिपाल को गुज़रे 20 वर्ष बीत गए, लेकिन हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के दर्शकों के ज़ेहन में उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी।

धर्मेंद्र की तरह डैशिंग हीरो थे शैलेश कुमार

गुजरे जमाने के फिल्मी सितारे और जोधपुर में जन्मे शैलेष कुमार ने वर्ष 1957 से 1977 तक करीब 28 फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी, धर्मेन्द्र, बलराज साहनी जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करने के बावजूद उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली थी। शैलेष कुमार को काजल फिल्म के 'मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन' गाने के लिए पहचाना जाता है, जो मीना कुमारी और उन पर फिल्माया गया था। आज भी रक्षाबंधन पर यह गाना खूब बजता है। ऐसा कहा जाता है कि वे विफलता के बाद अपने शहर जोधपुर लौट आए थे, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से वे जोधपुर लौटे। बलराज साहनी और मीनाकुमारी के साथ "भाभी की चूडिय़ां" फिल्म से फिल्मी करिअर शुरू करने वाले शैलेश ने नामचीन कलाकारों के साथ बेगाना, नई रोशनी, ये रात फिर न आएगी, आधी रात के बाद, काजल, शहीद, गोल्डन आइज, मयखाना, सस्ता खून महंगा प्यार, पहचान, फिर कब मिलोगी, हमराही जैसी फिल्में की थी। चरस में वे आखिरी बार एक छोटी भूमिका में दिखाई दिए। 28 फिल्मों में अभिनय के बाद उन्होंने मायानगरी से नाता तोड़ लिया था।

बताते हैं वे जोधपुर में तापी बावड़ी स्थित अपने पुस्तैनी मकान हाकम साहब की हवेली में लौट आए थे। उनका मूल नाम शंभुनाथ पुरोहित था और वे तीन भाइयों और एक बहिन में मझले थे। उनका थिएटर से जुड़ाव जोधपुर के जसवन्त कॉलेज से ही था। तब उनके साथ मंच पर ओम शिवपुरी भी हुआ करते थे, लेकिन शैलेश कुमार को पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण फिल्मों में ब्रेक जल्दी मिला। कम उम्र में ही थायरॉइड के चलते उन्हें काफी सर्जरी व रेडिएशन आदि भी का सामना करना पड़ा। रेडिएशन थेरेपी के कारण कुछ लोगों ने उन्हें कैंसर की झूठी अफवाह फैला दी और उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया।

विक्रम और बेताल से चमके थे अभिनेता सज्जन

1980 के दशक के अंत में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली टेलीविजन सीरीज 'विक्रम और बेताल' में विक्रम का किरदार अरुण गोविल और बेताल का किरदार सज्जन लाल पुरोहित ने निभाया था। सीरियल में बेताल का फेमस डायलॉग 'तू बोला, तो ले मैं जा रहा हूं, मैं तो चला!' काफी लोकप्रिय था। हालांकि, बहुत से लोगों को याद नहीं होगा कि बेताल का किरदार अभिनेता सज्जनलाल पुरोहित ने निभाया था, जिन्हें सज्जन नाम से ही जाना जाता है। सज्जन का पूरा नाम सज्जन लाल पुरोहित था। उनका जन्म 15 जनवरी 1921 को जयपुर में हुआ था। सज्जन ने जोधपुर के जसवंत कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह वकील बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सज्जन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म धन्यवाद से की थी। इसके बाद वह अलग-अलग फिल्मों में काम कर एक प्रतिष्ठित साइड हीरो बने। उन्होंने नलिनी जयवंत, मधुबाला, नूतन जैसी फेमस अदाकारों संग काम किया। वह दिल से एक कवि थे और इस टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने फिल्म मीना (1944) के डायलॉग लिखे थे। सज्जन की आखिरी फिल्म राजेश खन्ना स्टारर शत्रु थी। उन्होंने 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था।

चरित्र अभिनेता ओम शिवपुरी

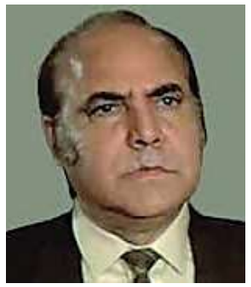

ओम शिवपुरी को आपने पुरानी फिल्मों में विलेन का रोल निभाते देखा होगा। 70 के दशक में करीब हर दूसरी फिल्म में दिखने वाले ओम शिवपुरी जोधपुर में जन्मे थे। ओम शिवपुरी ने अपने करियर की शुरुआत जयपुर में एक रेडियो स्टेशन में काम करके की थी। उस समय सुधा शिवपुरी भी वहां काम करती थीं। बाद में ओम शिवपुरी ने सुधा से शादी कर ली थी। ओम शिवपुरी ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने दो दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने 175 फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें से ज्यादातर में वो विलेन के रोल में नजर आए। ओम शिवपुरी ने सुधा शिवपुरी के साथ मिलकर 'दिशांतर' नाम से अपना एक थिएटर ग्रुप भी शुरू किया। ओम शिवपुरी ने कई प्ले खुद ही डायरेक्ट किए। इसमें 'आधे अधूरे', 'खामोश', 'अदालत जारी' और 'कोर्ट चालू है' काफी लोकप्रिय हुए थे। ओम शिवपुरी और सुधा की बेटी रितु शिवपुरी भी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रहीं। उन्होंने गोविंदा की हिट फिल्म 'आंखें' में लीड रोल निभाया था। इस फिल्म का गाना 'लाल दुपट्टे वाली' बहुत पॉपुलर हुआ था।

कपिल के शो में पलक के तौर पर छा गए थे कीकू

कीकू शारदा कॉमेडी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। कीकू शारदा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक के रूप में अपने किरदार से काफी फेमस हुए। बाद में द कपिल शर्मा शो में भी अभिनय किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकप्रिय भारतीय शृंखला F.I.R. में कांस्टेबल गुलगुले और कॉमेडी शो अकबर बीरबल में अकबर का किरदार निभाया था। मारवाड़ी परिवार से आने वाले कीकू शारदा का असली नाम राघवेन्द्र शारदा हैं। जोधपुर में वर्ष 1975 में जन्मे कीकू ने प्रियंका से शादी की और उनके दो बच्चे हैं। उनके पिता अमरनाथ शारदा मूल रूप से जोधपुर के निवासी हैं। कीकू शारदा ने अपनी शुरूआती शिक्षा जोधपुर से ही ली और उसके बाद कॉमर्स में ग्रेजुएशन के लिए वे मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी कॉमर्स की डिग्री ली। जिसके बाद उन्होंने चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडी एंड रिसर्च से एमबीए किया। वे एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं और इस समय कपिल शर्मा के शो में धमाल मचा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर हेराफेरी, एफआईआई, धमाल, जवानी जानेमन, अंग्रेजी मीडियम, रोडसाइड रोमियो, डरना मना है समेत कई फिल्मों व धारावाहिकों में अपने अभिनय का कमाल दिखाया है।

चित्रांगदा सिंह... 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी', 'देसी ब्वॉयज', 'इनकार' और 'ये साली जिंदगी' जैसी फिल्मों की अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी जोधपुर की बिटिया हैं। उनका जन्म 30 अगस्त 1976 को जोधपुर में हुआ था। लंबे फिल्मी करियर के बावजूद चित्रांगदा अभिनय में वो शोहरत हासिल नहीं कर पाईं, जिसकी वो हकदार हैं। इसके बाद फिल्म निर्माण में हाथ आजमाने वाली चित्रांगदा आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं। उनके भाई दिग्विजय सिंह गोल्फर हैं। अभिनेत्री ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज के दिनों से ही चित्रांगदा मॉडलिंग करने लगी थीं। इस दौरान उन्हें कई बड़े विज्ञापन मिले। अल्ताफ राजा की एल्बम 'तुम तो ठहरे परदेसी' से चित्रांगदा पहली बार लोगों की नजरों में आईं। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म सॉरी भाई से कदम रखा। आज भी वे बॉलीवुड में अपनी चमक बिखेर रही है।

इला अरुण... 15 मार्च 1954 को जोधपुर में जन्मी और जयपुर में पाली बढ़ी राजस्थानी लोक संगीत में अपनी पहचान बना चुकी इला अरुण की प्रसिद्धि उस समय चरम पर पहुंच गई जब 1993 में सुभाष घई की फिल्म 'खलनायक' के विवादित 'चोली के पीछे' नामक गीत से अपना जादू चलाया। मुंबई आकर इला ने कला की हर विधा में अपना नाम बनाया- फिल्म, टेलीविजन, संगीत और पार्श्व गायन और एक संगीतकार व गीतकार के रूप में भी। लगभग पचास वर्षों की अपनी रचनात्मक यात्रा के दौरान, इला इस क्षेत्र के कई जाने-माने नामों से जुड़ी रही हैं। जिनमें श्याम बेनेगल, शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, नीना गुप्ता, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लता मंगेशकर, अलका याग्निक जैसी बॉलीवुड हस्तियां शामिल हैं। हालांकि थियेटर अभी भी उनका जुनून है।

सुमित व्यास... सुमीत व्यास न सिर्फ अभिनेता है, बल्कि वे कई फिल्मों, वेब सीरीज और थिएटर नाटकों के राइटर भी हैं। उनका जन्म जोधपुर में लेखक बी.एम. व्यास और सुधा व्यास के घर हुआ। अभिनय और लेखन के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई जाने से पहले उन्होंने अपने शुरुआती साल वहीं बिताए। सुमित ने 2009 में फिल्म 'जश्न' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद उन्होंने फिल्म 'इंग्लिश विंग्लिश' में अभिनय किया। उन्होंने 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें गुड्डु की गन, पार्च्ड, औरंगजेब और कजरिया शामिल हैं। हालांकि, तीन दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें वैसी लोकप्रियता नहीं मिली, जैसी कि वेब सीरीज में उन्हें पसंद किया गया। यहां हर कोई उनकी राइटिंग और अभिनय का दिवाना बन गया। उन्होंने कई वेब सीरीजों में काम किया, जिनमें परमानेंट रूममेट्स और टीवीएफ ट्रिपलिंग शामिल हैं, जिनमें से बाद में उन्होंने राइटिंग में भी सहयोग दिया। फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में अभिनय के अलावा, व्यास भारत में थिएटर प्रस्तुतियों में भी दिखाई देते हैं।

शन्नो खुराना... शन्नो खुराना (जन्म 1927) एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायिका और संगीतकार हैं, जो रामपुर-सहसवान घराने से जुड़ी हैं। उन्होंने उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती और भजन जैसे विविध गायन शैलियों में निपुणता हासिल की। जोधपुर में जन्मी शन्नो ने 1945 में लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो से गायन की शुरुआत की, बाद में दिल्ली आकर संगीत साधना और शिक्षण में जुट गईं। उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संगीत में एम.फिल. और पीएच.डी. की और राजस्थान के लोक संगीत पर गहन शोध किया। उन्होंने देश-विदेश में भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और अनेक संगीत समारोहों में प्रस्तुति दी। वे संगीत नाटकों की रचना, निर्देशन और गायन भी कर चुकी हैं – जिनमें हीर रांझा, सोहनी महिवाल, जहांआरा, चित्रलेखा और सुंदरी जैसे नाट्य शामिल हैं। उनकी संस्था "गीतिका" ने महिलाओं के लिए संगीत महोत्सव आयोजित किए हैं। उन्हें पद्मश्री (1991), पद्म भूषण (2006) व संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (2002) से नवाजा जा चुका है।

मैं जोधपुर हूं! (आत्मव्यथा)

राजस्थान टुडे ब्यूरो

मारवाड़ की शान, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक जीवंत गाथा। मेरा अस्तित्व रामायण काल से माना जाता है। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंडोदरी का पीहर यहीं था, इसलिए लोग मुझे रावण का ससुराल भी कहते हैं। यह नाम सुनकर कुछ लोग हंसते हैं, तो कुछ तंज कसते हैं, लेकिन इतिहास अपनी जगह अटल है। समय बदला, राजे-रजवाड़े आए और गए, लेकिन मैं अडिग खड़ा रहा— बलुआ पत्थरों की नींव पर, अपनी पहचान के साथ।

मेरे नाम की गूंज

मुझे कई नामों से पुकारा जाता है— सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, जोधाणा। "सूर्य नगरी" इसलिए क्योंकि यहां सूरज की रोशनी सबसे अधिक दर्ज की गई है। मौसम विज्ञानियों ने भी कहा कि देश में सबसे ज्यादा धूप यहीं पड़ती है। लेकिन जब मई-जून की तपती गर्मी में लोग झुलसते हैं, तो कभी-कभी लगता है कि यह नाम सम्मान से ज्यादा, धूप सहने की सजा बन गया है। "ब्लू सिटी" मेरी पहचान का दूसरा नाम है। मेरे पुराने शहर की गलियां, हवेलियां और मकान नीले रंग से रंगे हैं। यह रंग कभी ब्राह्मणों की पहचान हुआ करता था। फिर धीरे-धीरे पूरे शहर ने इसे अपनाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि नीला रंग गर्मी को कम करता है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस रंग में जोधपुरवासियों का अपनापन और सादगी झलकती है।

मेरी पहचान—मेरा पत्थर

मैंने सदियों तक बलुआ पत्थरों को अपने सीने में संजोया है, और यही पत्थर मेरी पहचान बन गए। जोधपुर के प्रसिद्ध 'छीतर पत्थर' (Jodhpur Sandstone) से बनी इमारतें दुनियाभर में मशहूर हैं। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, किंग जॉर्ज मेमोरियल (मुंबई), और ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक में मेरे पत्थर लगे हैं। मेरी कारीगरी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। लेकिन आज यही पत्थर मेरी पीड़ा बन चुके हैं। दिन-रात इन्हें खोदकर निकाला जा रहा है, मानो मेरे ही शरीर को काटा जा रहा हो। मेरे आंगन में बसे गांव, जहां कभी शांति थी, आज पत्थर की खदानों के शोर में दब चुके हैं। मेरे अपने लोग मेरी छाती पर खनन मशीनें चला रहे हैं और उन घरों को तोड़ रहे हैं, जिनके लिए मेरे पत्थरों ने सदियों तक नींव बनाई थी। जब मेरे पत्थरों से दुनिया के महल सज सकते हैं, तो मेरी ही पहचान क्यों मिट रही है?

मेरी बोली की मिठास भी कम नहीं... मेरे जोधपुर वाले बोलने में इतने मीठे व सलीके वाले हैं कि यहां गुस्से में भी लोग 'सा' लगाए बिना किसी को गरिया नहीं सकते।

"पधारो सा, हटो सा, मूड खराब मत करो सा!'

अब सामने वाला गाली खाकर भी खुद को राजा-महाराजा समझने लगे तो हमारा क्या कसूर? दुनिया में किसी से "सा" जोड़कर बोलो, तो वो सोचेगा कि उसे नवाबी सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन जोधपुर में यही "सा" हथियार भी है और प्यार भी। ***अब बताइए, हमने तहजीब में भी हद कर दी या नहीं?***

मेरी चिंता और उम्मीद

आज मैं खुद से सवाल करता हूं—

जब मैं "सूर्य नगरी" हूं, तो मुझमें इतनी उदासी क्यों है?
जब मैं "ब्लू सिटी" हूं, तो मेरा रंग फीका क्यों पड़ रहा है?
जब मैं "पत्थरों का शहर" हूं, तो मेरी बुनियाद ही क्यों हिल रही है?
लेकिन फिर मैं अपने अतीत को देखता हूं—मैंने युद्ध देखे, राजे-रजवाड़ों की सत्ता देखी, ब्रिटिश शासन सहा, और फिर भी मैं खड़ा रहा।
मैं जानता हूं, मैं जोधपुर हूं—सूरज की तपिश सहना भी जानता हूं और अपनी शान बचाना भी।
बस, लोग मुझे देखने से ज्यादा समझने की कोशिश करें, तो शायद मेरी आत्मव्यथा कुछ कम हो जाए।

नगर निगम दक्षिण की ओर से शहरवासियों को

सूर्यनगरी के 567वें स्थापना दिवस

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

वनिता सेठ
महापौर
नगर निगम दक्षिण

किशनलाल लड्ढा
उप महापौर
नगर निगम दक्षिण

सिद्धार्थ पालानीचामी
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर

आपणो गौरव, आपणी विरासत।
आओ सा, एक साथ मिलनै मनावां
जोधाणा रौ स्थापना दिवस

सूर्यधरा
स्थापना महोत्सव
गौरव की धरा, शौर्य का पर्व

दिनांक: 10 11 12 मई 2025
ठिकाणो: जोधपुर री पावन धरा

आयोजक
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

मैजेस्टिक टॉकीज को बचाने के लिए महर्षि ने बेच दिया अपना सबकुछ

अयोध्या प्रसाद गौड़

वर्ष 1923 में जोधपुर का पहला सिनेमाघर सोजती गेट के पास सूरतसिंह जी की कोठी में शुरू हुआ। यहां मूक फिल्मों का प्रदर्शन होता था। थिएटर में लगभग सत्तर लोगों के ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था होती थी। ख़ास लोगों के लिए मुड्ढे भी लगाए जाते थे।

अगर किसी देश, राज्य या शहर के मिज़ाज़ का इतिहास टटोलना हो तो हमें उसके मनोरंजन स्थलों के इतिहास पर नज़र डालनी चाहिए। घर के तहखाने में धूल चढ़े बक्सों की तलाशी में जो दस्तावेज मेरे हाथ लगे वो मेरे लिए इतिहास की एक खिड़की खोलने जैसे थे। उन दस्तावेजों में छुपी थी मेरे दादा रामचंद्र महर्षि की एक फोटो और उनके सिनेमा हॉल से जुडी चौंकाने वाली जानकारी।

क्या आप जानते हैं कि जोधपुर के एक सिनेमा संचालक ने आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेज़ अधिकारियों से कागजी लड़ाई लड़ते हुए अपने थिएटर के लाइसेंस को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच डाला था?

हम बात कर रहे हैं 1938 में सोजती गेट के पास शुरू हुए मैजेस्टिक टॉकीज और उसके संचालक रामचंद्र महर्षि की। मैजेस्टिक टॉकीज के समय घटित रोचक किस्सों में एक किस्सा उन दर्शकों के बारे में था, जो ओपन स्काई थिएटर में पत्थर की बेंचों पर विराजमान हो, खुद को वीआईपी मानते। ज़मीन पर बैठने वालों से दो आने का टिकट वसूला जाता, जबकि बेंचों पर बैठने वाले चार आने यानी पच्चीस पैसे का टिकट खरीदते।

एक बार बिजली चले जाने या मशीन में रोल फंस जाने के कारण अचानक फिल्म प्रदर्शन रुका तो बेंचों पर बैठे दर्शकों में से एक ने लोअर क्लास वाले दर्शकों को सम्बोधित करते हुए कहाः "दोआने वाले, हाका करो रे!" अब, नीचे बैठने वालों में से एक के दिल पर ये बात लग गई और वहां से करारा जवाब आयाः "क्यूं रे! चारआने वालों के मुंडे फूलीजियेड़े हैं क्या?"

वर्ष 1923 में जोधपुर का पहला सिनेमाघर सोजती गेट के पास सूरतसिंह जी की कोठी में शुरू हुआ। यहां मूक फिल्मों का प्रदर्शन होता था। थिएटर में लगभग सत्तर लोगों के ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था होती थी। ख़ास लोगों के लिए मुड्ढे भी लगाए जाते थे। बिना साउंड वाली मूवी को देखने का क्या मतलब! इसलिए वहां दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की में गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू अपनी बुलंद आवाज में पर्दे पर चल रही कहानी रोचक तरीके से पढ़ कर लगभग लाइव सुनाते।

उन दिनों फिल्म प्रदर्शन के दौरान दस बार इंटरवल होते थे। फिल्म की रील या रोल गट्टों के रूप में बॉक्स में आती और एक गट्टा चल जाने के बाद नई रील लगाने के लिए मशीन को रोकना पड़ता। रामचंद्र महर्षि ने सोजती बारी के पास गिरधारी महाराज के नोहरे में मैजेस्टिक टॉकीज शुरू किया, उन्हीं दिनों कृष्णा टॉकीज, कंटालिया और एम्पायर टॉकीज भी शुरू हुए।

रामचंद्र ने सिनेमा प्रेमियों को नया और निर्बाध एक्सपीरियंस देने के लिए मैजेस्टिक टॉकीज को डबल मशीन थिएटर के रूप में विकसित करने का निर्णय किया।

ऐसा करने से रोल चेंज करने के लिए बार- बार होने वाले इंटरवेल से छुटकारा मिल गया। इंटरवल में दर्शकों के मनोरंजन के लिए लाइव डांस का आयोजन उन दिनों बड़ा आकर्षण का केंद्र था। बड़े बैनर की फिल्मों के प्रदर्शन के समय मुंबई से डांसर्स आकर कुछ दिन लाइव डांस पेश करते और उन्हें देखने टिकट खिड़की पर दर्शकों का हुजूम टूट पड़ता। मैजेस्टिक थिएटर ने बागवान, देशभक्त और कई हिट फिल्मों से अपने सफर को आगे बढ़ाया।

महर्षि के सपने और सफर पर उस समय ब्रेक लग गया, जब दस साल संचालन के बाद 1948 में अंग्रेज़ अधिकारी ने थिएटर का लाइसेंस नवीनीकरण करने से मना कर दिया। डबल मशीन लगाने और उनके रखरखाव में अपना पैसा लगा चुके महर्षि ने राज परिवार को पत्र लिख कर अपनी व्यथा सुनाई और लाइसेंस रीन्यू करने के बदले सात हज़ार रुपए दान की पेशकश बापू मेमोरियल बनाने के लिए की। पुराने दस्तावेज उस दौर में रियासत की तरफ से जारी होने वाले लाइसेंस प्रक्रिया को भी रोचक तरीके से उजागर करते हैं।

थाली में तहज़ीबः मारवाड़ का स्वाद, सदियों की साधना

जायकों की जमीन जोधपुर

जोधपुर सिर्फ सूर्यनगरी नहीं, स्वादनगरी भी है - जहां मसालों की भाप में इतिहास पकता है और हर रसोई एक प्रयोगशाला होती है। यह वह धरती है जहां स्वाद केवल जीभ का सुख नहीं, एक सांस्कृतिक संवाद है। इस स्थापना दिवस पर आइए, जोधपुर की थाली में परोसे उन चटपटे, तीखे और नवाचार से लबरेज़ व्यंजनों की कहानी सुनें, जो स्वाद और इतिहास दोनों को सहेजते हैं।

मधु मेहता
लेखिका

मारवाड़ की भूमि पर जब सूरज की तपिश रेत से टकराती है, तो वहां के लोग भोजन में छांव ढूंढ लेते हैं— स्वाद की, सादगी की और संस्कारों की। भोजन यहां पेट भरने का मात्र माध्यम नहीं, यह एक सांस्कृतिक आयोजन होता है, जिसमें हर निवाला केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है।

मारवाड़ के भोजन की परम्परा केवल स्वाद तक सीमित नहीं है; यह उस संतुलन की खोज है, जिसमें ऋतुओं के स्वभाव, शरीर की प्रकृति और धर्मशास्त्रों की मर्यादा सबका ध्यान रखा गया है। लगभग 108 वर्ष पूर्व 'मारवाड़ व ओसवाल' पत्रिका में प्रकाशित एक ऐतिहासिक आलेख में यह स्पष्ट झलकता है कि मारवाड़ी आहार-परम्परा शुद्ध वैदिक चिंतन और आयुर्वेदिक संतुलन की देन है। इस आलेख में उल्लेख मिलता है कि कैसे अलग-अलग ऋतुओं में विशेष प्रकार का भोजन करने की परम्परा रही है। जैसे गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाले हल्के मिष्ठान्न — कलाकंद और कीटी (फीका मावा)— को प्राथमिकता दी जाती थी। बरसात के मौसम में खजूर और मालपुए जैसे पोषक और रुचिकर व्यंजन बनाए जाते, वहीं शरद ऋतु में कचोरी जैसी गरिष्ठ चीजें खाई जातीं। सर्दियों की ठिठुरन में जलेबी और शीरा जैसे ऊर्जावान व्यंजन शरीर को ऊष्णता प्रदान करते थे।

मारवाड़ी रसोई की शाकाहारी कारीगरी में भी गज़ब की विविधता और गहराई है। 'चक्की' नामक एक अद्वितीय व्यंजन, जो गेहूं के आटे से तैयार होता है, अपने स्वाद में इतना समृद्ध होता है कि मांसाहारी व्यंजन भी उसके आगे फीके लगते हैं। यह शुद्ध शाकाहारी भोजन होते हुए भी उसकी बनावट, बनावट का ढंग और स्वाद ऐसा कि स्वीडन के एक खाद्य विशेषज्ञ ने भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। इसके साथ बनने वाला 'सलेवाड़ा' नामक व्यंजन, स्वाद और पौष्टिकता में किसी भी आधुनिक बिस्कुट या स्नैक को पीछे छोड़ देता है।

मारवाड़ के भोजन में केवल व्यंजन ही नहीं, भोजन करने का अनुशासन भी विशिष्ट होता है। भोजन के क्रम को भी विशिष्ट और वैदिक परम्परा के अनुरूप रखा जाता है— पहले मीठा, फिर रोटी और सब्ज़ी, उसके बाद खिचड़ी और नमकीन, फिर कांजी और चटनी, और अंत में पापड़। यह क्रम केवल स्वाद की दृष्टि से नहीं, बल्कि पाचन-तंत्र की गति और शरीर की आवश्यकता के अनुरूप रचा गया है। यह बताता है कि भोजन का हर चरण, एक संतुलित प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें स्वाद, स्वास्थ्य और संतुलन तीनों साथ चलते हैं।

- मारवाड़ी भोजन को लेकर प्रचलित एक आम भ्रांति है कि यह अधिक तीखा और मसालेदार होता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। आलेख बताता है कि मारवाड़ी लोग मिर्च का प्रयोग घी के साथ करते हैं, जिससे उसका तीखापन संतुलित हो जाता है और वह पाचक, कृमिनाशक और रुचिकर बन जाती है। मसालों का प्रयोग यहां केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनके औषधीय गुणों के कारण किया जाता है। हल्दी, धनिया, मिर्च — ये सभी तत्व पित्तनाशक और रोगनिवारक होते हैं। जहां विश्व के अन्य हिस्सों में मसाले केवल स्वाद का माध्यम होते हैं, वहीं मारवाड़ में ये शरीर के संतुलन का हिस्सा हैं।

- भोजन की परम्परा में शुद्धता और गरिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहां भोजन पत्तल या थाली में नहीं फेंका जाता, बल्कि क्रमबद्ध, स्नेह और सम्मान से परोसा जाता है। भोजन करने वाला व्यक्ति पाटे पर बैठता है, और हर व्यंजन को उचित क्रम और मर्यादा में परोसा जाता है। ऐसा नहीं होता कि मिठाई और नमकीन, कचोरी और पापड़ एक साथ रख दिए जाएं, जिससे भोजनकर्ता भ्रमित हो जाए। यहां की थाली में संगीत का एक राग बसता है — मिठाई उसका आलाप है, रोटी उसका स्थायी, खिचड़ी और कांजी उसकी अंतरा, और पापड़ उसका मृदंग।

चक्की की सब्ज़ी

जब महाराजा उम्मेद सिंह के दरबार में भोज की घण्टी बजी, तब रसोइयों के सामने एक चुनौती थी— मांस के बिना भी दावत में धूम मचानी थी। और वहीं जन्म हुआ चक्की की सब्ज़ी का। गेहूं के आटे को मसलकर, उबालकर और मसालों में पकाकर एक ऐसी डिश बनाई गई जो शाकाहार का शाही उत्तर बन गई। यह कोई साधारण सब्ज़ी नहीं, बल्कि शाकाहारी नवाचार की तलवार थी— बिना खून बहाए स्वाद की जंग जीतने वाली। चांदी की छड़ पर लिपटी चक्की, तीखी तरी में नहाकर जब थालियों में उतरी, तो इतिहास ने लिखा— यह जोधपुर है, यहां भोजन भी आत्मा से रचा जाता है।

गुलाब जामुन की सब्ज़ी

रसोई की गलतियों में कभी-कभी चमत्कार भी छिपे होते हैं। गुलाब जामुन की सब्ज़ी इसका जीता-जागता उदाहरण है। एक दिन जब मिठाई मसालों में गिर पड़ी, तो लगा सब बर्बाद हो गया... लेकिन जोधपुरी रसोइयों ने उसमें संभावना देखी— और जन्म हुआ इस अद्भुत डिश का।

यह कोई मज़ाक नहीं, बल्कि राजस्थान की रसोई की रचनात्मकता का प्रतीक है, जहां मिठाई भी मसालेदार बन जाती है। आज गुलाब जामुन की सब्ज़ी हर उत्सव में यह कहती है— "जोधपुर वो जगह है, जहां परम्परा में प्रयोग की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।"

जोधपुरी कबुली

अगर स्वाद को विरासत मानें, तो जोधपुरी कबुली उसकी सुनहरी मुहर है। मुगल प्रभाव, अफगानी खुशबू और मारवाड़ की आत्मा जब बासमती चावल में समाती है, तो पैदा होती है एक दास्तान— मिठास, गरम मसालों और सूखे मेवों की गाथा। यह केवल पुलाव नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का स्नेहिल आलिंगन है— जहां हर चम्मच में रेगिस्तान की तपन और इतिहास की ठंडक मिलती है। यह धीमी आंच पर पका हुआ संवाद है— एक सूफियाना सुर, जिसमें जोधपुर का दिल धड़कता है।

मिर्ची बड़ा

मिर्ची बड़े को अगर महज़ नाश्ता समझा जाए, तो जैसे सूर्यनगरी को रेत का शहर कह दिया जाए। यह एक चटपटा तख़्तनशीन है जो सड़क किनारे ठेले से लेकर राजसी भोज तक सब पर राज करता है। किसी गृहिणी की रसोई से निकली यह क्रांति, जो आज हर चाय के प्याले के संग अमर हो चुकी है। मिर्च, आलू, बेसन और तेज़ कड़ाही— इन चार शब्दों में जोधपुरी आत्मा की परतें सजी हैं। यह व्यंजन इतिहास में आमजन के स्वाद की स्वतंत्रता की घोषणा था।

प्याज की कचौरी

अगर जोधपुर की सुबह को स्वाद का चेहरा देना हो, तो वह निस्संदेह प्याज कचौरी होगी— खस्ता परतों में लिपटी तीखी कविता। यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि धूप की पहली किरण पर सवार एक लोकगीत है। सूखे, खारे रेगिस्तान में जहां भंडारण और टिकाऊपन ज़रूरी था, वहीं कचौरी ने आकार लिया— प्याज, आलू और मसालों की संगति से बना यह व्यंजन स्वाद के साथ बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक बना। हर परत में इतिहास है, हर बाइट में संस्कृति— और यही तो जोधपुर है, जहां खाना भी किस्सा बन जाता है।

सुनहरा कल, डगर आसान नहीं

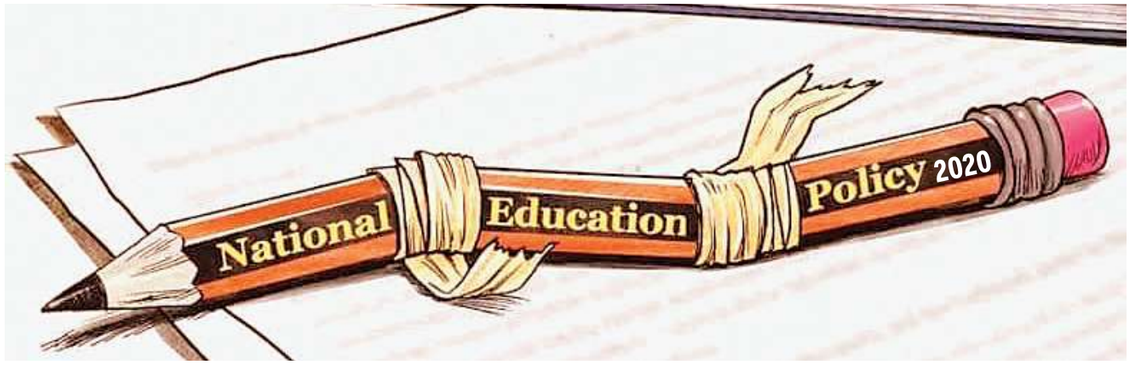

डॉ. श्यामसिंह राजपुरोहित
सेवानिवृत्त अधिकारी,
भारतीय प्रशासनिक सेवा

नियति ने भारतीय ज्ञान परम्परा से परिवेष्टित शिक्षा पद्धति को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया और उसके पुनरुत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर लम्बे विचार- विमर्श के उपरांत वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किया गया।

देश की शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने व शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से करीब पांच साल पहले राष्ट्रीय नीति- 2020 के प्रारूप को जारी कर दिया गया। इससे देश का भविष्य उजला व सुनहरा जरूर नजर आने लगा है, लेकिन पुरानी शैक्षिक व्यवस्था को बदलने व नई शिक्षा नीति के पूरी तरह क्रियान्वयन के लिए होने वाली विभिन्न तरह की वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को देखते हुए ये डगर आसान नहीं लग रही। इसके लिए सरकार, प्रशासन व आमजन की सहभागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी इस राह को आसान बनाया जा सकेगा।

यहां ये जानना जरूरी है कि प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परम्परा में शिक्षार्थी को शिक्षा की विभिन्न विधाओं में पारंगत करने की व्यवस्था विद्यमान थी, जो शताब्दियों तक बरकरार रही। इस अति समृद्ध व विपुल संस्कृति से परिपूर्ण शिक्षा पद्धति का कालांतर में अत्यधिक ह्रास प्रारंभ हो गया। पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के पुरावैभव, सभ्यता और संस्कृति के प्रतिकों के साथ-साथ भारतीय शिक्षण संस्थानों को भी तहस नहस कर दिया। रही सही कसर बाद में अंग्रेजों ने पूरी कर दी। उन्होंने भी गुरुकुल पद्धति से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपने शासन की सेवा के योग्य नौकर तैयार करना था। यह व्यवस्था रोजगार उत्पन्न करने वाली न होकर अंग्रेजी मानसिकता वाले नौकरीपेशा समूह को विकसित करने का जरिया बन कर रह गई।

अफसोसजनक तथ्य यह भी है कि सन 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया और उक्त मैकोलियन शिक्षा प्रणाली ही निरंतर जारी रही। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की ओर लौटने की तरफ कोई प्रतिबद्धता दिखाई ही नहीं गई। स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीतियों में कई परिवर्तन यद्यपि किए गए, तथापि भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना और शिक्षण व्यवस्था की सर्वांगीण विकासोन्मुखी पद्धति विकसित करने की तरफ सोचा तक नहीं गया। लेकिन कहते हैं नियति समय- समय पर करवट बदलती है। नियति ने भारतीय ज्ञान परम्परा से परिवेष्टित शिक्षा पद्धति को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया और उसके पुनरुत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर लम्बे विचार-विमर्श के उपरांत वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप जारी किया गया।

इस प्रारूप में यह स्पष्ट किया गया था कि नई शिक्षा नीति- 2020 भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसे 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया। यह नई शिक्षा नीति इससे पूर्व में लागू 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदल कर नए प्रारूप में लागू की गई थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा क्षेत्र में नैसर्गिक बदलाव लाना था।

क्या खास है नई शिक्षा नीति में

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न आयाम निर्धारित किए गए। इसमें पुराने (पिछले) अकादमिक ढांचे को परिवर्तित किया गया है। जहां पिछले ढांचे में 10+2 (आयुवर्ग 6-16+ 16-18) की व्यवस्था थी, वहीं नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था 5+3+3+4 की गई है।

5- 3 वर्ष से 8 वर्ष तक (स्कूल पूर्व शिक्षा तथा आंगनबाड़ी/बालवाटिका + कक्षा 1 एवं 2)

+3-- कक्षा 3 से 5 (आयु 8 से 11)

+3-- कक्षा 6 से 8 (आयु 11 से 14)

तथा

+4 कक्षा 9 से 12 (आयु 14 से 18)।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति में अकादमिक ढांचा 5+3+3+4 का रहेगा।

बुनियादी शिक्षा (fundamental) में बदलाव

नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा को एक नवीन रूप देने के लिए काफी सोच विचार किया गया। यह तय किया गया है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बुनियादी स्तर पर शिक्षा में बड़ा बदलाव किया जाए और इसमें तीन वर्ष की स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों के लिए आनन्ददायक और आल्हादकारी शिक्षण व्यवस्था हो। इसके उपरांत 6 से 8 वर्ष तक कक्षा एक और दो की शिक्षा व्यवस्था को शामिल किया गया है। सबसे अहम बदलाव जो इस स्तर की शिक्षा में किया जाना था, उसके लिए यह निर्धारित किया गया था कि इस बुनियादी शिक्षा अर्थात कक्षा 2 तक की शिक्षा एवं इसके आगे कक्षा तीन से पांच तक (आयु वर्ग 8-11) की शिक्षा का माध्यम अनिवार्यतः मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा ही होगी। इससे बच्चों को अपनी स्वयं की भाषा में सहज रूप से मस्तिष्क पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले सीखने का अवसर सुलभ होगा।

माध्यमिक शिक्षा (Middle) में सुझाए बदलाव

(A) **आधारभूत संरचना में बदलाव-** माध्यमिक शिक्षा को कक्षा 9 से 12 तक के 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें 5 + 3 + 3 + 4 संरचना का हिस्सा बनाया गया है। इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है।

(B) परीक्षा प्रणाली में बदलाव - परीक्षा को हर शैक्षणिक वर्ष में आयोजित न करते हुए स्कूली छात्र केवल तीन परीक्षाएं 2, 5 और 8 में ही भाग लेंगे। कक्षा 10 और 12 के लिए पहले की तरह ही बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेगी, लेकिन इनको फिर से डिजाइन किया जाएगा।

(C) **मूल्यांकन प्रणाली -** परीक्षा में मूल्यांकन केवल परख द्वारा ही किए जाएंगे। इसके अंतर्गत समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और अर्जित ज्ञान के विश्लेषण की पद्धति अपनाई जाएगी।

(D) **कौशल विकास** – कक्षा 6 से ही छात्रों को कोडिंग तथा उसी के समान अन्य स्किल भी सिखाई जाएगी। इससे छात्र अपने स्तर पर ही रोजगार परक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे।

उच्च शिक्षा

बुनियादी व माध्यमिक शिक्षा की तरह ही उच्च शिक्षा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण और सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा को लेकर नई शिक्षा नीति में बनाए गए नियम कुछ इस प्रकार हैं-

(A) **बहु प्रवेश और बहु निर्गम -** नए नियमों के अनुसार अब छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार प्रवेश और निकास का विकल्प मिलेगा। यदि कोई छात्र एक साल बाद कोर्स छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट, यदि कोई छात्र 2 साल बाद कोर्स छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा और 4 साल बाद कोर्स पूर्ण करता है तो उसे डिग्री दी जाएगी।

(B) **शिक्षण संस्थाओं का एकीकरण -** सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एकल नियामक एवं नियंत्रक प्राधिकरण के अंतर्गत लाया जाएगा। निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थानों की फीस को नियंत्रित किया जाकर सम्यक रूप से शुल्क सरंचना तय की जाएगी। समान कक्षाओं के लिए समान पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा और कहीं से भी प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्र कहीं से भी द्वितीय वर्ष का अध्ययन कर सकेगा।

(C) **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग -** उच्च शिक्षा को छात्रों के लिए नियमित और नियंत्रित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिकता और कौशल आधारित शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। इसके तहत छात्रों को इंटर्नशिप और इंडस्ट्रीज से जुड़े प्रोजेक्ट करने के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास करना है। समानता और समावेशिता के तहत सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, विशेष रूप से वंचित और आश्रय पर निर्भर रहने वाले समूह के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना प्राथमिक उद्देश्य है। इस नीति की प्राथमिकता शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। इसके लिए मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देना भी सम्मिलित है। विशेषकर कक्षा पांच तक की शिक्षा का सार्वभौमीकरण करते हुए वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में सौ फीसदी सकल नामांकन अनुपात सुनिश्चित करना है।

शिक्षा में नवाचार

शिक्षा में नवीनतम तकनीकी और नव आविष्कृत पद्धतियों का समावेश कर उसकी वहनीयता बढ़ाते हुए शिक्षा को सभी के लिए सुग्राह्य और सुलभ बनाना तथा शिक्षकों और छात्रों सभी के लिए पारदर्शिता लाना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय है। प्रत्येक स्तर पर सभी के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता है। यही नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा को भी बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है और इसके उद्देश्यों में छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना और उनको आधुनिक तकनीक से लैस रखना भी है।

तकनीकी शिक्षा को लेकर नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य -

(A) डिजिटल शिक्षा का विस्तार - छात्रों को ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक अवसर मिलेंगे। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से डिजिटल संसाधनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा।

(B) तकनीकी कौशल विकास - छात्रों को विभिन्न तकनीकी कौशल जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स और डाटा साइंस में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर उनको तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है।

(C) नवाचार और शोध - शोध और नवाचार के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देगा।

(D) शिक्षकों का विकास - शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना है, ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकें।

शिक्षकों के विकास के लिए नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य

1. **शैक्षणिक योग्यता-** 2030 तक शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय बीएड न्यूनतम आवश्यकता होगी
2. **शोध और नवाचार-** शिक्षकों को शोध और नवाचार के लिए पृथक से प्रोत्साहित किया जाएगा।
3. **तकनीकी साक्षरता-** शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी साधनों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें।
4. **प्रोत्साहन और पुरस्कार -** उत्कृष्ट शिक्षक को प्रोत्साहन और पुरस्कार दिए जाएंगे।

चुनौतियां भी कम नहीं

नई शिक्षा नीति को लागू करने की राह में कई समस्याएं और चुनौतियां भी हैं।

- **बुनियादी ढांचे की कमी -** कई स्कूलों में अभी भी पर्याप्त पुस्तकें प्रयोगशालाएं और शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है।
- **पाठ्यक्रम -** पुराने पाठ्यक्रम को नए पाठ्यक्रम से बदलने में बहुत अधिक समय लगने की संभावना है।
- **राज्यों की सहमति -** इस नीति को लागू करने में बहुत से राज्य न केवल उहापोह की स्थिति में हैं, बल्कि कतिपय राज्यों ने तो इस बाबत नकारात्मक मंतव्य भी स्पष्ट कर दिया है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का इस बाबत दिया गया बयान इसी तथ्य की पुष्टि करता है।

शिक्षकों की कमी

नई शिक्षा नीति की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि यहां शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। कई विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त है और कई विद्यालय में तो न्यूनतम आवश्यक शिक्षक ही नहीं है। नीति में कई सुधार और नई शिक्षण विधियां अपनाने के लिए पर्याप्त और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी, लेकिन शिक्षकों की कमी बहुत बड़ी समस्या है। नई विधियों और नई तकनीक को समझने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता रहेगी, जो सभी शिक्षकों के लिए वर्तमान में उपलब्ध ही नहीं है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में तो हालात और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होंगे।

वित्तीय बाधाएं

नई शिक्षा नीति को समग्र रूप से लागू करने की दृष्टि से अच्छी गुणवत्ता वाले नए स्कूल व कॉलेज खोलने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों की आवश्यकता रहेगी। कमजोर वित्तीय संसाधनों के चलते शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी मुश्किल और दुरूह कार्य है। हर स्कूल में पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं सुसज्जित करने के साथ ही वहां कंप्यूटर, इंटरनेट और उसके लिए आवश्यक अन्य डिजिटल सुविधा लागू करने के लिए भी बहुत सा धन चाहिए।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि नई शिक्षा नीति लागू तो कर दी गई है, लेकिन धरातल के स्तर पर अभी कोई विशेष प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि भारत भर के विभिन्न प्रान्तों के बड़ी संख्या में विश्विद्यालय इस ओर जिस प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर हुए हैं और जिस तरह से राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों ने आगे बढ़कर रुचि दिखाई है, उसे देखते हुए कोई संदेह नहीं रहता कि विभिन्न प्रतिकूलताओं और चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में यात्रा गाजे बाजे के साथ प्रारम्भ हो ही चुकी है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए कतिपय विलंब से ही सही, लेकिन अंततोगत्वा यह अपनी मंजिल पर पहुंच कर ही रहेगी।

इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने देश भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ सैकड़ों कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए हैं। शासन और शिक्षण संस्थानों के बीच प्रभावी सामंजस्य और तारतम्य बिठाने का कार्य किया है और इस तरह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण कार्य शासन के सहयोग से अपने हाथ में लेकर इसे एक सुखद परिणाम तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित भी है।

'भारतीय महिलाओं की प्रेरणादायक उड़ान'

धरती से अंतरिक्ष तक लहराया परचम

मधुलिका सिंह
✍ लेखिका, पत्रकार

महिलाएं भी उसी परम्परा की वाहक हैं। कभी रसोई तक सीमित मानी जाने वाली महिलाएं अब अंतरिक्ष तक अपना परचम लहरा रही हैं। कल्पना चावला ने जब अंतरिक्ष में कदम रखा था, तो वह न सिर्फ भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनीं, बल्कि करोड़ों लड़कियों के लिए वह सपना बन गईं।

भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा देवी का रूप माना गया है। चाहे वो दुर्गा की शक्ति हो या सीता की सहनशीलता, सावित्री की दृढ़ता हो या गार्गी की विद्वत्ता— पौराणिक काल से ही नारी ने समाज को दिशा देने का कार्य किया है। लेकिन इन देवी-स्वरूप नारियों की असली विशेषता ये थी कि वे साधारण परिवेश से निकलकर असाधारण कार्यों की प्रेरणा बनीं।

आज के आधुनिक भारत की महिलाएं भी उसी परम्परा की वाहक हैं। कभी रसोई तक सीमित मानी जाने वाली महिलाएं अब अंतरिक्ष तक अपना परचम लहरा रही हैं। कल्पना चावला ने जब अंतरिक्ष में कदम रखा था, तो वह न सिर्फ भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनीं, बल्कि करोड़ों लड़कियों के लिए वह सपना बन गईं, जिसे पूरा किया जा सकता है। हरियाणा के एक छोटे से शहर की बेटी ने यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती।

इसी कड़ी में हाल ही में भारत की एक और बेटी, सुनीता विलियम्स ने फिर अंतरिक्ष से लौटकर यह संदेश दिया कि भारतीय महिलाएं आज किसी भी मंच पर पीछे नहीं हैं। भले ही सुनीता का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं और उनका गौरव भी हर भारतीय के दिल में बसता है। उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लम्बा समय बिताने वाली महिला बनकर इतिहास रच दिया। इनके अलावा भी भारतीय महिलाएं मिसाल कायम कर रही हैं जैसे-

▪ नीता अंबानी

एक समय सिर्फ एक गृहिणी मानी जाने वाली नीता आज भारत की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शुमार हैं। शिक्षा, खेल और समाजसेवा के क्षेत्रों में उन्होंने अपने योगदान से नए मानदंड स्थापित किए हैं।

▪ कमला हैरिस

कमला की मां भारतीय थीं, आज अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का अद्भुत उदाहरण पेश किया है।

▪ गीता गोपीनाथ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की उप प्रबंध निदेशक गीता वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा देने में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं।

▪ फाल्गुनी नायर

फाल्गुनी ने 50 की उम्र में अपनी कंपनी नायका (Nykaa) की स्थापना की और उसे एक अरब डॉलर से अधिक की वैल्यू पर पहुंचाया।

▪ अवनी चतुर्वेदी

भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी ने इतिहास रचा, जब वह मिग-21 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनीं। उनके साथ भावना कांत और मोहना सिंह ने भी फाइटर पायलट के रूप में भारतीय महिलाओं को एक नया आसमान दिया।

देश में भारतीय महिलाओं की भागीदारी

1. वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी... वर्ष 2023-24 में भारत की कुल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 41.7% तक पहुंच गई है, जो 2017-18 में 23.3% थी। यह एक सकारात्मक वृद्धि है, जो महिलाओं की बढ़ती सहभागिता को दर्शाती है।

2. नेतृत्व क्षमता भी कम नहीं... भारत में 36.5% वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं, जो 2004 में 11.7% थी। यह तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है।

3. हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं... बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी 24.5% है। एफएमसीजी सेक्टर में यह आंकड़ा 21.5% है। प्रोफेशनल सर्विसेज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 46% तक पहुंच गया है।

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाएं... भारत में STEM स्नातकों में महिलाओं की दर 42.7% है, जो कई विकसित देशों से अधिक है। हालांकि, इन क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार दर 17.35% है।

विदेशों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी

1. वैश्विक कार्यबल में भारतीय महिलाएं... वैश्विक स्तर पर, भारतीय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, और गीता गोपीनाथ IMF की उप प्रबंध निदेशक हैं।

2. नेतृत्वकारी पदों पर महिलाएं... वैश्विक स्तर पर, कंपनियों में CEO पद पर महिलाओं की भागीदारी 21.7%, COO पद पर 25.5%, CFO पद पर 44.6%, CIO पद पर 22.8%, और CTO पद पर 22% हैं।

कविता कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ करें..

दिनेश सिंदल ✍ कवि, लेखक

कोई बड़ा रचनाकार जो तकनीकी योग्य है, वह कविता की परिभाषा कर सकता है। काव्य सिद्धांतों को जानता है। पाश्चात्य और भारतीय काव्य सिद्धांतों पर बड़े- बड़े लेख लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है। कविता की आलोचना पद्धति तैयार कर सकता है, लेकिन वह सामाजिक अयोग्य हो सकता है। उसके विचार बहुत ऊंचे व मानव कल्याण के हो सकते हैं।

कई बार यह देखा गया है कि बहुत से कवि अच्छी कविताएं लिखते हैं, लेकिन उनका पाठ अच्छा नहीं कर पाते। कुछ कवि पाठ तो अच्छा करते हैं, लेकिन कविता अच्छी नहीं लिख पाते। बहुत कम कवि ऐसे होते हैं, जो अच्छा लिखते भी है व उसका पाठ भी अच्छा करते हैं। कविता पढ़ने व सुनते वक्त हमारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होनी चाहिए।

कविता लिखते समय कवि भाव के जिस तल पर विचरण कर रहा होता है, कविता के पाठ के समय भी अगर वह उस तल को छू ले तो वह पाठ 'श्रेष्ठ' होगा। कवि श्रोताओं से और श्रोता कवि से जुड़ पाएंगे। श्रोताओं से जुड़ने की पहली शर्त है कवि स्वयं का उस कविता से जुड़ाव। अगर कोई कविता मस्तिष्क से लिखी गई है और कवि उसका होंठो से पाठ कर रहा है तो श्रोता उस कविता से नहीं जुड़ पाएंगे। हृदय से लिखी गई कविता हृदय से ही पढ़ी जाए तो वह श्रोता के हृदय में उतर जाती है। लेकिन विचार का आग्रह कविता को हृदय तक जाने नहीं देता। कुछ कहने की जल्दी की वजह से कवि विषय के भीतर नहीं उतर पाता। वह जीवनानुभव को काव्यानुभव बनाने तक का अवकाश नहीं देता। फिर खिचड़ी पकती नहीं और परोस दी जाती है।

खिचड़ी को पक जाने देने के लिए दो बातों पर विचार होना चाहिए। एक तकनीकी, यानि विषयगत योग्यता और दूसरा है सामाजिक योग्यता। मंच पर सफलतापूर्वक काव्य- पाठ करने वाले कई कवि तकनीकी अयोग्य हो सकते है, लेकिन उनके पास सामाजिक योग्यता होती है।

उन्हें जनभाषा, जनता का भाषाई मुहावरा, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समझ, उनके दैनिक क्रियाकलाप, लोक व्यवहार की समझ होती है।

दूसरी तरफ कोई बड़ा रचनाकार जो तकनीकी योग्य है, वह कविता की परिभाषा कर सकता है। काव्य सिद्धांतों को जानता है। पाश्चात्य और भारतीय काव्य सिद्धांतों पर बड़े- बड़े लेख लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है। कविता की आलोचना पद्धति तैयार कर सकता है, लेकिन वह सामाजिक अयोग्य हो सकता है। उसके विचार बहुत ऊंचे व मानव कल्याण के हो सकते हैं। बहुत प्रबल हो सकते हैं, लेकिन वे इतने प्रबल होते हैं कि कोई श्रोता या पाठक उसकी परवाह नहीं करता। उसके मित्र भी उसके साथ रहने में खुशी महसूस नहीं करते। उन्हें भी लगता है कि जब वह आसपास नहीं होता, तब वे ज्यादा खुश रहते हैं। उसकी उपस्थिति में वे असंयत महसूस करते हैं।

विचार के आग्रह से कमजोर हुआ कला का पक्ष

कविता कला है। कविता में जबसे विचार का आग्रह हुआ है कला का पक्ष कमजोर होता गया है। कोई भी अच्छी चीज गलत लोगों के हाथ में पड़ जाती है तो बात बनती नहीं, बिगड़ी है। विचार के आग्रह ने इसी तरह से कविता को कमतर कर दिया है। कविता में विचार इस तरह से आना चाहिए, जैसे पेड़ की छाया जमीन को बुहारे और धूल का एक कण तक न उड़े।

हमे इस पर विचार करना चाहिए कि कविता के नाम पर कहीं हम अपनी कुंठाएं तो नहीं परोस रहे? एक बार रुक कर हमें जरूर सोचना चाहिए कि हमारे निहार्थ क्या है? कविता, या कविता के बहाने और कुछ? आपकी कविता आप स्वयं को कितना सुख देती है? क्या वह आपको तभी सुख देती है जब कोई उस पर ताली बजाता है, कोई उसे छापता है, कोई उसे पुरस्कृत करता है? अगर आप ये सोचते हैं तो फिर आप उस 'कोई' के इशारों पर चलने लगेंगे। कोई और की तृप्ति, आपकी तृप्ति। इस समय आप एक वस्तु हो गए हैं, जिसका 'कोई और' उपयोग कर रहा है। अब आप आत्मवान नहीं हैं। आपकी आत्मा पुरस्कार, पद, पैसे के कूड़े करकट के नीचे दबी पड़ी है।

आपने कभी अपनी आत्मा के लिए तो गाया ही नहीं। कभी किसी एकांत में अपना गीत स्वयं को तो सुनाया ही नहीं। कभी क्या आपने अपनी कविता पर स्वयं ने ताली बजाई? अपनी कविता पर अपने स्वयं को कोई पुरस्कार दिया? अगर अपनी कविता पर खुश होकर आपने स्वयं अपने लिए ताली बजा दी होती तो भीड़ की तालियों की चाहत नहीं रहती। अपनी ही किसी बात पर रात के एकान्त में जब कोई कविता आपके भीतर उतरी, तब शाबाशी में अपनी ही पीठ थपथपा दी होती तो किसी दूसरे पुरस्कार की चाह नहीं रहती। कविता साध्य है, साधन नहीं। कविता जब कवि के भीतर उतरती है तभी कवि को उसका पुरस्कार मिल चुका होता है।

एक शब्द है अध्ययन (study), दूसरा है पाठ। हमें इनके अंतर को भी समझना चाहिए। अध्ययन का संबंधन मस्तिष्क से है। किसी ग्रन्थ का हम अध्ययन करते हैं, उसे समझते हैं या कोई अन्य हमें उसके अर्थ समझाता है। जब हमने उसको समझ लिया, तब उस समझाने वाले की आवश्यकता हमें नहीं रही। अब हम उसकी सहायता के बिना किसी अन्य को उसके अर्थ समझा सकते हैं। लेकिन पाठ का संबंधन हृदय से है। रस से है। उसे बार-बार पढ़ने से जो रसानुभूति होती है, वह पाठक का अपना आनंद है। उसे वह किसी दूसरे के साथ बांट नहीं सकता। उसका अनुभव किसी दूसरे को नहीं करा सकता। कोई अन्य भी उस रचना का पाठ करके रस ले सकता है, लेकिन ये उसका अपना रस है।

कविता और विज्ञान में फर्क है। विज्ञान में तत्वों की चर्चा होती है, कविता में अनुभूतियों की। अनुभूतियां हाथों में पकड़ी नहीं जा सकती, तराजू में तोली नहीं जा सकती। जब तक आपको अनुभव न हो, तब तक बात हवा में ही रहेगी। स्वाद मिले तो ही बात बने और स्वाद केवल बुद्धि की बात नहीं है। वह तो हृदय से ही मिलता है। अनुभव ऐसा जहां अनुभवकर्ता खो जाता हो। गीत सुनते- सुनते वह स्वयं गीत ही बन जाए। गीत को एक दुश्मन की तरह नहीं, एक प्रेमी की तरह समझाना होता है तो ही रहस्य खुलता है। उसे कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ करना पड़ता है। कंठ तो शरीर का हिस्सा है। गीत हृदय में जन्म लेता है।

> गीत का जब भी कभी अंतरण होगा
> तब बगावत कर रहा सा व्याकरण होगा
> स्वर्ण - मृग की लालसा मन में रही तो
> दोस्तों तय बात है सीता हरण होगा

ग्रहों की चाल

ज्योतिषी : विपुल दोभाल
ईमेल : vipravaani@gmail.com
मोबाइल : 9928424374

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना काफी बेहतर जाने वाला है। हालांकि कुछ भाग-दौड़ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी सिद्ध होते दिख रहे हैं। राजकीय मामलों में सफलता प्राप्त होगी। इस सब के साथ 14 तारीख के बाद भाग्य विशेष रूप से आपका साथ देता दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी भूमि, भवन या वाहन की खरीद करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय अनुकूल है। इस महीने सूर्य को जल अर्पित करना और अपने किसी गुरुजन को प्रणाम करके सम्मानित करना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृषभ

वृषभ राशि के जातक इस महीने थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंता का कारण बाहरी ना होकर अपने भीतर आवश्यकता से अधिक सोच विचार करना हो सकता है। आप इस महीने अपने मित्रों या परिचितों की मदद के लिए तत्पर रहेंगे और ऐसा करके बहुत सुकून महसूस करेंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। 18 तारीख के पश्चात अपने दफ्तर या व्यापार में थोड़ी अशांति महसूस कर सकते हैं। एलर्जी से संबंधित कोई रोग परेशान कर सकता है। भगवान शिव का पूजन और मंत्र जाप आपके लिए शुभ रहने वाला है।

मिथुन

मिथुन राशि के जातक इस माह अपने कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी प्रशंसा की जाएगी। धन लाभ होता दिखाई दे रहा है। विदेश से भी कुछ संबंध बन सकते हैं। किन्ही शुभ कार्यों में धन व्यय होगा। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है। अपनी ही वाणी के कारण आप अपने कार्य बिगाड़ सकते हैं। अतः बहुत नियंत्रित वार्तालाप करने की आवश्यकता रहेगी। शत्रु सिर उठा सकते हैं। किसी भूमि या नए मकान की खरीद का प्लान बन सकता है जो भविष्य में सफल रहेगा। इस बीच भगवान श्री गणेश की स्तुति आपको अत्यधिक लाभ दे सकती है।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना शुभ रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ क्रोध से बचें। आपके कोई भी राजकीय कार्य अगर अटके हुए हैं तो इस महीने पूरे होने की प्रबल संभावना है। भाई और बहनों के साथ स्नेह बढ़ेगा। आय होगी, किंतु व्यय भी बने रहेंगे। इस माह जो भी कार्य करें भगवान शिव का स्मरण करने के बाद करें। 18 तारीख के बाद बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचें। सूर्य को जल अर्पित करना और भगवान शिव की आराधना आपके लिए शुभ रहेगी।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने कुछ तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कोई भी दस्तावेज बिना ठीक से जांचे हस्ताक्षर न करें। इस महीने किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए घातक हो सकता है। कुटुंब में तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। किसी कीमती वस्तु के को जाने का भय है। बुजुर्ग के चरण स्पर्श के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो काफी सुरक्षित रहेंगे। प्रातः उठकर खाली पेट रहते हुए कबूतरों को दाने डालना भी आपके लिए शुभ रहेगा।

कन्या

कन्या राशि के जातकों को इस महीने पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। संयमित रहें और अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें। पत्नी के साथ भी आपसी सामंजस्य बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का प्रतिशत कम रहने वाला है, किंतु अपने पुरुषार्थ से आप अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। पेट और आंतों संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही कमर और निचले हिस्से भी रोग ग्रस्त हो सकते हैं। आपके शत्रुओं का मनोबल गिरता दिखाई दे रहा है। शनि देव की उपासना आपको शुभ फल प्रदान कर सकती है।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय मिले-जुले असर वाला है। इस माह के मध्य भाग तक आपको मान सम्मान के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। किंतु महीने का उत्तरार्ध अत्यधिक लाभदायक और शुभ फलदाई रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अवश्य थोड़ा चिंता रह सकती है। पत्नी के साथ बीच- बीच में वैचारिक मतभेद पनप सकते हैं। ननिहाल पक्ष से किसी के रोग का समाचार आ सकता है। इस महीने गुरुवार को चने की दाल और गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृश्चिक

जातकों के लिए यह महीना शुभ रहेगा। हालांकि कुछ व्यय बढ़ेंगे, किंतु वह उपयोगी कार्यों के लिए होंगे। आय के साधनों में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अगर आप किसी वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद करना चाहते हैं तो 18 तारीख से पहले कर लेना शुभ रहेगा। संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यर्थ विवाद से बचें। पिता के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। इस महीने सूर्य को जल अर्पित करना और ओम नमः शिवाय के जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना सुखों में कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बनते हुए कार्यों में बाधा महसूस हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर आप काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रु बलवती होते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें विपक्षी आप पर हावी हो सकते हैं। भाइयों के साथ विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। व्यर्थ की धन हानि भी हो सकती है। इस महीने आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। भाइयों के साथ भी विवाद की स्थिति से बचाव रखना होगा। शनि देव की आराधना आपके लिए अत्यधिक शुभ फलदाई होगी।

मकर

मकर राशि के जातकों को इस महीने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, किंतु किसी कीमती वस्तु के खो जाने का भय रहेगा। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। पत्नी के साथ छोटी- मोटी विवाद की स्थिति बन सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के योग हैं। जो लोग उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि देव की उपासना भी लाभप्रद रहेगी।

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय मिले- जुले असर वाला रहेगा। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। महीने के मध्य भाग तक थोड़े संघर्ष बने रहेंगे, किंतु उसके पश्चात सफलता प्राप्त होगी। कुटुंब में किसी विवाद की स्थिति से बचें। उनसे वार्तालाप नियंत्रित ही रखें। सर दर्द और नेत्र दोष के प्रति सतर्कता बरतें। यह समय कर्म प्रधान समय रहेगा। भाग्य का प्रतिशत कुछ कम ही दिखाई दे रहा है। गणेश जी की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय कुछ मानसिक द्वंद्व लाता दिखाई दे रहा है। परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ दबे हुए मसले वापस जोर पकड़ सकते हैं। हालांकि महीने का उत्तरार्द्ध धन लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी। कोई भी बड़े निर्णय इस माह ना लें तो अच्छा होगा। इस महीने उधार लेने और देने दोनों से ही बचें। भगवान शिव की आराधना आपके लिए शुभ फलदाई होगी।

जोधपुर के 567वें स्थापना दिवस
की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

ROYALE
PROPERTIES & RENTAL SERVICES
SELL | PURCHASE | RENT | LEASE

रियल एस्टेट सेक्टर में
20 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में...

JODHPUR, UDAIPUR, JAIPUR & MANY MORE...
Commercial Approved Properties.
Main Location in All Cities. *Available for Rent/Sale

SPACES
Vastu Shastra Interior Design Astro-numerology
Let's Live with Happiness, Mental peace and good Health.
Mob.: 95497-48189 ■ Mail: solutions@vridhivasstu.in

Other Services
Title Search Report, Trade Mark
Corporate Compliances. RERA Registration

The Internet Can Help you Discover Thousands of Properties
But... A REAL ESTATE CONSULTANT
Can Help you Discover The Right One.

find your Dream Property with us !
521-a/1-Stilt Floor, Umaid Heritage,
Defence Lab Road, Ratanada, Jodhpur
CALL & WHATSAPP PROPERTIES & RENTAL SERVICES
93148 10522, 93147 10522, 0291-2972851

bandhani
The Ethnic Store

567th Glorious Years Of Jodhpur

A Celebration of Heritage, Royalty and Colours

Jodhpur – A City Woven in Royal Dreams In 1459, Rao Jodha founded Jodhpur on the rocky hill of Bhakurcheeria, building the majestic Mehrangarh Fort. Known as the "Gateway of Thar," the city became a symbol of valor, culture, and royal pride. Now, 567 years later, Jodhpur still stands tall — a living legacy of resilience and heritage.

Bandhani – Beyond its forts and sunlit streets, Jodhpur's spirit lives on in Bandhani — the ancient tie-and-dye art representing joy, blessings, and tradition. Worn by royals and citizens alike, it remains a proud symbol of identity. This Foundation Day, we celebrate with the Rao Jodha Bandhani Collection — sarees, turbans, dupattas, and jackets handcrafted by Rajasthan's finest artisans. Each piece honors heritage and timeless style.At Bandhani – The Ethnic Store, we blend tradition with fashion, telling stories through every thread.In every dot of Bandhani lies the soul of Jodhpur.

Nai Sarak | Jaljog | Sardarpura | Ahemdabaad

www.bandhaniethnic.com

bandhani
The Ethnic Store